04 - एशियाई समाजवाद में है भारत की विदेश नीति की स्थिरता

05 - मदरसा अधिनियम की संवैधानिक वैधता बरकरार

A Daily News Magazine

भोपाल

सोमवार, 25 नवंबर, 2024

06 - स्कूल न जाने वाली बालिकाएं होती हैं ज्यादा अपराध का शिकारः एएसपी कमला जोशी

07- महिला मतदाता बदल रही चुनावी तस्वीर

भोपाल एवं इंदौर से एक साथ प्रकाशित

वर्ष -22 अंक-86 नगर संस्करण, पृष्ठ -8, मूल्य रू.- 2 (डाक पंजीयन संख्याः म.प्र./भोपाल/4-391/2018-20)

सुबह सवेरे

subahsaverenews@gmail.com

facebook.com/subahsaverenews

www.subahsavere.news

twitter.com/subahsaverenews

प्रसंगवश

महाराष्ट्र में बीजेपी की जीत का देश की राजनीति पर क्या असर होगा?

दिलनवाज़ पाशा

महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में महायुति के नाम से चुनाव लड़ रहे बीजेपी नेतृत्व के एनडीए गठबंधन ने ना सिर्फ़ स्पष्ट बहुमत हासिल किया है, बल्कि राज्य में अभी तक की सबसे बड़ी जीत में से एक दर्ज की है।

वहीं, झारखंड में कांग्रेस के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रही झारखंड मुक्ति मोर्चा पहले से अधिक सीटें हासिल कर अपनी सरकार बचाने में कामयाब रही है। इस साल मई में हुए लोकसभा चुनाव के बाद ये सबसे बड़े राज्य के चुनाव थे। ख़ासकर नज़रें महाराष्ट्र पर थीं।

जहां आम चुनाव में कांग्रेस, एनसीपी (शरद पवार गुट) और शिवसेना (उद्धव ठाकरे) गुट के महाविकास अघाड़ी गठबंधन ने बड़ी जीत हासिल कर बीजेपी गठबंधन की सत्ता में वापसी पर सवाल खड़े कर दिए थे। 23 नवंबर को आए नतीजों ने सभी को चौंका दिया है। महाराष्ट्र के नतीजों ने शरद पवार और उद्धव ठाकरे जैसे दिग्गज नेताओं के राजनीतिक भविष्य पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं।

बीजेपी प्रवक्ता सैयद जफ़र इस्लाम कहते हैं, 'हमें 200 सीटें जीतने की उम्मीद थी, लेकिन हमारा स्ट्राइक रेट इतना बेहतर होगा, ये हमने भी नहीं सोचा था। जनता ने महायुति के काम पर एक बार फिर से मुहर लगा दी है।' आम चुनावों में जब बीजेपी अपने दम पर बहुमत हासिल नहीं कर सकी थी और सरकार बनाने के लिए उसे गठबंधन सहयोगियों पर निर्भर होना पड़ा था।

तब ये कहा जाने लगा था कि दस साल से केंद्र की सत्ता पर क़ाबिज़ बीजेपी के ढलान का वक्त आ गया है। लेकिन, उसके बाद हुए राज्य चुनावों में बीजेपी ने पहले हरियाणा में पहले से अधिक सीटें जीतकर वापसी की। और अब महाराष्ट्र में अप्रत्याशित जीत हासिल कर साबित कर दिया है कि चुनाव प्रबंधन और जनता की नब्ज़ को समझने के मामले में अभी भी उसका का कोई मुक़ाबला नहीं है।

राजनीतिक विश्लेषक शरद गुप्ता कहते हैं, 'प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने आम चुनावों में लगातार तीसरी बार वापसी की थी, लेकिन कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्ष के गठबंधन ने जिस तरह से बीजेपी को अकेले बहुमत तक पहुंचने से रोका था, उसके बाद ये कयास लगाया जाने लगा था कि अब बीजेपी का ढलान शुरू हो जाएगा। अब से पहले ये देखा गया था कि जब किसी सरकार का ढलान शुरू होता था, तब वो रुकता नहीं था। लेकिन विधानसभा चुनावों में जिस तरह हरियाणा और महाराष्ट्र में बीजेपी ने असंभव से दिखने वाले नतीजे हासिल किए हैं, उससे ये स्पष्ट हो गया है कि अभी ना सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का करिश्मा बरक़रार है, बल्कि बीजेपी की भी लोकप्रियता वही है।'

'हरियाणा और महाराष्ट्र की जीत के पीछे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से बीजेपी को मिले सहयोग की भी अहम भूमिका मानी जा रही है। आगामी दिल्ली चुनावों के लिए भी आरएसएस कमर कस रही है।'

वरिष्ठ पत्रकार समर खडस कहते हैं, 'महाराष्ट्र, ख़ासकर राजधानी मुंबई देश की अर्थव्यवस्था के लिए बेहद अहम है। इस जीत से निश्चित रूप से बीजेपी पहले से अधिक ताक़तवर होगी।' वरिष्ठ पत्रकार समर खडस कहते हैं, 'ये माना जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस ही मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन बीजेपी में कई बार बिल्कुल अलग फैसले भी ले लिए जाते हैं। अगर देवेंद्र फडणवीस को सीएम नहीं बनाया जाता है, तो उन्हें बीजेपी का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। ऐसे में बीजेपी की अंदरूनी राजनीति में देवेंद्र फडणवीस मज़बूत हो जाएंगे।' जानकारों के मुताबिक देवेंद्र फडणवीस को एक तरफ जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क़रीबी माना जाता है, वहीं दूसरी तरफ अमित शाह से उनके रिश्ते बहुत बेहतर नहीं हैं। ऐसे में विश्लेषक ये मान रहे हैं कि महाराष्ट्र की ये बड़ी जीत बीजेपी की अंदरूनी राजनीति को भी प्रभावित कर सकती है।

शरद पवार और उद्धव ठाकरे की पार्टी का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा है। लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र से उद्धव ठाकरे की शिवसेना के 9 और शरद पवार की एनसीपी के 8 सांसद जीते थे। लेकिन, विधानसभा चुनाव के नतीजों ने दोनों ही नेताओं की पार्टियों को बेहद कमजोर स्थिति में ला दिया है। ऐसे में इन दलों के लिए अपने सांसदों को साथ बनाए रखने की भी चुनौती होगी। समर खडस कहते हैं, 'शरद पवार ने अपनी पार्टी के कांग्रेस में विलय के संकेत दिए थे, अब आगे ये संभावना बन सकती है।' 'अगर राजनीति आगे और कोई करवट लेती है तो उद्धव ठाकरे के लिए अपने सांसदों को साथ बनाए रखना आसान नहीं होगा।' अगले कुछ महीनों में दिल्ली में विधानसभा चुनाव होना है। साथ ही अगले साल अक्तूबर में बिहार में चुनाव होंगे।

महाराष्ट्र की हार ने इंडिया गठबंधन के लिए स्थिति को बेहद मुश्किल कर दिया है और गठबंधन के सामने सभी दलों को साथ रखने की चुनौती भी आ सकती है। दिल्ली में बीजेपी अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। यहां उसे गठबंधन सहयोगी की ज़रूरत नहीं हैं। लेकिन, विश्लेषक मान रहे हैं कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के लिए साथ आना राजनीतिक मजबूरी हो सकता है। सीएसडीएस के निदेशक संजय कुमार कहते हैं, 'अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी साथ नहीं आते हैं, तो इसका निश्चित रूप से बीजेपी को फ़ायदा मिलेगा।' हालांकि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और आप साथ मिलकर लड़े थे, लेकिन सातों सीटें हार गए। संजय कुमार कहते हैं, 'बीजेपी इन चुनावों के नतीजों के बाद आत्मविश्वास से भरी हुई है। बड़ी जीत के बावजूद संकेत साफ़ है कि बीजेपी अपने गठबंधन सहयोगियों को साथ लेकर चलना चाहती है। अगले साल बिहार में होने वाले विधानसभा चुनावों में बीजेपी के लिए गठबंधन को बनाए रखना अहम होगा।' विश्लेषक ये भी मान रहे हैं कि इन चुनाव नतीजों ने इंडिया गठबंधन की अंदरूनी कमजोरियों को एक बार फिर उजागर कर दिया है।

'शरद गुप्ता कहते हैं कि महाराष्ट्र के नतीजों के बाद ये धारणा मज़बूत हुई है कि इंडिया गठबंधन सहयोगी आपसी विवाद में उलझे रहते हैं और मज़बूत विकल्प पेश नहीं कर पाते।' वहीं, कांग्रेस को लग रहा है कि महाराष्ट्र चुनाव नतीजों का एक संकेत ये भी है कि बीजेपी में केंद्रीय नेतृत्व कमज़ोर हो रहा है और क्षेत्रीय क्षत्रप उभर रहे हैं।

विश्लेषक मानते हैं कि बीजेपी महाराष्ट्र जैसे राज्य में नियंत्रित सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने में कामयाब रही। विश्लेषक मान रहे हैं कि यदि हिंदुत्व की राजनीति आगे और भी मज़बूत हुई तो भारतीय राजनीति में मुसलमान और हाशिए पर होंगे।

(बीबीसी हिंदी में प्रकाशित लेख के संपादित अंश)

संसद का विंटर सेशन आज से, हंगामे के आसार

19 बैठकें, वक्फ समेत 16 विधेयक लिस्ट में, अडाणी बनेंगे मुख्य मुद्दा

नई दिल्ली (एजेंसी)। 18वीं लोकसभा का तीसरा सत्र (शीतकालीन सत्र) कल 25 नवंबर से शुरू होने वाला है। इससे पहले रविवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक हुई। इस दौरान 30 पार्टियों के कुल 42 नेता मौजूद थे। कांग्रेस समेत विपक्षी नेताओं ने लोकसभा में पहले दिन अडाणी मामले पर बहस की मांग की है। अमेरिका की न्यूयॉर्क फेडरल कोर्ट ने गौतम अडाणी पर सोलर एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए भारतीय अधिकारियों को लगभग 2,200 करोड़ रुपए की रिश्वत देने की पेशकश का आरोप लगाया है। राहुल गांधी ने इस मामले पर जेपीसी की मांग रखी है। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि उनकी पार्टी ने मणिपुर हिंसा, प्रदूषण, रेल दुर्घटनाओं पर भी संसद में चर्चा करने का प्रस्ताव रखा है। हालांकि संसदीय कार्यमंत्री किरण रिजिजू ने कहा- चर्चा के मुद्दों पर फैसला कार्य मंत्रणा समिति करेगी। विपक्ष सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलने दे।

वक्फ बिल पर बनी जेपीसी ने मांगा और समय

वक्फ संशोधन विधेयक पर संयुक्त समिति के 29 नवंबर को संसद में अपनी रिपोर्ट पेश करने की उम्मीद है, लेकिन यह तभी संभव है जब वह मानसून सत्र में दी गई समय सीमा का पालन करती है। हालांकि विपक्षी सदस्यों ने पैनल को अपनी रिपोर्ट देने के लिए समय बढ़ाने की मांग की है। हालांकि संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि जेपीसी का कार्यकाल बढ़ाने का प्रावधान है, लेकिन अभी तक इस पर कोई चर्चा नहीं हुई है। इस पर चर्चा कार्य मंत्रणा समिति में होनी चाहिए।

सत्र में कुल 16 बिल, 11 पर चर्चा, 5 मंजूरी के लिए पेश होंगे

संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान कुल 16 विधेयक पेश किए जाने हैं। इनमें से 11 विधेयक चर्चा के लिए रखे जाएंगे। जबकि 5 कानून बनने के लिए मंजूरी के लिए रखे जाएंगे। वन नेशन वन इलेक्शन के लिए प्रस्तावित विधेयकों का सेट अभी सूची का हिस्सा नहीं है, हालांकि कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि सरकार इसे सत्र में ला सकती है।

आज हो सकता है 'महायुति' सरकार का शपथ ग्रहण

- **मुख्यमंत्री पद पर सस्पेंस बरकरार, दो डिप्टी सीएम रहेंगे कायम**

मुंबई (एजेंसी)। महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में शानदार जीत दर्ज करने के बाद, भाजपा-नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन ने सरकार बनाने का दावा पेश करने की तैयारी कर ली है। शिवसेना (शिंदे गुट) के वरिष्ठ मंत्री दीपक केसरकर ने बताया कि शपथ ग्रहण समारोह कल यानी सोमवार को आयोजित होने की संभावना

है। शपथ से पहले मुख्यमंत्री पद को लेकर भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के बीच कड़ी टक्कर है। रिपोर्ट के मुताबिक, शपथ ग्रहण समारोह में केवल मुख्यमंत्री और उनके संभावित डिप्टी शपथ लेंगे। कैबिनेट में शामिल अन्य मंत्रियों के नामों पर अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है। इसके अलावा, सीएम पद को लेकर अंतिम फैसला गठबंधन के सहयोगियों के साथ चर्चा के बाद ही लिया जाएगा। फडणवीस ने कहा, मुख्यमंत्री को लेकर कोई विवाद नहीं होगा।

मन की बात में पीएम ने फिर किया डिजिटल अरेस्ट का जिक्र

नई दिल्ली (एजेंसी)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मन की बात रेडियो शो के 116वें एपिसोड में स्वामी विवेकानंद की 162वीं जयंती, एनसीसी दिवस, गयाना यात्रा, लाइब्रेरी जैसे मुद्दे पर बात की। पिछली बार की तरह पीएम मोदी

- **बोले-लोगों को समझाना होगा सरकार में इसका प्रावधान नहीं, यह लोगों को फंसाने की साजिश**

ने कहा- हमें बार-बार लोगों को समझाना होगा कि सरकार में डिजिटल अरेस्ट का कोई प्रावधान नहीं है। यह एक खुला झूठ और लोगों को फंसाने की साजिश है। 115वें एपिसोड में उन्होंने डिजिटल अरेस्ट जैसे फ्रॉड से बचने के लिए तीन स्टेप रुको, सोचो और एक्शन लो अपनाने की बात कही थी। पीएम ने एनसीसी डे पर कहा कि जब हम एनसीसी का नाम सुनते हैं, हमें अपने स्कूल और कॉलेज के दिन याद आ जाते हैं। मैं खुद एनसीसी कैडेट रह चुका हूं, इसलिए मैं पूरे आत्मविश्वास से कह सकता हूं कि उससे मिले अनुभव मेरे लिए अमूल्य हैं। 024 तक एनसीसी से 20 लाख से ज्यादा युवा जुड़े हैं। पहले की तुलना में, 5 हजार नए स्कूलों और कॉलेजों में एनसीसी का प्रावधान किया गया है। पहले एनसीसी में लड़कियों की संख्या सिर्फ 25 फीसदी थी। अब यह बढ़कर लगभग 40 फीसदी हो गई है, जो एक बड़ा बदलाव है। एनसीसी युवाओं में अनुशासन, नेतृत्व और सेवा की भावना विकसित करती है।

सुप्रभात

सबसे अच्छी कविता
इतनी विनम्र होगी
कि अविश्वसनीय लगेगी
इतनी प्राकृतिक होगी
कि हिंदी लगेगी

इतने दुखों में काम आएगी
कि लिखी हुई नहीं लगेगी

सबसे अच्छी कविता
सबसे बुरे दिनों में याद आएगी
उसे जो कंठ गाएगा
मीठा लगेगा

सबसे अच्छी कविता
विकल कर देगी
मुक्ति के लिए

सबसे अच्छी कविता
सबसे अच्छी बंदूक़ का
सबसे बुरा छर्रा साबित होगी

सबसे अच्छी कविता
सबसे बुरे दिनों में पहचानी जाएगी
देखते-देखते
आग में बदल जाएगी।

- विष्णु नागर

शुभमस्तु कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. यादव का उद्योगपतियों ने आभार व्यक्त किया

भोपाल में जीआईएस समिट- 2025 करने के निर्णय के लिए भोपाल और प्रदेश के उद्योगपतियों ने किया स्वागत

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि मध्यप्रदेश उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों में तेजी से आगे बढ़ रहा है। प्रदेश की अर्थव्यवस्था को उद्योग क्षेत्र के सहयोग से मजबूत बनाया जाएगा। अन्य देशों से भी मध्यप्रदेश में निवेश आएगा। ऐसी स्थिति में स्थानीय उद्योगपतियों को भी उतना ही महत्व दिया जाएगा। नई तकनीक का उपयोग कर सभी तरह के उद्योगों के विकास और अधिक से अधिक संख्या में युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने को प्राथमिकता दी जाएगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव आज राज्य शासन के फरवरी 2025 में भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट करने के निर्णय पर उनका आभार व्यक्त करने आए प्रमुख उद्योगपतियों, विभिन्न औद्योगिक संगठन एवं उद्योग क्षेत्र के प्रतिनिधियों को संबोधित कर रहे थे। इस

अवसर पर कई संस्थाओं ने जीआईएस समिट भोपाल में आयोजित करने के लिए मुख्यमंत्री डॉ. यादव को उद्योग जगत की ओर से शुभमस्तु कार्यक्रम में धन्यवाद देते हुए आभार व्यक्त किया गया। साथ ही मुख्यमंत्री डॉ. यादव को औद्योगिक निवेश के दृढ़ संकल्प एवं विकसित मध्यप्रदेश की परिकल्पना को साकार करने के लिए 24 से 30 नवम्बर तक यू.के. और जर्मनी यात्रा के लिए मंगलकामनाएं भी दी गईं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को मध्यप्रदेश में औद्योगिक निवेश के लिए यूके एवं जर्मनी की यात्रा करने पर जनप्रतिनिधियों ने शुभकामनाओं के साथ विदाई दीं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश में कई तरह के उद्योगों के विकास की संभावनाएं विद्यमान हैं। यदि बात मेडिकल टूरिज्म की करें तो प्रदेश में स्वास्थ्य और चिकित्सा सुविधाओं का निरंतर विस्तार हो रहा है। प्राकृतिक सुंदरता के कारण प्रदेश के कई स्थान पर्यटन क्षेत्र में उद्योगों की संभावनाओं को साकार कर रहे हैं। प्रदेश की राजधानी भोपाल की ही बात करें तो यहाँ राजस्थान के उदयपुर से अधिक संख्या में झीलें हैं, जो पर्यटन के विकास की दृष्टि से किसी भी राज्य के पर्यटन उद्योग से अधिक प्रगति में सहायक है।

यू.के. और जर्मनी में रहने वाले भारतीयों ने किए विचार व्यक्त

कार्यक्रम में प्रवासी भारतीय श्री विपिन विजयवर्गीय जर्मनी ने मुख्यमंत्री डॉ. यादव के जर्मनी आगमन का स्वागत किया। जर्मनी से ही श्री विवेक रूसिया एवं श्री प्रशांत सोनी ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. यादव की यह यात्रा मध्यप्रदेश की विकास यात्रा बने, ऐसी हम सभी की कामना है। यू.के. से श्री रोहित ने कहा कि फ्रेंड्स ऑफ एमपी की ओर से मुख्यमंत्री डॉ. यादव का यू.के. में स्वागत है, उनकी यह यात्रा मध्यप्रदेश में निवेश बढ़ाने में बड़ा कदम साबित होगी। कार्यक्रम में एमपीआईडीसी के प्रभारी एमडी श्री टी इलैया राजा ने कहा कि विकसित मध्यप्रदेश का स्वप्न साकार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री के सचिव श्री भरत यादव, संचालक जनसंपर्क श्री अंशुल गुप्ता सहित अन्य अधिकारी कार्यक्रम में उपस्थित थे।

दो भारतीय बने आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी

जेद्दा (एजेंसी)। विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे क्रिकेटर बन गए हैं। सऊदी अरब के जेद्दाह में चल रहे आईपीएल मेगा ऑक्शन में लखनऊ सुपर जायंट्स ने उन्हें 27 करोड़ रुपए में खरीदा। इसी ऑक्शन में आईपीएल इतिहास के दूसरे सबसे महंगे खिलाड़ी श्रेयस अय्यर बने। उन्हें पंजाब किंग्स ने 26.75 करोड़ की बोली लगाकर खरीदा। इस ऑक्शन में बिकने वाले वह पहले कप्तान हैं। पहली बार ऑक्शन में आए ऋषभ पंत ने चंद मिनटों के भीतर ही आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे प्लेयर बनने का रिकॉर्ड तोड़ दिया। स्टार विकेटकीपर पर लखनऊ सुपर जायंट्स ने 27 करोड़ की मोटी बोली लगाकर हर किसी को हक्का-बक्का कर दिया। इस तरह लखनऊ सुपर जाययंट्स ने शायद अपना नया कप्तान भी चुन लिया है। चंद मिनट पहले ही पंजाब किंग्स को श्रेयस अय्यर ने 26 करोड़ 75 लाख रुपये की मोटी बोली लगाकर अपने साथ जोड़ा था, जो आईपीएल की सबसे बड़ा बोली का रिकॉर्ड भी था। 2016 में फाइनल तक

- **पंत 27 करोड़ में लखनऊ, श्रेयस 26.75 करोड़ में पंजाब टीम में गए, चहल सबसे महंगे स्पिनर**

पहुंची अंडर-19 वर्ल्ड कप टीम के विकेटकीपर रहे ऋषभ पंत दिल्ली के लिए घरेलू क्रिकेट खेलते हैं। बड़े-बड़े शॉट लगाने की क्षमता ने उन्हें आईपीएल में हाथों-हाथ एंट्री दिला दी। दिल्ली डेयरडेविल्स (दिल्ली कैपिटल्स) ने उन्हें अपने साथ जोड़ा। 2016 से 2022 तक उन्होंने लगातार दिल्ली की ओर से दम दिखाया। ऋषभ पंत ने दिल्ली कैपिटल्स के लिए 111 मैच में 3284 रन बनाए हैं, जिसमें एक शतक और 18 अर्धशतक शामिल हैं। 128 उनका बेस्ट स्कोर रहा है, जो उन्होंने 2018 में बनाया था। वहीं 29 साल के श्रेयस अय्यर ने 2015 में आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेलते हुए डेब्यू किया था। जब से अब तक अय्यर ने आईपीएल में 116 मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 127 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए 3127 रन बनाए हैं। अय्यर का हाईएस्ट स्कोर इंडियन प्रीमियर लीग में 96 रन है। उनके बल्ले से इस बड़े टूर्नामेंट में 21 अर्धशतक देखने को मिले हैं। अपनी कप्तानी में अय्यर ने कोलकाता को जिताया था।

भोपाल का तापमान

अधिकतम 23 °c | न्यूनतम 18°c

सुबह सवेरे

भोपाल ■ सोमवार, 25 नवंबर 2024

जो अग्नि हमें गर्मी देती है , हमें नष्ट भी कर सकती है ; यह अग्नि का दोष नहीं है।

चाणक्य नीति

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बुधनी विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में श्री रमाकांत भार्गव के निर्वाचित होने पर उन्हें पुष्प गुच्छ भेंट कर बधाई दी।

उपचुनाव रिजल्ट के दूसरे दिन बाजार बंद

उपद्रव के डर से लिया निर्णय, टीआई बोले- गब्बर नहीं रहा, तो गब्बर के आदमी कहां से होंगे

श्योपुर (नप्र)। श्योपुर जिले के विजयपुर उपचुनाव के नतीजों में भाजपा के रामनिवास रावत को कांग्रेस के मुकेश मल्होत्रा ने 7 हजार से ज्यादा वोट से हरा दिया। नतीजे आने के दूसरे दिन विजयपुर के सुनवई रोड इलाके का बाजार बंद हो गया। ऐसा नहीं है कि बाजार बंद कराने के लिए कोई आया हो या किसी ने कहा हो। असल में दुकानदारों ने उपद्रव की आशंका के डर से खुद ही बाजार बंद कर लिया। नतीजे वाले दिन भी शनिवार दोपहर करीब 2 बजे से बाजार बंद है रहा।

वैसे तो सुनवई रोड इलाके में रोजाना दुकान सुबह 8:00 बजे खुल जाती हैं, लेकिन शनिवार दोपहर से लेकर रविवार सुबह 10 तक बजे तक दुकान नहीं खोली गई। बताया गया कि विजयपुर विधानसभा सीट पर जब-जब चुनाव होते हैं, तब नतीजा चाहे किसी के भी पक्ष में आए, कुछ असामाजिक तत्व उत्पात मचाने पहुंच जाते हैं। पथराव, मारपीट और तोड़फोड़ जैसी घटनाएं होती हैं। इसे देखते हुए दुकानदारों ने पहले से ही दुकान बंद करने का निर्णय लिया। इस बारे में दुकानदार विवेक जाटव का कहना है कि दूसरे लोग ने दुकान बंद की थी, इसलिए उन्होंने भी दुकान बंद की है।

विजयपुर थाना टीआई पप्पू सिंह यादव का कहना है कि परिणाम के बाद दुकान बंद हुई है, तो लोग सेलिब्रेशन करने चले गए होंगे। ऐसे में लोग सेलिब्रेशन के मूड में आ जाते हैं। कोई बात नहीं है क्योंकि, जब गब्बर ही नहीं रहा तो गब्बर के आदमी कहां रहेंगे।

संक्षिप्त समाचार

बिहार विधानसभा में बीजेपी की और बढ़ी ताकत

- 80 विधायकों के साथ बिहार विधानसभा में बन गई सबसे बड़ी पार्टी

पटना (एजेंसी)। बिहार में हुए विधानसभा उपचुनाव में एनडीए को बड़ी जीत मिली है। चारों सीटें जीतकर एनडीए ने अपनी ताकत बढ़ा ली है। इस जीत से जदयू, बीजेपी और हम के विधायकों की संख्या में इजाफा हुआ है, जबकि राजद और कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ा है। रामगढ़ और तारारी सीटों पर जीत के साथ ही बीजेपी अब 80 विधायकों के साथ सदन में सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। वहीं, बेलागंज सीट जीतकर जदयू के विधायकों की संख्या 45 हो गई है।

रूस ने यूक्रेन के कब्जे से छुड़ाई अपनी 40 फीसदी जमीन

- कुर्स्क की 1376 स्क्वेयर किमी जमीन यूक्रेन ने कब्जाई थी

कीव (एजेंसी)। यूक्रेन ने अगस्त में रूस के कुर्स्क इलाके में अचानक हमले किए थे। इस दौरान यूक्रेन ने कुर्स्क के एक बड़े इलाके पर कब्जा कर लिया था। हालांकि अब रूस

ने यूक्रेन के कब्जे में से 40 फीसदी जमीन को वापस छीन लिया है। इसकी जानकारी यूक्रेन के जनरल स्टाफ के एक अधिकारी ने दी। अधिकारी के मुताबिक यूक्रेन ने कुर्स्क प्रांत में 1376 स्क्वेयर किमी जमीन कब्जा कर लिया था।

अब देश में कोई उपचुनाव नहीं लड़ेगी बीएसपी

- खराब नतीजे के बाद मायावती का बड़ा ऐलान,ईवीएम पर फोड़ा ठीकरा

लखनऊ (एजेंसी)। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने उपचुनाव के नतीजों के बाद बड़ा फैसला किया है। उन्होंने देश में कोई भी उपचुनाव नहीं लड़ने का ऐलान करते हुए कहा कि बैलट से धांधली तो होती ही थी अब ईवीएम से भी धांधली होने लगी। इसलिये बसपा ने यह निर्णय किया है कि वह देश के किसी भी राज्य में अब कोई भी उपचुनाव नहीं लड़ेगी। यूपी की पूर्व उपमुख्यमंत्री ने कहा,यूपी में 9 सीटों पर हुए चुनाव और फिर उसके नतीजे के बाद लोगों में ईवीएम को लेकर आम चर्चा है। पहले देश में बैलेट पेपर के जरिए चुनाव जीतने के लिए सत्ता का दुरुपयोग करके फर्जी वोट डाले जाते थे। अब तो ईवीएम के जरिए भी ये कार्य किया जा रहा है।

भोपाल आलमी तब्लीगी इज्तिमा में 4 फूड जोन

टेंट, टॉयलेट, सड़कों का काम पूरा ; 28 से आएंगी जमातें

भोपाल (नप्र)। भोपाल में 29 नवंबर से 2 दिसंबर तक आलमी तब्लीगी इज्तिमा होना है। तैयारियां जोर-शोर से जारी हैं। 95 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है। टेंट, टॉयलेट, फूड जोन, सड़कों का काम तो पूरा कम्प्लीट हो चुका है, इलेक्ट्रिक वर्क 10 प्रतिशत बचा है। यह भी अगले दो दिन में पूरा कर लिया जाएगा।

इज्तिमा कमेटी के मीडिया कोऑर्डिनेटर डॉक्टर उमर हफीज ने बताया-28 नवंबर से जमातें भी आना शुरू हो जाएंगी। इस बार इज्तिमा की थीम सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त रखी गई है।

300 से ज्यादा जमातें आएंगी- इस बार 300 से ज्यादा जमाते इस इज्तिमे में आएंगी, जो 28 नवंबर तक भोपाल पहुंचेंगी। इस बार 600 एकड़ एरिया में व्यवस्थाएं की जा रही हैं। 300 एकड़ में पार्किंग, 100 एकड़ में टेंट लगाया जा रहा है। 200 एकड़ एरिया में दूसरी व्यवस्थाएं जैसे- फूड जोन, वुजू खाने, वॉशरूम बनाए गए हैं। 4 फूड जोन बनाए गए हैं। इंटरनल फूड की 28 शॉप, 21 नाश्तें और पानी के लिए भी कई शॉप्स हैं, जो करीब 80 के आसपास हैं। 300 शॉप्स होटल की हैं।

इस बार 12 लाख लोगों के आने की उम्मीद- इस बार के इज्तिमा में मेट्रो निर्माण का काम रुकावट नहीं बने, इसलिए भोपाल टॉकीज से करौंद तक के एरिया में बैरिकेडिंग कम की जाएगी। इज्तिमा के पहले दिन से लेकर तीसरे दिन तक 8 लाख लोग जमा होते हैं। आखिरी दिन दुआ में शामिल होने के लिए 4 लाख से अधिक लोग और पहुंचते हैं। इस बार 12 लाख से ज्यादा लोगों के आने की उम्मीद है।

स्थानीय रोगी कल्याण समिति के माध्यम से

अशासकीय विशेषज्ञ चिकित्सकों को अनुबंधित किये जाने के संबंध में आदेश जारी

भोपाल(नप्र)। लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा प्रदेश के शासकीय चिकित्सालयों में स्थानीय रोगी कल्याण समिति के माध्यम से अशासकीय (निजी) विशेषज्ञ चिकित्सकों को अनुबंधित किये जाने के लिये मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी और सिविल सर्जन-सह-मुख्य अस्पताल अधीक्षक तथा समस्त जिला चिकित्सालयों को आदेश जारी कर दिये हैं। आदेश अनुसार अनुबंध की अवधि एक वर्ष के लिये होगी, जिसे प्रदर्शन और पारस्परिक सहमति के आधार पर नवीनीकृत किया जा सकेगा। आयुक्त लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा श्री तरुण राठी ने जिला चिकित्सालयों में विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी के कारण स्वास्थ्य सुविधाएँ तथा शल्य चिकित्सा आदि प्रभावित होने के दृष्टिगत प्रदेश के शासकीय चिकित्सालयों में जहाँ पर विशेषज्ञ चिकित्सकों के पद स्वीकृत होकर रिक्त हैं तथा उक्तानुसार चिकित्सीय सेवा प्रदायगी के लिये समुचित संसाधन उपलब्ध हैं, वहाँ रोगी कल्याण समिति के माध्यम से (बिना आउटसोर्स एजेंसी) प्रति केस के मान से भुगतान (मासिक आधार पर) प्रावधानित कर अशासकीय (निजी) विशेषज्ञ चिकित्सकों को अनुबंधित किये जाने के लिये कहा है। विशेषज्ञ चिकित्सकों को अनुबंधित किये जाने के लिये भारतीय चिकित्सा परिषद या राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त वैध चिकित्सा डिग्री और विशेषज्ञता योग्यता होनी चाहिये।

'एक जिला-एक उत्पाद' की तर्ज पर लगाई जाएगी फूड प्रोसेसिंग यूनिट : मंत्री श्री कुशवाहा

भोपाल (नप्र)। मध्यप्रदेश में 'एक जिला-एक उत्पाद' की तर्ज पर उद्यानकी फसलों की प्रोसेसिंग के लिए फूड प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना की जाएगी। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा विस्तृत कार्य-योजना तैयार की जायेगी। यह बात उद्यानिकी एवं खाद्य प्र-संस्करण मंत्री श्री नारायण सिंह कुशवाहा ने रविवार को नागपुर में आयोजित एग्रो विजन राष्ट्रीय कृषि मेले में आयोजित कार्यशाला में कही। उन्होंने कहा कि फूड प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना जिला और संभाग लेवल पर हो जाने से उत्पादक किसानों को उपज का वाजिब दाम मिल सकेगा।

मंत्री श्री कुशवाह ने कहा कि मध्यप्रदेश में 20 वर्षों में सिंचाई सुविधाओं का विस्तार किया गया है। खेती-किसानी को सस्ती दर पर बिजली की आपूर्ति की जा रही है। इसके परिणामस्वरूप प्रदेश में कृषि उत्पादन बड़ा है। किसान भाई परंपरागत खेती के स्थान पर कैश क्रॉप के प्रति आकर्षित हुए हैं, उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश सरकार का प्रयास है कि उद्यानकी फसलों का उत्पादन करने वाले किसानों को फसल का सही दाम मिल सके। इसके लिए फूड प्रोसेसिंग यूनिट और मार्केटिंग का काम प्राथमिकता के साथ किया जाएगा

मध्यप्रदेश में नागपुर की तर्ज पर होगी संतरे की खेती

उद्यानिकी एवं खाद्य प्र-संस्करण मंत्री श्री कुशवाहा ने नागपुर में पैदा किये जा रहे हैं ऑर्गेनिक संतरे की फसल का अवलोकन किया। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश में भी संतरे का उत्पादन बड़े स्तर पर होता है। संतरे की फसल को और अधिक बेहतर बनाने के लिए प्रदेश के किसानों को नागपुर स्टडी टूर पर भेजा जाएगा, जिससे किसान भाई ऑर्गेनिक संतरे की उत्पादन प्रक्रिया को देख और समझ सकेंगे।

यूपी के संभल में भारी हिंसा, तीन लोगों की मौत

संभल (एजेंसी)। संभल की जामा मस्जिद में सर्वे के दौरान भड़की हिंसा में तीन युवकों की मौत हो गई। एसपी संभल ने इसकी पुष्टि की है। एक युवक के परिजन का दावा है कि पुलिस की गोली से मौत हुई है। इधर, दो लोगों की मौत की खबर फैलते ही शहर में फिर तनाव हो गया। सपा सांसद बर्क के इलाके में पथराव की घटना हुई है। हिंसा के बाद डीआईजी, आईजी मौके पर पहुंच चुके हैं। दरअसल, रविवार सुबह मस्जिद के सर्वे के लिए टीम पहुंची थी। इस दौरान करीब दो हजार की संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग पहुंच गए। उन्होंने सर्वे का विरोध किया। भीड़ मस्जिद के अंदर जाने पर अड़ गई। पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो कुछ लोगों ने पथराव कर दिया। इसके बाद भगदड़ जैसे हालात हो गए। अचानक पथराव शुरू हो गया, पुलिस को भागना पड़ा। बवाल इतना बढ़ गया कि पुलिस ने पहले आंसू गैस के गोले दागे फिर

कमिश्नर ने कहा-छतों से फायरिंग हुई,परिजन बोले-पुलिस की गोली से मौत

लाठीचार्ज करके भीड़ को खदेड़ा। हालात कई घंटे से बेकाबू है। कई घंटों तक गलियों में जगह-जगह पथराव होता रहा। उग्र भीड़ ने कई गाड़ियों में आग लगा दी। पथराव में एसपी समेत कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। डिप्टी कलेक्टर भी चोटिल हुए हैं। एक पुलिसवाले को भी गोली लगी है। इधर, अखिलेश यादव ने लखनऊ में दावा किया कि संभल में बीजेपी ने बवाल कराया है। ताकि चुनाव में की गई धांधली की चर्चा न हो। दरअसल, सुबह 6.30 बजे डीएम-एसपी के साथ एक टीम जामा मस्जिद का सर्वे करने पहुंची थी। टीम देखकर मुस्लिम समुदाय के लोग भड़क गए। कुछ ही देर में करीब दो हजार से ज्यादा लोग जामा मस्जिद के बाहर पहुंच गए। भीड़ मस्जिद के अंदर जाने पर अड़ गई।

कोर्ट ने सर्वे कराकर एक हफ्ते में रिपोर्ट देने को कहा था

जामा मस्जिद का 5 दिन में दूसरी बार सर्वे करने के लिए टीम पहुंची थी। इससे पहले 19 नवंबर को सर्वे हुआ था। उसी दिन यानी 19 नवंबर को हिंदू पक्ष की संभल शाही जामा मस्जिद के श्री हरिहर मंदिर होने की याचिका पर कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने मस्जिद का सर्वे करवाकर एक हफ्ते के अंदर रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए। 26 नवंबर को रिपोर्ट पेश करनी है। 29 नवंबर को इस पर सुनवाई होगी। संभल हिंसा पर मुरादाबाद के मंडलायुक्त ने कहा-सर्वे शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था।

मणिपुर हिंसा

सुरक्षाबलों की 288 कंपनियां तैनात, इंफाल घाटी में सर्चिंग

इंफाल (एजेंसी)। मणिपुर सरकार ने 7 जिलों में मोबाइल इंटरनेट सर्विस पर लगी रोक को दो दिन के लिए और बढ़ाया गया। इंफाल पश्चिम, इंफाल पूर्व, काकचिंग, बिष्णुपुर, थौबल, चुराचांदपुर और कांगपोकपी जिलों में 16 नवंबर को पहले दो दिन के लिए इंटरनेट

- सात जिलों में लगा इंटरनेट बैन दो दिन और बढ़ाया, विधायकों के घर पर हमले मामले में अब तक 34 गिरफ्तार

सर्विस बैन की गई थी। मणिपुर में हिंसा लगातार जारी है। इसी को ध्यान में रखते हुए बैन को लगातार बढ़ाया जा रहा है। गृह विभाग ने नोटिस जारी किया है। इससे पहले 19 नवंबर को सरकार ने ब्रॉडबैंड सर्विस से बैन हटाया था। जिससे स्कूल-कॉलेजों, अस्पतालों, सरकारी ऑफिसों के काम नहीं रुकें। वहीं, 16 नवंबर को विधायकों के घरों में तोड़फोड़-आगजनी के मामले में 2 और लोग गिरफ्तार किए गए। पुलिस ने अब तक 34 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक और भी लोगों की तलाश की जा रही है। इसके लिए इंफाल घाटी में सर्चिंग जारी है। 11 नवंबर को जिरिबाम में सुरक्षाबलों ने मुठभेड़ में 10 कुकी-जो उग्रवादियों को मार गिराया था।

बुरे फंसे नेतन्याहू, भविष्य पर खड़े हुए सवाल

- विदेश में गिरफ्तारी वारंट, इजरायल में चल रहा भ्रष्टाचार का मुकदमा

तेल अवीव (एजेंसी)। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू फिलहाल एक मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। उन पर घरेलू और अंतरराष्ट्रीय, दोनों स्तर पर कानूनी मामले चल रहे हैं। एक तरफ अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने गुरुवार को नेतन्याहू के खिलाफ गाजा में युद्ध अपराध के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। वहीं दूसरी ओर नेतन्याहू को इजरायल में भी भ्रष्टाचार के एक मुकदमे में गवाही देनी है। दोनों ही मामले उनके लिए मुश्किल खड़ी कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, नेतन्याहू के खिलाफ इजरायल में लंबे समय से भ्रष्टाचार का मामला चल रहा है।

तीन राज्यों में बर्फबारी 9 में छाया घना कोहरा

- एमपी-राजस्थान और छत्तीसगढ़ के 15 शहरों में तापमान लगातार दूसरे दिन 10 डिग्री से नीचे

नई दिल्ली/ भोपाल/ जयपुर (एजेंसी)। जम्मू-कश्मीर के साथ-साथ अब हिमाचल प्रदेश और लद्दाख में भी बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है। हिमाचल के कुल्लू जिले के रोहतांग पास और अटल टनल के पास रविवार को बर्फबारी हुई। वहीं, जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा, गुलमर्ग, बांदीपोरा और लद्दाख के लेह में भी रविवार को बर्फबारी हुई। तीनों राज्यों में सोमवार को भी बर्फ गिरने का अनुमान जताया गया है। मौसम विभाग ने देश के 8 राज्यों में घना कोहरा छाने का भी अनुमान जताया है। इनमें पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश और दिल्ली शामिल है। उत्तरी राज्यों के साथ-साथ अब मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी ठंड लगातार बढ़ रही है। एमपी और राजस्थान 7-7 स्थानों और छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में तापमान लगातार दूसरे दिन 10 डिग्री से नीचे रहा। मौसम वैज्ञानिकों ने कहा कि पहाड़ों पर बर्फ पिघलने के बाद वहां से आई बर्फीली हवा के कारण मध्य प्रदेश और राजस्थान में ठंड पड़ रही है।

प्रधानमंत्री श्री मोदी के मन की बात कार्यक्रम से सदैव कुछ नया करने की मिलती है प्रेरणा : मुख्यमंत्री

● प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में भोपाल के महेश के कार्य को सराहा ● बुजुर्गों को मोबाइल से पैमेंट करना सिखा कर महेश बना रहे डिजिटल क्रांति का हिस्सा ● मन की बात कार्यक्रम में 'एक पेड़ माँ के नाम' अभियान के लिए इन्दौर की हुई प्रशंसा ● अभियान के अंतर्गत इन्दौर ने 24 घंटे में लगाए थे 12 लाख से अधिक पौधे

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में मध्यप्रदेशवासियों द्वारा सामूहिक प्रयासों से पर्यावरण-संरक्षण के लिए किए जा रहे कार्यों की सराहना की है। यह निश्चित रूप से सभी के लिए गर्व और प्रेरणा का विषय है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के 'मन की बात' कार्यक्रम से सदैव कुछ नया करने की प्रेरणा मिलती है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मुंबई प्रवास के दौरान प्रधानमंत्री श्री मोदी के 'मन की बात' कार्यक्रम के 116 वां संस्करण सुनने के बाद यह विचार व्यक्त किए।

इंदौर की रेवती हिल्स इलाके में हुए पौधरोपण का हुआ उल्लेख- रविवार 24 नवंबर को प्रधानमंत्री श्री मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान अंतर्गत इंदौर में पेड़ लगाने के बने रिकॉर्ड का उल्लेख करते हुए कहा कि मध्यप्रदेश के इंदौर में अभियान अंतर्गत 24 घंटे में 12 लाख से ज्यादा पेड़ लगाए गए। अभियान में हुई जन-सहभागिता से इंदौर की रेवती हिल्स का बंजर इलाका अब ग्रीन जोन में बदल जाएगा।

डिजिटल अरेस्ट नाम का सरकार में कोई भी प्रावधान नहीं- प्रधानमंत्री श्री मोदी ने डिजिटल क्रांति में बुजुर्गों को भागीदार बनाने के लिए युवाओं द्वारा की जा रही पहल के अंतर्गत भोपाल के महेश का उल्लेख करते हुए कहा कि उन्होंने अपने मोहल्ले के कई बुजुर्गों को मोबाइल के माध्यम से पेमेंट करना सिखाया है। इन बुजुर्गों के पास स्मार्टफोन तो था, लेकिन उसका सही उपयोग बताने वाला कोई नहीं था। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने आह्वान किया कि बुजुर्गों को डिजिटल अरेस्ट के खतरे से बचाने के लिए भी युवा आगे आएं। उन्होंने यह भी कहा कि हमें बार-बार लोगों को समझना होगा कि डिजिटल अरेस्ट नाम का सरकार में कोई भी प्रावधान नहीं है। यह सरासर झूठ है, लोगों को फसाने का एक षड्यंत्र है। यह प्रसन्नता का विषय है कि देश के युवा जागरूकता के इस काम में पूरी संवेदनशीलता से हिस्सा ले रहे हैं और दूसरों को भी प्रेरित कर रहे हैं।

पर्यावरण-संरक्षण और स्वच्छता के प्रति संवेदनशीलता जरूरी

प्रधानमंत्री श्री मोदी ने पर्यावरण संरक्षण के प्रति संवेदनशील होने के लिए प्रेरित करते हुए कहा कि बायोडायवरसिटी बनाए रखने में गौरैया (स्पेरो) पक्षी का विशेष महत्व है। इस पक्षी की वापसी के लिए विभिन्न राज्यों में अनोखे प्रयास हो रहे हैं। अपने आसपास और सभी के ऐसे प्रयास करने से गौरैया फिर से हमारे जीवन का हिस्सा बन सकती है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने सरकारी दफ्तरों में पुरानी फाइलों और स्क्रेप को हटाने के लिए चलाए गए विशेष स्वच्छता अभियान का उल्लेख भी किया तथा प्लास्टिक वेस्ट और अनुपयोगी समझीं जाने वाली चीजों को री-साईकल कर कचरे से कंचन बनाने के विचार को अमल में लाने की अपील भी की।

11-12 जनवरी को दिल्ली में होगा विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग

प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि चमन की बातज्देश के सामूहिक प्रयासों, उपलब्धियों, जन-जन के सामर्थ्य, युवा सपनों और देश के नागरिकों की आकांक्षाओं की बात है। उन्होंने युवाओं से अधिक से अधिक संख्या में एनसीसी से जुड़ने की अपील करते हुए कहा कि यह किसी भी कैरियर के लिए व्यक्तित्व निर्माण में सहायक है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने बताया कि 11-12 जनवरी को दिल्ली में विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग का आयोजन हो रहा है। इसमें गांव, ब्लॉक, जिलों, राज्यों से लगभग दो हजार युवा भाग लेंगे। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि समाज को सशक्त बनाने में पुस्तकालयों की महत्वपूर्ण भूमिका है। युवाओं को भी किताबों से दोस्ती करने के लिए पहल करना चाहिए। उन्होंने ओरल हिस्ट्री प्रोजेक्ट के संबंध में भी चर्चा की।

प्रांतीय ड्राइवर कल्याण महासंघ का गठन

भोपाल। ट्रक और बस ड्राइवरों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश के वाहन चालकों ने प्रांतीय ड्राइवर कल्याण महासंघ का गठन किया। इसकी पहली बैठक भोपाल में सहारा बायपास रोड पर स्थित एक होटल में संपन्न हुई। महासंघ के अध्यक्ष रमेश विश्वकर्मा ने बताया कि ड्राइवर का कोई संगठन नहीं

है। इसलिए उनका हर कहीं शोषण होता है मोटर मालिक भी शोषण करते हैं और सड़क पर पुलिस वाले, आरटीओ और अन्य विभाग के लोग भी आए दिन परेशान करते हैं, लेकिन उनके कल्याण के बारे में कोई नहीं सोचता है। महासंघ के माध्यम से हम नसीब ड्राइवर के बल्कि उनके परिवारों के उचित देखभाल आपात स्थितियों में उनकी हर प्रकार की मदद करने के मकसद से काम करेंगे महासंघ मध्य प्रदेश फंक्शन समिति में हाल ही में पंजीकृत हुआ है । श्री रमेश ने बताया कि शीघ्र ही महासंघ प्रदेश स्तर पर एक बड़ा सम्मेलन बुलाएगा जिसमें ड्राइवर की समस्याओं पर विस्तार पूर्वक चर्चा होगी और उनका समाधान कैसे हो उसका रास्ता निकाला जाएगा।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव से महाराष्ट्र कैडर के आईपीएस श्री शर्मा ने की सौजन्य भेंट

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से मुम्बई में महाराष्ट्र कैडर के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी श्री मनोज शर्मा (आईजी) एवं उनकी धर्मपत्नी, महाराष्ट्र पर्यटन विकास निगम की प्रबंध निदेशक श्रीमती श्रद्धा शर्मा ने सौजन्य भेंट की। मुख्यंत्री डॉ. यादव ने कहा कि श्री मनोज शर्मा की संकल्पों की सिद्धि और दृढ़ता प्रदेश और देश के सभी युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि श्री मनोज शर्मा ने विपरीत परिस्थितयों में चुनौतियों का सामना करते हुए सफलता प्राप्त कर न केवल मुरैना बल्कि पूरे मध्यप्रदेश को गौरवान्वित किया है।

उल्लेखनीय है कि मध्यप्रदेश के निवासी श्री मनोज कुमार शर्मा 2005 बैच के भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) अधिकारी हैं, जिन्हें महाराष्ट्र कैडर आवंटित हैं। वे वर्तमान में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) में पुलिस महानिरीक्षक के पद पर कार्यरत हैं। उनका जन्म चंबल संभाग के एक गांव में 3 जुलाई 1975 में हुआ था।

फॉस्टर केयर लीडिंग टू फॉस्टर एडॉप्शन विषय पर राज्य स्तरीय कार्यशाला आज

भोपाल (नप्र)। केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण द्वारा प्रति वर्ष नवम्बर माह में दत्तक ग्रहण को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय दत्तक ग्रहण जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। इसी कड़ी में 25 नवंबर को होटल पलाश में राष्ट्रीय दत्तक ग्रहण जागरूकता कार्यक्रम 'फ़ॉस्टर केयर लीडिंग टू फ़ॉस्टर एडॉप्शन' विषय पर राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। महिला बाल विकास मंत्री सुश्री निर्मला भूरिया कार्यशाला का शुभारंभ करेंगी।

उल्लेखनीय है कि यह कार्यक्रम फोस्टर केयर पर गए बालकों को फ़ॉस्टर एडॉप्शन को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है। यदि पालक माता-पिता 2 से अधिक वर्ष तक बालक का पालन पोषण कर रहे हैं, ऐसे बालकों को फ़ॉस्टर एडॉप्शन के माध्यम से दत्तक ग्रहण दिया जा सकता है। कार्यक्रम में लगभग 200 प्रतिभागी शामिल होंगे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने पूर्व मुख्यमंत्री श्रद्धेय कैलाश जोशी की पुण्य-तिथि पर किया नमन

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्रद्धेय कैलाश जोशी की पुण्य-तिथि पर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने अपने संदेश में लिखा है कि प्रदेश के विकास, समाज के उत्थान एवं जनसेवा के लिए समर्पित श्रद्धेय जोशी जी का जीवन सदैव मार्गदर्शन का स्त्रोत रहेगा।

फ्री कोचिंग के लिए टेस्ट में बैठे 628 स्टूडेंट्स

पास होने वाले 150 को मिलेगा मौका ; भोपाल में दिसंबर में शुरू होगी कोचिंग

भोपाल (नप्र)। भोपाल में यूपीएससी (संघ लोक सेवा आयोग) और एमपीपीएससी (मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग) की फ्री कोचिंग के लिए रविवार को टेस्ट हुआ। यह टेस्ट एमपीपीएससी प्रीलिम्स जैसा ही था। शासकीय हमीदिया आर्ट्स एवं कॉमर्स कॉलेज गिन्नौरी में दिसंबर से कोचिंग शुरू की जाएगी।

फ्री कोचिंग की कुल 150 सीटों के लिए 900 स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन कराया था। ये रजिस्ट्रेशन अक्टूबर में किए गए थे। हालांकि, रविवार को हुए टेस्ट में 628 स्टूडेंट्स बैठे। इस हिसाब से प्रत्येक 4 में से 1 स्टूडेंट का सिलेक्शन कोचिंग के लिए होगा। फ्री कोचिंग के लिए अक्टूबर में कुल 990 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कराया था।

1 घंटे की कोचिंग, 21 कमरों में व्यवस्था

यह कोचिंग एनजीओ 'आदर्श परिवार एवं आधुनिक नालंदा' के सहयोग से शुरू की जा रही है। एनजीओ से जुड़े राम लखन मीणा ने बताया कि, सिविल सेवा की फ्री कोचिंग के लिए 18 से 25 अक्टूबर तक रजिस्ट्रेशन किए गए थे। 990 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कराया था। इनके लिए रविवार को दोपहर 12 से 1 बजे टेस्ट हुआ। 25 प्रश्नों का यह ऑप्शनल टेस्ट था। जिसमें जनरल नॉलेज, सोशल साइंस, साइंस, हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट के प्रश्न शामिल रहे। एक सप्ताह के अंदर रिजल्ट जारी कर देंगे। ताकि, दिसंबर से कोचिंग शुरू की जा सके।

अब लालू और तेजस्वी मां पीतांबरा की शरण में

मां बगुलामुखी देवी की पूजा-अर्चना के बाद तेजस्वी बोले-2025 बिहार विस चुनाव जीतेंगे

दतिया (नप्र)। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव रविवार दोपहर दतिया पहुंचे। यहां उन्होंने पीतांबरा पीठ पहुंच कर मां बगुलामुखी देवी की विशेष पूजा-अर्चना कर देश के कल्याण और शांति की कामना की। इसके साथ ही मंदिर परिसर में विराजित वन खंडेश्वर महादेव का जल अभिषेक किया। वे 2.30 बजे विशेष विमान से दतिया एयरपोर्ट पहुंचे थे। यहां से वह सड़क मार्ग से होते हुए पीतांबरा पीठ पहुंचे। दर्शन के पश्चात वह सर्किट हाउस के लिए रवाना हुए। यहां वह यादव सामज व अन्य राजनेताओं से मुलाकात के बाद वापस एयरपोर्ट पहुंचेंगे और विशेष विमान से पटना के लिए रवाना होंगे।पीतांबरा शक्तिपीठ में बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पूजा-अर्चना की।

40 मिनट रहे मंदिर में

लालू प्रसाद यादव करीब 3 बजे पीतांबरा पीठ पहुंचे थे। यहां उनकी अगवानी यादव समाज और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने की थी। वे तेजस्वी के साथ सीधे माता के दर्शन के लिए पहुंचे। यहा गर्भ गृह के बहार करीब 10 मिनट रुक कर पीठ के पुजारियों ने विशेष पूजा अर्चना करवाई। पूर्व सीएम लालू यादव का स्वस्थ ठीक न होने से उन्हें व्हीलचेयर से मंदिर ले जाया गया और वहां अन्य देवी देवताओं के दर्शन कराए गए। इस दौरान वह पीठ प्रांगण में 40 मिनट तक रूके।

तेजस्वी बोले-मां शक्ति देना हम आगे और लोगों की सेवा कर सकें

इस अवसर पर तेजस्वी यादव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वह झारखंड में जीते हैं। महाराष्ट्र में क्यों हार गए, इसकी समीक्षा की जा रही है। बिहार में साल 2025 में होने वाले चुनाव में जीत का दावा किया। तेजस्वी ने कहा कि आज पिता के साथ माता के दरबार में पहुंचे हैं। माता का आशीर्वाद प्राप्त किया है। मां शक्ति दे कि हम आगे और लोगो की सेवा कर सकें।

उत्तरी हवाओं से ठिठुरा एमपी, 3 दिन कड़ाके की ठंड

भोपाल में 36 साल बाद सबसे कम तापमान ; इंदौर, ग्वालियर-जबलपुर में भी पारा लुढ़का

भोपाल (नप्र)। उत्तरी हवाओं की वजह से नवंबर में ही मध्यप्रदेश ठिठुर गया है। भोपाल समेत प्रदेश के कई इलाकों में जनवरी जैसी सर्दी पड़ रही है। भोपाल में पारा 8.8 डिग्री पर पहुंच गया। नवंबर में 36 साल बाद यह रात का सबसे कम तापमान है। इससे पहले 1988 में नवंबर में रात का सबसे कम तापमान 7.5 डिग्री दर्ज किया गया था। मौसम केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. वेद प्रकाश सिंह ने बताया कि उत्तर से बर्फीली हवा का सबसे ज्यादा असर भोपाल संभाग और उसके आसपास हो रहा है। वहीं, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर-उज्जैन में भी तापमान सामान्य से 5 डिग्री तक नीचे लुढ़क गया है।

मौसम विभाग की माने तो अगले 3 दिन प्रदेश में कड़ाके की ठंड रहेगी। मौसम विभाग के अनुसार, पहाड़ों पर बर्फ पिघलने के बाद वहां से आई बर्फीली हवा से ठंड बढ़ी है। अगले दो-तीन दिन और ऐसी कड़ाके ठंड से राहत के आसार नहीं है। इंदौर में शनिवार को दिन का तापमान 27.5 (-2) डिग्री सेल्सियस रहा। रात के तापमान में 2 डिग्री का इजाफा हुआ और तापमान 13.6 (0) डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। रविवार सुबह मौसम ठंडा रहा। धूप खिलने के साथ मौसम साफ है। उज्जैन में रविवार सुबह धूप निकलने के बाद भी हल्की ठंड होने से लोग गर्म कपड़ों में नजर आए। वेधशाला में शनिवार-

रविवार की रात का तापमान 12.5 डिग्री दर्ज किया गया।

पचमढ़ी सबसे ठंडा, पारा 6.6 डिग्री पर आया- प्रदेश के इकलौते हिल स्टेशन पचमढ़ी में रात में टेम्प्रेचर 6.6 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। यह प्रदेश में सबसे कम रहा। शुक्रवार-शनिवार की रात में मंडला में 7.4 डिग्री, शहडोल के कल्याणपुर में 7.6 डिग्री, अनूपपुर के अमरकंटक में 7.7 डिग्री, शाजापुर के गिरवर में 8.2 डिग्री, उमरिया में 8.9 डिग्री, राजगढ़ में 9.2 डिग्री, नौगांव में 9.5 डिग्री दर्ज किया गया।

भोपाल में 3 बार 9 डिग्री के आसपास रहा था पारा

भोपाल में 25 साल में नवंबर में पहली बार ऐसी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। इससे पहले वर्ष 2000 से लेकर 2023 तक नवंबर में सिर्फ तीन बार तापमान 9.5 डिग्री (2001) और 9 डिग्री (2013) दर्ज किया गया था। साल 2017 में पारा 9.6 डिग्री पर पहुंचा था। यानी, 25 साल के अंदर पहली बार पारा 9 डिग्री के नीचे यानी, 8.8 डिग्री पर पहुंचा है।

तो भोपाल में यह शीतलहर मान ली जाती

मौसम केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. वेद प्रकाश सिंह के मुताबिक, भोपाल में रात का तापमान 8.8ए सामान्य से 4.8ए कम रहा। सामान्य से 4.5 डिग्री या उससे कम तापमान शीतलहर मानी जाती है। भोपाल पश्चिम डिवीजन में है। यदि डिवीजन के एक और शहर में तापमान सामान्य से 4.5 डिग्री या उससे कम होता तो शीतलहर मान ली जाती।

वेस्टर्न डिस्टरबेंस (पश्चिमी विक्षोभ) एक साइक्लोनिक सकुर्लेशन के रूप में उत्तरी हिस्से में एक्टिव है। पूर्वी हिस्से में एक साइक्लोनिक सकुर्लेशन एक्टिव है। वहीं, उत्तरी हवाएं भी प्रदेश में आ रही है। इस कारण तेज ठंड है।

अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस की पूर्व संध्या पर ब्रह्माकुमारी सुख शांति भवन में कार्यक्रम आयोजित

महिलाएं आज भी वित्तीय और मनोवैज्ञानिक हिंसा की शिकार

ध्यान और आत्मिक सशक्तिकरण द्वारा पा सकते हैं महिला हिंसा पर विजय

भोपाल। अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस के अवसर पर प्रजापिता ब्रह्माकुमारी सुख शांति भवन मेडिटेशन रिट्रीट सेंटर नीलबड़ भोपाल में अंतरराष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस की पूर्व संध्या पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिसमें शहर की विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत महिला अधिकारी तथा ग्रहणी महिलाएं भी शामिल हुई जो राजयोग का अभ्यास नियमित रूप से कर रही हैं। उन्होंने अपने सफलता के सूत्र सभी से साझा किए।

कार्यक्रम में विशेष रूप से डॉक्टर दीप्ति दाते (सीनियर गाइनेकोलॉजिस्ट), नंदिता साहू (ब्रांच मैनेजर बैंक ऑफ़ बड़ौदा), डॉक्टर श्रेष्ठा धीमान (समाज सेविका) एवं आर्किटेक्ट राजयोगिनी बीके दुर्गा दीदी जी उपस्थित थे।

महिलाओं के खिलाफ हिंसा का मतलब सिर्फ शारीरिक हिंसा से नहीं है। वल्कि यह बहुत ही व्यापक विषय है और इसमें भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक और वित्तीय दुर्व्यवहार शामिल हैं। राष्ट्रीय योजनायें महिलाओं के खिलाफ़ हिंसा के दो मुख्य प्रकारों को परिलक्षित करती है - घरेलू और पारिवारिक हिंसा। यह कहना था डॉक्टर श्रेष्ठा धीमान का, जिन्होंने अपने घर पर आने वाली एक महिला सहयोगी का उदाहरण देते हुए कहा कि शराब के नशे में उस महिला का पति उसे किस प्रकार प्रताड़ित करता है परंतु वह सब कुछ सहते हुए अपने घर की आर्थिक स्थिति संभालने के लिए घर से निकलने पर मजबूर है।

इसी प्रकार ब्रांच मैनेजर श्रीमती नंदिता साहू जी ने बताया कि कई बार ऐसे कस्टमर का उन्हें सामना करना पड़ता है जो एक महिला होने के कारण उन पर दबाव बनाने की भी कोशिश करते हैं उन्होंने अपने अनुभव से साझा किया कि मेडिटेशन राजयोग ध्यान मेडिटेशन के अभ्यास के कारण उन्हें आत्मिक शक्ति करण अनुभव किया है एवं शांत मन के द्वारा ऐसी अनेक प्रकार की परिस्थितियों का सामना सफलता पूर्वक कर पाती हैं। इसी प्रकार कार्यक्रम में पधारी सीनियर गाइनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर दीप्ति दाते जी ने अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि किस प्रकार आज भी महिलाओं पर वारिस को जन्म देने का दबाव बनाया जाता है जो की ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक दिखाई देता है।इस प्रकार के दबाव के कारण महिलाओं पर अनावश्यक मानसिक तनाव एवं भावनात्मक कमजोरी भी दिखाई देती है।साथ ही साथ सोशल मीडिया, कई प्रकार के अनुचित एप्स एवं इंटरनेट के माध्यम से भी आज समाज में इस तरह के उत्पीड़न के अनेक मामले सामने आ रहे हैं। इन सब के चलते राजयोगिनी ब्रह्माकुमारी दुर्गा दीदी जी ने अपना अनुभव साझा करते हुए बताया कि वह पूर्व में आर्मी में आर्किटेक्चर रह चुकी है। एवं सबसे मिलते हुए पहले जो अनुभव करती थी तथा एक ब्रह्माकुमारी बनने के बाद उन्होंने अपने जीवन में परिवर्तन अनुभव किया। उन्होंने बताया कि ब्रह्माकुमारी संस्थान विश्व में एकमात्र ऐसी संस्थान है जिसकी सभी '145 देश में जो भी शाखाएं हैं सब की हेड अथवा इंचार्ज बहने एवं माताएं हैं' और सुचारू रूप से पूरा ही कारोबार किस प्रकार एक परमात्मा की याद से चलता है।

रोटरी क्लब मिडटाउन के दिव्यांग विंटर गेम्स मानवता का सबसे बड़ा तीर्थ

भोपाल। आम लोग की नजर में सहानुभूति के पात्र, लेकिन मन में कुछ कर गुजरने के जज्बे को लेकर प्रदेश के करीब डेढ़ हजार दिव्यांग बच्चों का खेल समागम विंटर गेम्स 24 नवंबर रविवार को भोपाल के टी टी नगर स्टेडियम में आयोजित किया गया । इस पर पधारे अतिथियों ने कहा कि विंटर गेम्स मानवता का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है यहां आकर लगता है कि हम किसी तीर्थ में आए हैं और विशिष्ट लोगों की सेवा कर रहे हैं यह दिव्यांग नहीं बल्कि विशेष है। इनमें सामान्य लोगों से कुछ ज्यादा होता है, इसलिए हमने विशेष में कहेंगे।

रोटरी क्लब भोपाल मिडटाउन द्वारा वर्ष 2001 से स्पेशल बच्चों के लिए हर वर्ष विंटर गेम्स आयोजित किए जाते हैं। इस बार 22वें संस्करण का आयोजन आगामी 24 नवंबर रविवार को टी टी नगर स्टेडियम में किया गया ।

इस अवसर पर कार्यक्रम की मुख्य अतिथि श्रीमती सोनाली वायगणकर प्रमुख सचिव सामाजिक न्याय विभाग मध्य प्रदेश ने कहा कि रोटरी क्लब मिडटाउन भोपाल द्वारा विंटर गेम्स के माध्यम से वास्तव में

समाज के दिव्यांग बच्चों को प्रोत्साहन देकर सामाजिक न्याय का कार्य किया जा रहा है। कार्यक्रम के विशेष अतिथि दिलीप बिल्डकॉन ग्रुप के सीएमडी दिलीप सूर्यवंशी ने कहा कि विंटर गेम्स में आकर ऐसा लगता है कि हम जैसे मानवता का कोई बड़ा तीर्थ कर रहे हैं उन्होंने कहा कि पिछले 22 साल से कभी ऐसा मौका नहीं आया जब मैं इस कार्यक्रम में शामिल न हुआ हूं। आगे भी मैं अपनी पूर्ण सहभागिता इस कार्यक्रम में रखूंगा। उन्होंने मिड टाउन भोपाल के सभी साथियों को इन विशेष बच्चों के कार्यक्रम आयोजन की बधाई दी। कार्यक्रम में बैंक ऑफ़ महाराष्ट्र की आंतरिक प्रबंधक श्रीमती रश्मि रेखापति केनरा बैंक के कार्यकारी निदेशक और मध्य प्रदेश प्रमुख दीपक कुमार बासु, रोटरी क्लब 3040 के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर अनीश मलिक मल्होत्रा शाहिद भोपाल के सभी रोटरी क्लबोन रोटेरियन उपस्थित थे। कार्यक्रम के संबंध में अपर मुख्य सचिव मध्य प्रदेश शासन संजय दुबे ने अपना शुभकामना संदेश भेजा।

इस कार्यक्रम में 32 संस्थाओं के विभिन्न श्रेणी के लगभग डेढ़ हजार से ज्यादा स्पेशल बच्चे शामिल हुए। इनमें मुख्यरूप से भोपाल के अलावा विदिशा, खरगोन, राजगढ़, होशंगाबाद, रीवा, जबलपुर, इंदौर, देवास, शुजालपुर , नरसिंहगढ़ और नागदा की संस्थाओं के बच्चे शामिल हुए। इस मौके पर स्पेशल ओलंपिक मापदंड के अनुसार दौड़, रिले दौड़, हिट द बाल, कैरम, पावर ऑफ रिस्ट, व्हील चेयर, चित्रकला, रेस प्रतियोगिताएं हुई। प्रथम द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले बच्चों को पुरस्कार दिए गए। इसके अलावा विभिन्न प्रतियोगिताओं में शामिल होने वाले सभी बच्चों और शिक्षकों को भी प्रोत्साहन के लिए प्रमाणपत्र और स्मृति चिन्ह दिए गए। यह आयोजन सभी दर्शकों के लिए खुला था। भोपाल रोटरी क्लब मिड टाउन की अध्यक्ष श्रीमती प्रीति उपाध्याय ने बताया कि भोपाल और मध्य प्रदेश के अन्य जिलों से आने वाले सभी प्रतिभागियों का विशेष रूप से ध्यान रखा गया है। यहां उन्हें आवास और परिवहन की सुविधा क्लब की ओर से निःशुल्क उपलब्ध कराई गई। विंटर गेम प्रोग्राम के चेयरपर्सन सुयश प्रताप सिंह ने बताया कि सभी दिव्यांग पार्टिसिपेशन करने वालों को अनिवार्य रूप से प्रमाण पत्र और रिटर्न गिफ्ट क्लब की ओर से उपलब्ध कराए गए । इस कार्यक्रम में एशियाई दिव्यांग खेलों में भाग लेने वाले कई प्रतिभागी भी शामिल हुए।

संपादकीय

महाराष्ट्र- कौन बनेगा मुख्यमंत्री

महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महायुति की महाविजय के बाद यह महासवाल भी सियासी हल्कों में तेजी से चल रहा है कि राज्य का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? देवेन्द्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे या फिर अजित पवार है। चुनाव में महायुति के तीनों घटकों ने अच्छा प्रदर्शन किया है। जो नतीजे आए हैं, उसकी तो महायुति को भी उम्मीद नहीं थी। लेकिन इस प्रचंड विजय ने राज्य कमान किसके हाथ का मुद्दा और संजीदा बना दिया है। अगर महायुति के मुख्य घटक भाजपा की बात की जाए तो चुनाव 132 सीटें जीतकर वह तीसरी बार सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। यानी 14 विधायक और जुटा ले तो उसकी अपनी सरकार बन सकती है। लेकिन भाजपा ऐसा शायद ही करेगी, क्योंकि इससे गठबंधन धर्म का अपमान होगा तथा सहयोगी दलों में भाजपा की नीयत को लेकर गलत संदेश जाएगा। जिसका दुष्परिणाम दूसरे राज्यों में भी देखने को मिल सकता है। शिवसेना शिंदे गुट ने भी 57 सीटें जीतकर उद्धव सेना को बौना बना दिया है। दो साल पहले एक रणनीति के तहत मात्र 40 विधायकों वाली शिवसेना (शिंदे) के नेता एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाकर और अपनी पार्टी के सीएम पद के सबसे बड़े दावेदार देवेन्द्र फडणवीस को उपमुख्यमंत्री बनाने का निर्णय लिया था। फडणवीस ने भी पार्टी के आदेश को शिरोधार्य करते हुए डिप्टी सीएम बनकर काम किया। उनकी और शिंदे की ट्यूनिंग भी अच्छी रही है। लेकिन चुनाव में बंपर सीटें जीतने के बाद भाजपा कार्यकर्ता यह मांग जोरों से उठा रहे हैं कि पार्टी पिछली बार की तरह कोई 'त्याग' न करे और देवेन्द्र को ही सीएम बनाए। वैसे भी भाजपा में देवेन्द्र फडणवीस ही सीएम पद के सबसे मजबूत दावेदार हैं। उधर शिवसेना शिंदे के विधायक एकनाथ शिंदे को ही फिर से सीएम बनाने के लिए दबाव बना रहे हैं। क्योंकि शिंदे के नेतृत्व में चली सरकार के काम पर ही मतदाताओं ने सकारात्मक वोट दिया है। वैसे सीएम पद के तीसरे दावेदार अजित पवार भी हैं, लेकिन उनकी दावेदारी बहुत मजबूत नहीं है। वो फिर से उपमुख्यमंत्री बनकर संतुष्ट रहेंगे। बड़ा सवाल शिंदे के सामने है कि अगर वो सीएम नहीं रहे तो क्या बनेंगे और मुख्यमंत्री पद नहीं दिया तो क्या वो विपक्ष में बैठना पसंद करेंगे? शिंदे की मुश्किल है कि यदि उन्होंने महायुति से बाहर निकलने का फैसला किया तो खुद उनकी पार्टी में भी बगावत हो सकती है। शिंदे के विधायक कतई नहीं चाहेंगे कि केवल सीएम पद की मांग के चलते पांच साल विपक्ष में बैठना पड़े। वैसे भाजपा सहित तीनों घटक पार्टियां सार्वजनिक रूप से यही कह रही हैं कि सीएम पद का मसला तीनों पार्टियों के शीर्ष नेता मिल बैठकर सुलझा लेंगे। यह भी संभव है कि सीएम पद की दावेदारी छोड़ने की ऐवज में शिवसेना (शिंदे) को मुंबई महानगर पालिका के मेयर पद का या केन्द्र में कैबिनेट मंत्री बनाने की पेशकश की जा सकती है। लेकिन शिंदे इस पर शायद ही राजी हों। अगर वो विपक्ष के साथ जाना भी चाहें तो मआवि के विधायकों की संख्या इतनी कम है कि उनके समर्थन से वो कोई सरकार बना सकें। वैसे भी इस चुनाव में जनता का आदेश महायुति के पक्ष में है। जो महायुति तोड़ेगा, उसे गंभीर खमियाजा भुगतना पड़ सकता है। यह संभव के अगले सा बिहार विधानसभा चुनाव तक शिंदे को ही सीएम बनाए रखें और उसके बाद उन्हें स्वेच्छा से पद छोड़ने को कहा जाए। शिंदे क्या करेंगे, यह अनुमान लगाना मुश्किल है। यह भी संभव है कि भाजपा नेतृत्व इस मामले में भी कोई चौंकाना वाला फैसला करे।

नजरिया

रघु ठाकुर
लेखक समाजवादी विचारक हैं।

एशियाई समाजवाद में है भारत की विदेश नीति की स्थिरता

यह भी एक संभावना है कि उनकी इस कल्पना के पीछे अमेरिका का कुछ संकेत रहा हो। क्योंकि सार्क में चीन नहीं था, बल्कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार शामिल थे। यह नीति एक प्रकार से चीन से भिन्न और पड़ोस के दक्षिण एशिया के देशों को एक मंच पर इकट्ठा कर चीन के मुकाबले खड़ा करने की नीति थी। इस नीति का भारत की सरकार ने, साम्यवादियों व लगभग सभी सदस्यीय दलों ने समर्थन किया। यद्यपि हम समाजवादियों ने यह माना कि यह डॉ. लोहिया के भारत-पाक महासंघ के द्वारा गरीब व भारत के विभाजन की काली रेखा को कमजोर करने और आक्रामक चीन के मुकाबले एक ताकतवर मंच बनाने की भूमिका से हटने की शुरुआत है। जबकि सार्क के इस विचार ने दक्षिण एशियाई भूभाग में एक एकता का मनोवैज्ञानिक वातावरण तैयार किया था। हम लोंगों ने दक्षेश देशों का सम्मलेन दिल्ली में आयोजित कर सार्क सिटीजन फोरम का गठन किया व उसके लिए काम शुरू किया था। परन्तु 1991 में स्व. नरसिंह राव के प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने सार्क से हटकर एक नई नीति की रचना की। श्लुक टू द ईस्ट्य की इस नीति के तहत पूर्वी एशिया याने चीन की तरफफिर दोस्ती के चश्मे से देखना शुरु किया है। इसके कई कारण हो सकते हैं।

यह कहना विचित्र सा लगेगा कि दुनिया एकता की तलाश विभेद में करती है। विशेषतः एशियाई देश जिसमें भारत भी शामिल है, इस अनिश्चितता की समस्या से मुक्त नहीं है। बीसवीं सदी के मध्य में दुनिया में एक अंतरराष्ट्रीय संगठन था, संयुक्त राष्ट्र संघ : दुनिया दो सामरिक धड़ों में विभाजित थी एक नाटो (नार्थ एटलान्टिक ट्रीटी) दूसरा नाटो मुख्यतः अमरीकी शक्ति के साथ चलने वाले देशों का संगठन था। दूसरा रूस, चीन व कम्युनिस्ट देशों की ताकत के साथ एक समझौते का संगठन है। नाटो, रूस, चीन के खतरों के विरुद्ध अपने संगठन के देशों को सुरक्षा मुहैया कराता था। दूसरा अमेरिकी याने नाटो के हमलों से सुरक्षा देने के लिए बनाया गया संगठन था। उस समय दुनिया इन दो ही शक्ति के धड़ों में विभाजित थी। परन्तु कालान्तर में कई शक्ति के केंद्र उभरे हैं और नाटो और दूसरे की भूमिका या तो सिकुड़ी है या बिखरी है। 1950 में आजादी के बाद भारत दोनों धड़ों से अलग था। और उसने भारत, अरब, युगोस्लाविया आदि देशों के साथ गुटनिरपेक्ष देशों का एक संगठन तैयार करने में सहभागिता की।

1950 और उसके बाद नेहरु, नासिर, टीटो की चर्चा दुनिया में युद्ध व हथियार की शक्ति से हटकर एक निर्गुट संगठन बनाने के रूप में हुई थी। इस गुटनिरपेक्ष विदेश नीति ने भारत और दुनिया को दो शक्तिशाली धड़ों के प्रभाव से बचाकर एक मंच विकसित करने की आशा जगाई थी। हालांकि इस गुट निरपेक्ष संगठन के ये तीन देश सामरिक, आर्थिक रूप से बहुत शक्तिशाली नहीं थे और अर्थ व शस्त्र से समर्थ दुनिया का कोई मजबूत विकल्प या उस ताकतवर दुनिया से पीड़ित देशों के लिए कोई सुरक्षा देने की स्थिति में व्यावहारिक रूप से नहीं थे। ये केवल एक नैतिक समर्थन कर सकते थे। भारत की गुटनिरपेक्ष नीति यद्यपि केवल नेहरु सरकार की देन नहीं थी बल्कि यह आजादी के आन्दोलन और महात्मा गाँधी की कांग्रेस की देन थी।

डॉ. लोहिया के जर्मनी से पढ़कर लौटने तथा कांग्रेस में सक्रिय होने के बाद उन्हें कांग्रेस पार्टी के विदेश विभाग का सचिव बनाया गया था। गुटनिरपेक्ष नीति के दस्तावेज को डॉ. लोहिया ने ही तैयार किया था। जिस पर कांग्रेस व तत्कालीन अध्यक्ष जवाहरलाल ने मोहर लगाईं थी। इक्कीसवीं सदी के आते-आते सामरिक तबके में शक्तियों के केंद्र बदल गए हैं अब दुनिया दो ध्रुवीय नहीं रही बल्कि एक अर्थ में बहु ध्रुवीय बन गई है। चीन भले ही रूस का वैचारिक भाई रहा परन्तु उसने कभी भी अपने मन से रूसी श्रेष्ठता या वर्चस्व को स्वीकार नहीं किया। 1960 के बाद तो, याने चीन में कम्युनिस्ट शासन की स्थापना के ग्यारह वर्ष बाद चीन ने अपनी वैश्विक व विदेश नीति की भूमिका को रूस से स्वतंत्र रूप से अदा करना शुरू कर दिया था। 1960-70 के बाद चीन-रूस के भी समानंतर खड़े होने लगा। अपने प्रभाव का फैलाव आसपास के देशों में करने लगा था। 1959 में उसने सैन्य शक्ति से तिब्बत पर कब्जा किया। पंचशील समझौते के दो साल बाद ही भारत की उत्तरी सीमा पर हमला कर भारत के बड़े भूभाग पर कब्जा किया। इन सब में रूस की भूमिका लगभग एक मूकदर्शक व समर्थक जैसी बनी रही। इन घटनाओं से नाटो और सेंटो का प्रभाव कम हुआ। वियतनाम में सारे हथियारों के प्रयोग के बाद भी अमेरिकी पराजय के बाद अमेरिका और नाटो की भूमिका अविश्वसनीय और सीमित हुई।

इक्कीसवी सदी के आते-आते दुनिया ने नाटो और सेंटो से हटकर तथा यू.एन.ओ. से भी इतर अपनी अपनी सुविधा और जरूरत के अनुसार देशों के समूह बनाने शुरू किये। 1991 में स्व. नरसिंह राव की सरकार ने श्लुक टू द ईस्ट्य के नाम से एक नई विदेश नीति की शुरुआत की। उन्होंने पाकिस्तान से भिन्नता व सार्क संगठन की भारतीय विदेश नीति के बदलने की शुरुआत की। दरअसल 1980 के बाद सार्क की चर्चा (दक्षिण एशियाई देशों) शुरू हुई थी। इसके मूल में बांग्लादेश के विद्वान थे जिन्होंने दक्षिण एशियाई देशों के एक आर्थिक संगठन की कल्पना प्रस्तुत की। यह भी एक संभावना है कि उनकी इस कल्पना के पीछे अमेरिका का कुछ संकेत रहा हो। क्योंकि सार्क में चीन नहीं था, बल्कि पाकिस्तान, अफ्गानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार शामिल थे। यह नीति एक प्रकार से चीन से भिन्न और पड़ोस के दक्षिण एशिया के देशों को एक मंच पर इकठ्ठा कर चीन के मुकाबले खड़ा करने की नीति थी। इस नीति का भारत की सरकार ने, साम्यवादियों व लगभग सभी सदस्यीय दलों ने समर्थन किया। यद्यपि हम समाजवादियों ने यह माना कि यह डॉ. लोहिया के भारत-पाक महासंघ के द्वारा गरीब व भारत के विभाजन की काली रेखा को कमजोर करने और आक्रामक चीन के मुकाबले एक ताकतवर मंच बनाने की भूमिका से हटने की शुरुआत है। जबकि सार्क के इस विचार ने दक्षिण एशियाई भूभाग में एक एकता का मनोवैज्ञानिक वातावरण तैयार किया था। हम लोंगों ने दक्षेश देशों का सम्मलेन दिल्ली में आयोजित कर सार्क सिटीजन फोरम का गठन किया व उसके लिए काम शुरू किया था। परन्तु 1991 में स्व. नरसिंह राव के प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने सार्क से हटकर एक नई नीति की रचना की। श्लुक टू द ईस्ट्य की इस नीति के तहत पूर्वी एशिया याने चीन की तरफफिर दोस्ती के चश्मे से देखना शुरु किया है। इसके कई कारण हो सकते हैं।

1. उस समय अमेरिका व चीन के बीच मित्रवत सम्बन्ध शुरू हो गए थे व व्यापारिक संबंध और चीन अमेरिका के आर्थिक व राजनैतिक सम्बन्ध भी पिघलने लगे थे। अमेरिका ने अपना बाजार चीन के लिए खोला था। तथा चीन ने अमेरिकी कंपनियों को प्रवेश देना शुरू किया था। यह जुमला चल पड़ा था कि अब विदेश नीति व रिश्ते सरकारें या राजनीति नहीं वरन व्यापार तय करेगा।
2. वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर लादेन के हमले के बाद अमेरिका का मुख्य लक्ष्य लादेन को मारना व अफगानिस्तान के तालिबानों को मिटाना था। एक प्रकार से यह मुस्लिम कट्टरपन्थ व मुस्लिम आक्रामकता के खिलाफभी वैश्विक हमला था। स्व. नरसिंह राव भी अयोध्या में बाबरी मस्जिद के तोड़े जाने के बाद देश व विदेश में मुस्लिम समाज के निशाने पर थे। सम्भव है कि इसीलिए उन्होंने वेस्ट से हटकर ईस्ट की ओर देखना शुरू किया है। लगभग एक दशक तक भारत की सरकारें इस नीति पर चलती रहीं। परंतु जब चीनी आर्थिक सत्ता व आर्थिक साम्राज्यवाद से अमेरिका के लिए खतरा शुरू हुआ तो अमेरिका ने अपनी नीति को बदला। चीन ने अमेरिका के के उपभोक्ता बाजार पर कब्जा जमा लिया था। अपनी साहूकारी नीति से पैसा देकर नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका, मालद्वीव, बांग्लादेश आदि देशों को अपने प्रभाव क्षेत्र में ले लिया। और वन बेल्ट वन रोड की महत्वाकांक्षी योजना से अपने व्यापार को सड़क मार्ग से ईरान और यूरोप तक जोड़ने की योजना पर काम शुरू किया था। इस खतरे को समझ कर अमेरिका ने अपने बाजार व सहयोगी देशों के बाजार में चीन को प्रतिबंधित करना शुरु किया। चीनी विस्तार को फिर से रोकने की नीति शुरू की। भारत कभी भी अमेरिकी प्रभाव से मुक्त नहीं हो सका है। जिस प्रकार अमेरिका की चीन के प्रति नीति बदलने से भारत भी पूर्व की ओर देखने लगा था उसी प्रकार बाद में अमेरिका की नजर से भारत ने पश्चिम की ओर देखना शुरू किया। इसके लिए कई कई देशों के कई संगठन बनाये जाने शुरू हुए। विदेश नीति में एक बदलाव आया कि विभिन्न विषयों के आधार पर देशों के समूह या संगठन बनाये जायें या जो बने उनमें शामिल हुआ जाए। यह एक प्रकार से दो ध्रुवीय दुनिया के विखंडन की शुरआत थी। संघाई सहयोग के नाम से (एससीओ) नामक एक समूह बना जिसमें चीन नहीं था पर पाकिस्तान है। इस संगठन के सम्मेलन में हिस्सेदारी करने के लिए 9 वर्षों के बाद भारत के विदेशमंत्री श्री जयशंकर 15 अक्टूबर को पाकिस्तान पहुंचे। यद्यपि यह शिरकत अभी बहुत प्रारंभिक है। इसके चार दिन पूर्व याने 11 अक्टूबर 2024 को वियतनाम में एशिया शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने कहा था कि विश्व के विभिन्न भागों में जारी संघर्षों का सर्वाधिक नाकारात्मक प्रभाव ग्लोबल साउथ के देशों पर पड़ा है। भारत सरकार ने 1950 की निर्गुट नीति, फिर सार्क संगठन फिर, लुक टू द ईस्ट, फिर ब्रिक्स और अब दक्षिण एशिया के आगे जाकर दक्षिणी विश्व की चर्चा शुरू की है।

ब्रिक्स में भार, रूस, चीन और विश्व के दक्षिण के देश जिनमें साउथ अफ्रीका, किर्गिजिस्तान आदि शामिल हैं को महत्व देना शुरू किया। उन्होंने अपने भाषण में पश्चिमी एशिया में शान्ति बहाल हो इसकी भी चर्चा शुरू की। याने विदेश नीति का केंद्र अब सार्क से हटकर कुछ पूर्वी एशिया के देशों की तरफ देखना शुरू किया। ग्लोबल साउथ का इस्तेमाल लेटिन अमेरिका, अफ्रीका और ओसानिया के गरीब और पिछड़े देशों के लिए किया जाता है। कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि भारत की विदेश नीति अस्थिरता और भटकाव में घूमती है। जिसे अपने वास्तविक राष्ट्रीय हितों की या तो ठीक समझ नहीं है या फिर उनके प्रति गंभीर नहीं है।

पूर्वी एशिया के शिखर सम्मलेन के एक दिन पहले ही श्री नरेन्द्र मोदी ने लाओस में भारत आशियान ने बैठक को सम्बोधित किया था। उपर्युक्त घटनाओं से यह स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है कि भारत की विदेश नीति तात्कालिकता और अस्थिरता के दौर से गुजर रही है। 1950 के दशक में ही समाजवादी नेता डॉ. राममनोहर लोहिया ने एशियाई समाजवाद शब्द का इस्तेमाल किया था। उन्होंने रंगून के सम्मेलन में एशियाई समाजवाद की परिकल्पना प्रस्तुत की थी। वे चाहते थे कि एशिया के सभी देश समाजवाद के रास्ते को स्वीकार करें और एक सामूहिक नीति तैयार करें, जो अमेरिकी पूँजीवाद और नाटो के सैन्य वर्चस्व तथा रूस के साम्यवाद और सेंटो के वर्चस्व से हटकर हो। एशिया के देश राष्ट्रीय सम्पन्नता, लोकतंत्र, समता और छोटी मशीन के आधार पर एशिया को समाजवादी बनाने की पहल करें। यह पूँजीवाद और साम्यवाद दोनों के आर्थिक और राजनैतिक वर्चस्व का विकल्प बने। अगर डॉ. लोहिया की विदेश नीति को तत्कालीन भारत सरकार ने स्वीकार किया होता और एशिया में समाजवाद की नीति को स्वीकार किया होता तो भारत की विदेश नीति में स्पष्टता और स्थिरता होती। एशिया अगर आज भी समाज की विचार व्यवस्था और सिद्धांतों पर एक गुट हो सके तो अफ्रीकी महाद्वीप व लेटिन अमेरिकी देश एशिया के साथ होंगे। क्योंकि वे भी पूँजीवादी अमेरिका और यूरोप से शोषित हैं। शोषण मुक्त समाज की दुनिया के लिये यह एक ऐतिहासिक पहल हो सकती है।

प्रसंग

चित्रा माली
लेखक गांधी एवं शांति अध्ययन विभाग महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय क्षेत्रीय केंद्र कोलकाता में सहायक प्रोफेसर हैं।

हिंसा के बढ़ते आंकड़ों के बीच अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस

अंतरराष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस महिलाओं के प्रति हिंसा,शोषण और उत्पीड़न की बढ़ती घटनाओं के उन्मूलन हेतु संयुक्त राष्ट्र के द्वारा प्रतिवर्ष 25 नवंबर को यह दिवस मनाया जाता है। इस दिन का अपना एक इतिहास है। 25 नवंबर 1960 में तीन बहनों (पैट्रिया,मारिया,एंटोनिया) की सामूहिक हत्या डोमिनिक तानाशाह शासक राफेल ट्रिर्जलों ने करवाई थी। इन बहनों की हत्या महज इसलिए करवाई गई थी कि वे अपने अधिकारों के लिए तानाशाह के खिलाफ लड़ रही थी। 1981 में महिला अधिकारों के समर्थकों ने उन तीन बहनों की स्मृति में महिला हिंसा के खिलाफ इस दिन को मनाने की शुरुआत की। 1993 में संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने 'महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन की घोषणा' करते हुए महिलाओं के विरुद्ध हिंसा को परिभाषित भी किया था इसके अनुसार लिंग आधारित हिंसा का कोई भी कार्य जिसके परिणामस्वरूप शारीरिक,यौन संबंध स्थापित होते है या स्थापित होने की संभावना है तथा महिलाओं को मानसिक क्षति या पीड़ा पहुंचना भी हिंसा है। इसके अतिरिक्त किसी भी महिला को डराना,धमकी देना या उन्हें उनकी स्वतंत्रता से वंचित करना भी हिंसा की श्रेणी में आता है यह सार्वजनिक और निजी दोनों जीवन में शामिल हैं । महिला हिंसा के खिलाफ अपनी प्रतिबद्धता को जाहिर करते हुए 1999 में संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने 25 नवंबर को अंतरराष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस घोषित किया। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा महिला हिंसा उन्मूलन कार्यक्रम के तहत 2008 से 2030 तक एक UNITE Campaign चलाई जा रही है। संयुक्त राष्ट्र के प्रयासों के फलस्वरूप ही 155 देशों में 'घरेलू हिंसा' पर नियंत्रण करने के लिए कानून बनाए गए है तथा 140 देशों ने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न रोकने के लिए कानून बनाए है। संयुक्त राष्ट्र महिला संघ की स्थापना भी संयुक्त राष्ट्र सुधार कार्यक्रम एजेंडे के तहत हुई है जिसमें लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण से संबंधित संसाधनों एवं अधिकार क्षेत्र को एक साथ जोड़ा गया है जो अधिक प्रभावी है। प्रतिवर्ष 25 नवंबर से 10 दिसंबर तक 16 दिवसों तक लोगों को महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा के खिलाफ सक्रिय और जागरूक करने के लिए यह अभियान चलाया जाता है। इसका स्लोगन है No E&cuse महिलाओं के खिलाफ हिंसा को समाप्त करने के लिए एकजुट हो और इस दिन यूनेस्को के द्वारा विश्व को नारंगी रंग में रोशन किया जाएगा।

महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा में यौन शोषण और उत्पीड़न,बलात्कार एवं बलात्कारोत्तर मानसिक और शारीरिक शोषण,तस्करी,अपहरण,

अनैतिक देह व्यापार, घरेलू हिंसा,भावनात्मक शोषण,एसिड अटैक, डेटिंग दुरुपयोग, अंतरंग साथी की हिंसा, जबरन पोर्नोग्राफी, सायबर क्राइम,छिपकर देखना (Stalking),ब्लेक मेल (Voyeurism) करना,ऑनर किलिंग इत्यादि को शामिल किया जाता है। समूचे विश्व में महिलाओं और लड़कियों के साथ किसी न किसी रूप में हिंसा अवश्य होती है जिसकी मात्रा देशों की विविधताओं के साथ कम या ज्यादा हो सकती है,लेकिन हर देश की महिला हिंसा को सहती है। अफ्रीका सहित कई देशों में संस्कृति के नाम पर महिलाओं का जननांगछेद्रिकरण और ब्रेस्ट आयरनिंग जैसी भयावह अमानवीय प्रथाएं प्रचलित हैं। चीन में भी संस्कृति के नाम पर फुट बाध्यकरण (Foot Binding) महिलाओं पर सदियों से थोपा जा रहा है। हमारे देश भारत में भी संस्कृति के नाम पर कई ऐसी प्रथाएं प्रचलित है जिसमें महिलाओं के साथ हिंसा होती है। वैश्विक स्तर पर लगभग 736 मिलियन महिलाओं में औसतन तीन में से एक महिला अपने जीवन में कम से कम एक बार शारीरिक और यौन शोषण का शिकार होती है। वैश्विक स्तर पर 35 प्रतिशत महिलाओं ने यौन हिंसा का अनुभव किया है जिसमें उनके अंतरंग साथी और अन्य पुरुष शामिल हैं। कोविड-19 के बाद महिलाओं के साथ यौन हिंसा में 5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। प्रतिदिन लगभग 137 महिलाओं को उनके परिवार के सदस्यों के द्वारा मार डाला जाता है। 40 प्रतिशत से भी कम महिलाएं अपने साथ हो रही हिंसा के खिलाफ किसी से सहायता ले पाती हैं। मानव तस्करी से पीड़ित लोगों में महिलाओं की संख्या 49 प्रतिशत, लगभग आधी है। 31 देशों में 15 से 49 आयु वर्ग की 200 मिलियन महिलाओं और लड़कियों ने जननांग विकृति (Female Genital Mutilation) का सामना किया है। 15 से 19 आयु वर्ग की 15 मिलियन लड़कियों ने अपने साथ जबरन सेक्स का अनुभव किया है। यूरोपीय संघ की 10 महिलाओं में से एक महिला 15 वर्ष से भी कम आयु में साइबर क्राइम का शिकार हुई है। मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका में 40 से 60 प्रतिशत महिलाओं के साथ सड़क पर यौन उत्पीड़न हुआ है। 82 प्रतिशत महिला सांसदों ने यह स्वीकार किया है कि वे मानसिक हिंसा का शिकार हुई है। WHO की रिपोर्ट के अनुसार प्रतिदिन 3 में से 1 महिला किसी न किसी प्रकार की हिंसा के साथ शारीरिक हिंसा का शिकार होती है। महिलाओं के साथ होने वाली लैंगिक हिंसा में लगातार वृद्धि हुई है जिसके आंकड़े उपलब्ध है और वर्तमान में 161 देशों की जनकारी उपलब्ध है जिसका इस्तेमाल संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (NFPA) और संयुक्त राष्ट्र महिला के इन आंकड़ों से निष्कर्ष निकालने का कार्य कर रहे हैं जो महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ सभी प्रकार की हिंसा को समाप्त करने पर केंद्रित एक नई वैश्विक और बहु – वर्षीय पहल 'द स्पॉटलाइट इनिशिएटिव' है। महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा उनके मानवाधिकारों का हनन है। किसी व्यक्ति को उसकी मर्जी के बिना कोई काम करने या कोई बात मानने के लिए मजबूर करने के लिए जब शक्ति का प्रयोग किया जाता है तो नतीजा हिंसा में निकलता है। हिंसा शारीरिक,आर्थिक और मानसिक सभी प्रकार की हो सकती है। हिंसा शक्ति-संबंध का एक अनिवार्य आयाम है। हिंसा के प्रकट और प्रच्छन्न रूप को संरचनात्मक हिंसा के प्रमुख सिद्धान्तकार जोहन गालटुंग ने अलग अलग प्रकारों से स्पष्ट किया है। लैंगिक आधार पर महिलाओं और लड़कियों के साथ हर रोज कोई न कोई हिंसा होती रहती है इसमें ट्रांसजेंडर और समलैंगिक भी शामिल है। प्रोग्रेस ऑन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स: द जेंडर स्नैपशाट की 2022 की रिपोर्ट के अनुसार कार्यस्थल पर उच्च पदों पर समान रूप से प्रतिनिधित्व प्राप्त करने में अभी 140 साल का समय और लगेगा और राष्ट्रीय सांसदों में समान प्रतिनिधित्व हासिल करने में कम से कम 40 वर्षों का समय लगेगा। वर्तमान में बाल विवाह को रोकने हेतु जो प्रयास किए जा रहे हैं उन्हें 17 गुना तेज करना होगा तभी सफलता प्राप्त हो सकेगी। वर्ष 2030 तक लैंगिक समानता के लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। वर्तमान प्रगति की गति से वैश्विक स्तर पर पूर्ण लैंगिक समानता हासिल करने में 300 वर्षों का समय लगेगा। लैंगिक समानता के लिए वैश्विक स्तर के साथ साथ क्षेत्रीय स्तर पर सहयोग और भागीदारी को सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। इस रिपोर्ट के अनुसार कानूनी संरक्षण में अंतराल को पाटने और भेदभावपूर्ण कानूनों को दूर करने में 286 वर्षों तक का समय लगेगा। वर्तमान समय में हम जिस दौर से गुजर रहे हैं वही स्थिति रही तो अफ्रीका में 2030 में आज की तुलना में महिलाएं और लड़कियां अत्यधिक गरीबी का सामना करेंगी। कोविड-19 और वैश्विक स्तर पर विभिन्न देशों के मध्य हिंसक संघर्षों ने महिलाओं को प्रभावित किया।

फूल नोचवा प्रजाति को प्रणाम

कटाक्ष

श्याम यादव
लेखक व्यंग्यकार हैं।

अलसुबह मुंह अंधेरे उठने वाले उन तमाम बंधुओं भगनियों को मेरा प्रणाम।

प्रणाम इसलिए कि इस कुनकुनी ठंड के मौसम में जब अलसुबह हम जयपुरिया रजाई में दुबके पड़े रहते हैं तब ये लोग बिना ठंड की परवाह किए हल्के अंधेरे में मुंह छिपाए,हाथों में पन्नी की थैली लिए हुए उन फूलों का शिकार करने निकल जाते हैं, जो बस सूरज निकलने से पहले खिल कर वातावरण को खुशनुमा बनाने का प्रयास करते हैं। इन फूलों को तोड़ने, मतलब नोचने के पीछे इनका कोई आर्थिक हित नहीं होता। मतलब ये फूलों का कोई व्यापार व्यवसाय नहीं करते।

इन फूल नोचवा प्रजाति में केवल पुरुष ही नहीं स्त्रियां भी होती है और जिस बेरहमी से ये खिलते हुए फूलों को डाली से नोचते है। उससे लगता है कि ये फूल तोड़ने की कला में पारंगत होते हैं। अब इनकी ये फूलों को नोचने को कला कहा जाय या विज्ञान ये अलग बहस का विषय हो सकता है। फूल नोचवा प्रजाति केवल मनुष्यों में ही पाई जाती है। आपकी बाउंड्री पर रखे गमले हो या बगिया के पौधे, इनकी निगाह से कोई नहीं बच पाता। अब इस बात पर अनुसंधान किया जा सकता है कि इस प्रजाति के मनुष्यों में ये गुण स्वमेव ही पैदा होता है या एक दूसरे को देख कर ये सीख जाते हैं।

बहस का विषय तो यह भी हो सकता है कि इस तरह से फूल को नोचना चोरी की श्रेणी में आता है या श्रद्धा की। बहरहाल जो भी हो कवि माखनलाल चतुर्वेदी की पुष्प की अभिलाषा से इनका कोई सरोकार नहीं होता। क्योंकि, ये वनमाली होते नहीं।

पानी, खाद, पौधा कोई भी लगाए इनका तो एकमात्र मकसद ही फूल को तोड़ना ही होता है। यदि कोई इन्हें ऐसा करने से रोकने का प्रयास करे, तो वे इसे भगवान के नाम से नोचने का वास्ता दे देते हैं। भगवान के नाम पर ये फूल नोच ले जाते है। फूलनोचवा की ये प्रजाति हर जगह पाई जाती है। चाहे बसाहट गरीबों वाली हो या अमीरी वाली। अंधेरे में भी इनकी आँखें इतनी तेज होती है कि ये उल्लू को भी चकमा दे सकते है। ये प्रजाति फूल को दूर से ही निहार लेती है।

आधे पौन घंटे के अलसुबह के इनके भ्रमण से इनका खुद का स्वास्थ्य तो ठीक रहता है, लेकिन ये पौधों का स्वास्थ्य खराब कर देते हैं। इतनी देर में इनकी वो थैली जो ये साथ ले कर चलते है भर जाती है ,लेकिन इस बीच वे 'अलीबाबा चालीस चोर की कहानी' के तरह उन फूलों की भी पहचान कर लेते है जो अगले दिन कली से फूल बनाने वाले होते है। यकीन न आए तो कभी अलसुबह उठकर इन फूल नोचवा प्रजाति से साक्षात्कार कर लीजिएगा।

व्यंग्य

अशोक गौतम
लेखक व्यंग्यकार हैं।

चरण कमल बंदौ पाठकाई

वे जब भी निकट भविष्य में किसी में भी दुहने की संभावनाएं देखते हैं तो उसके चरण कमलों के हो जाते हैं। तब उसे वे गैर मंजूरशुदा अहाते में उसकी सेवा करवाने लाते हैं। वे गैर मंजूरशुदा साहित्य रचते हैं। गैर मंजूरशुदा अहाते में गला तर करने बैठते हैं। हर मंजूरशुदा से उनका सैंतीस का आंकड़ा है। कल फिर वे अचानक गैरमंजूर शुदा अहाते में बैठे दिखे, अपने तय कोने में। उन्हें बहुधा कोने ही पसंद हैं। चाहे साहित्य के हों या फिर गैर मंजूरशुदा अहाते के। मैंने देखा कि उन्होंने कोई जकड़ रखा है। उनकी मास्टर किसीको उतनी पकड़ने में नहीं जितनी जकड़ने में है। गैर मंजूरशुदा ही सही , साहित्यकार हैं, सो, प्रकाशक, आलोचक, संपादक ही पकड़ेंगे। मेरी तरह श्रीमती के चरण तो पकड़ने से रहे। नीच से नीच गृहस्थ को जो कहीं मुक्ति मिलती है तो केवल बीवी के चरणों में ही मिलती है।

मैंने अपने कबाड़ी की शर्ट के मेरी तरह तुड़े मुड़े कॉलर खड़े किए और दबे पांव उनके पास जा पहुंचा। मुझे देख वे तनिक भी विचलित नहीं हुए। बस, जिसके वे चरणों को चूम रहे थे, उनके पास से हाथ जोड़ उठे और मुझे गैर मंजूरशुदा अहाते के दूसरे कोने में ले गए।

'बंधु ! ये कौन?' मैं। सीधा प्रश्न पर आया। 'बस, यों ही समझ लो।' 'मतलब कोई प्रकाशक फांस लिया क्या ? कहीं कीं इंट कहीं का रोड़ा रचनाओं का कालजयी संग्रह प्रकाशित करवाने के लिए?'

'नहीं !' वे पूरे आत्विश्वास से बोले।

'तो क्या साहित्य विभाग के कोई अफसर हैं? अफसरों की कृपा हो तो कूड़ा भी कालजयी हो सरकारी खरीद में मजे से चला जाता है।'

'नहीं !' कहते हुए झिझके नहीं तो साफ हो गया कि वे सरकारी साहित्य विभाग के अफसर भी नहीं। मतलब वे सच बोल रहे हैं।

'तो क्या कहीं कीं इंट कहीं काा रोड़ा रचनाओं की पेड समीक्षा के लिए कोई समीक्षक हैं?' 'कहा न ! नहीं यार ! तुम भी न ! लेखक की खाल उतार कर रख देते हो।'

'तो क्या कहीं कीं इंट कहीं को रोड़ा रचनाओं को प्रकाशित करवाने के लिए कोई संपादक पटा रहे हो?' 'नहीं।' 'तो ये बेतलब के अपरिचित कौन? क्योंकि जानता हूं जिससे तुम्हारा मतलब नहीं होता उसकी ओर तुम ओढ़ी नजर से भी नहीं देखते। ऐसे में....' 'मेरा पाठक है यार !' उन्होंने सीना चौड़ा कर कहा तो मैं बेहाश होते होते बचा।

'पाठक? पाठक और लेखक का क्या नाता? लेखक और प्रकाशक का रिश्ता तो समझ में आता है, लेखक और संपादक का रिश्ता भी समझ में आता है, लेखक और समीक्षक का रिश्ता भी कुछ कुछ समझ में आता है, पर लेखक और पाठक का नाता? सबकुछ हजम कर जाने वाले को ये बात गुरु कुछ हजम नहीं हो रही,' मैंने दो टूक कहा तो वे झल्लाते बोले,' समझते क्यों नहीं यार ! पाठक है तो लेखक है। आजकल पाठक मिलता ही कहां है? तम अपने को चिड़िया का दूध लाने को कहोगे तो पलक झपकते ले आऊंगा। पर माफ करना ! पाठक लाने को कहोगे तो मैं शर्मिंदा हो जाऊंगा। हालांकि मैं शर्म फ्री जीव हूं। कहीं भी किसी भी किसी भी स्तर की साहित्यिक गोष्ठी में चले जाओ। साहित्यिक गोष्ठियों में सब कुछ होता है, चाय होती है, समोसा होता है, लंच भी कभी कभार हो जाता है। ऑन लाइन पारिश्रमिक भी कभी कभार खाते में आ ही जाता है। जितना आने जाने का किराया भरो वह भी हो जाता है, पर गोष्ठियों में नहीं मिलता तो बस, पाठक नहीं मिलता। खुशनसीब होते हैं वे साहित्यकार जिनके पास साहित्य के अतिरिक्त पाठक भी होते हैं।'पाठक' मैंने न की मुद्रा में अपने कंधे उचकाए तो वे बोले,' तुम क्या समझो पाठक की ट्र वैल्यू ! सच्चे लेखक नहीं हो न ! साहित्यकार होने के लिए पहली शर्त साहित्य नहीं, साहित्य रचने से पहले उसके साहित्य के पाठक होती है। पाठक है तो प्रकाशक है, पाठक है तो संपादक है, पाठक है तो समीक्षक है। जो पाठक नहीं होगा तो प्रकाशक क्या करेगा? जो पाठक नहीं होगा तो अखबार कहां जाएगा?'

' विज्ञापकों के पास । आज पाठक पढ़ने से बेहतर विज्ञापन देखना पसंद करते हैं।' 'चुप ! जो पाठक नहीं होगा तो पत्रिका कहां जाएगी? जो पाठक नहीं होगा तो समीक्षक क्या करेगा? पूरा का पूरा कुनबा उजड़ नहीं जाएगा क्या?' कहते कहते वे जुगाड़ू साहित्यकार से साहित्य के सच्चे साधक हुए,' कल बंधु का फोन आया था। कहा कि मैं तुम्हारा पाठक बोल रहा हूं,' सच कहूं, साहित्यकार न होते हुए भी बंधु के मुखारविंद से यह सुना तो साहित्य मुंह को आ गया। समाज में सबकुछ मिल जाता है। रचनाओं को छपवाने के लिए संपादक भी मिल जाता है। किताब को छपवाने के लिए प्रकाशक भी मिल जाता है। प्रकाशित पुस्तक को थोक खरीद में लाने के लिए अपने को बेचने वाले भी मिल जाते हैं। पुस्तक चयन कमेटी में अपने रिश्तेदार भी मिल जाते हैं, न मिलें तो दूसरों से दूर की रिश्तेदारियां निकल आती हैं, पर पाठक मिलना बहुत दुर्लभ होता है बंधु ! गीदड़ सींगी की तरह। जिस लेखक को एक भी पाठक मिल जाए, उसकी रचना कालजयी हो या न, पर वह हर हाल में कालजयी हो जाए। इसलिए मैं उसी श्रीपाठक के चरणों की सेवा वंदना में लीन हूं जिस श्रीपाठक की कृपा से मुझसा साहित्कार भी कालजयी और मालजयी निकट भविष्य में एक साथ हो सकता है, जिस श्रीपाठक की कृपा से कचरा छापने वाले प्रकाशक को भी मां लक्ष्मी के दर्शन होने लगते हैं, जिस श्रीपाठक का फोन आते ही मेरे जैसा धूर्तन्य भी मूर्धन्य हो जाता है। हे बंधु ! मैं गैर मंजूरशुदा अहाते के कोने में उसीके श्रीचरणों की सोमवंदना कर रहा हूं सॉरी !' उन्होंने कहते हुए मुझे हाथ जोड़े और अपनी रुकी वंदना को पुनः चालू करने के लिए कोने की ओर हो लिए।

स्वामी, सुबह सवेरे मीडिया एल.एल.पी. के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक उमेश त्रिवेदी द्वारा श्री सिद्धीविनायक प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 26-बी, देशबंधु परिसर, प्रेस कॉम्प्लेक्स, जोन-1, एम.पी.नगर, भोपाल, म.प्र. से मुद्रित एवं डी-100/46, शिवाजी नगर भोपाल से प्रकाशित।

प्रधान संपादक
उमेश त्रिवेदी
कार्यकारी प्रधान संपादक
अजय बोकिल
संपादक (मध्यप्रदेश)
विनोद तिवारी
वरिष्ठ संपादक
पंकज शुक्ला
प्रबंध संपादक
अरुण पटेल
(सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल रहेगा)
RNI No. MPHIN/ 2003/ 10923,
Ph. No. 0755-2422692, 4059111
Email- subahsaverenews@gmail.com

'सुबह सवेरे' में प्रकाशित विचार लेखकों के निजी मत हैं। इनसे समाचार पत्र का सहमत होना आवश्यक नहीं है।

कानून और न्याय

विनय झैलावत

(पूर्व असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल एवं वरिष्ठ अधिवक्ता)

मदरसा अधिनियम-1

मदरसा अधिनियम की संवैधानिक वैधता बरकरार

सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि मदरसों जैसे अल्पसंख्यक संस्थानों को अनुच्छेद 30 के तहत धार्मिक शिक्षा प्रदान करने और अपना प्रशासन संभालने का अधिकार है। उच्चतम न्यायालय ने उच्च शिक्षा से संबंधित प्रावधानों पर रोक लगाने वाले उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ मदरसा शिक्षा अधिनियम, 2004 की संवैधानिक वैधता को मंगलवार को बरकरार रखा। सर्वोच्च न्यायालय ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस फैसले को खारिज कर दिया, जिसने धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन करने के लिए पूरे अधिनियम को रद्द कर दिया था। सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले का सभी वर्गों ने स्वागत किया है।

मदरसे इस्लामी सिद्धांतों और प्रथाओं के साथ-साथ मुख्यधारा की धर्मनिरपेक्ष शिक्षा दोनों में धार्मिक शिक्षा प्रदान करते हैं। अधिकांश मदरसे राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद पाठ्यक्रम का पालन भी करते हैं। मदरसा अधिनियम उत्तर प्रदेश में इन संस्थानों के लिए एक कानूनी ढांचा प्रदान करता है। इसने उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड की स्थापना की है जो पाठ्यक्रम सामग्री तैयार करता है और निर्धारित करता है और सभी पाठ्यक्रमों के लिए परीक्षा आयोजित करता है। यह अधिनियम राज्य सरकार को मदरसा शिक्षा को विनियमित करने के लिए नियम बनाने की शक्ति भी देता है।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने यह कहते हुए इस अधिनियम को पूरी तरह रद्द कर दिया था कि यह संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करता है। साथ ही यह कानून धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973) में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि संसद संविधान के मूल ढांचे को बदल नहीं सकती है। इसके अलावा एसआर बोम्मई बनाम भारत संघ (1994) में फैसला सुनाया था कि धर्मनिरपेक्षता मूल ढांचे का हिस्सा है। उच्च न्यायालय ने कहा कि अधिनियम ने छात्रों के लिए इस्लाम का अध्ययन करना अनिवार्य कर दिया है और अधिक आधुनिक विषयों को वैकल्पिक बना दिया गया है। इसने माना कि राज्य धर्म के आधार पर शिक्षा प्रदान करके भेदभाव नहीं कर सकता है।

उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में यह भी कहा था कि यह अधिनियम आधुनिक विषयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से वंचित करके संविधान के अनुच्छेद 21 ए के तहत मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार का उल्लंघन करता है। इसमें कहा गया है कि अधिनियम के तहत फाजिल और कामिल जैसी उच्च शिक्षा की डिग्री प्रदान करने की बोर्ड की शक्तियां क्रमशः स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्री के बराबर-विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (यूजीसी अधिनियम) के साथ संघर्ष करती है। सर्वोच्च न्यायालय ने तीन मुख्य आधारों पर उच्च न्यायालय के फैसले को दरकिनार किया। सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार बुनियादी शिक्षा परीक्षण की आवश्यकता नहीं है। संवैधानिक संशोधनों का परीक्षण बुनियादी संरचना सिद्धांत के खिलाफ किया जाता है, न कि एक सामान्य विधान के खिलाफ।

अपने फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने इंदिरा गांधी बनाम राज नारायण (1975) के अपने फैसले का हवाला देते हुए इसे रेखांकित किया, जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में संशोधन से संबंधित था। इसे इंदिरा गांधी को चुनाव में भाग लेने से अयोग्य ठहराने के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले को उलटने के लिए लागू किया गया था। संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करने के लिए संशोधन को चुनौती दी गई थी। हालांकि, सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि, यह तर्क कि संशोधन मूल संरचना का उल्लंघन करता है, एक साधारण कानून की वैधता निर्धारित करने के लिए बहुत अस्पष्ट और अनिश्चित था। मदरसा अधिनियम मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन करने के लिए एक कानून को रद्द करने के लिए, इसे संविधान के प्रावधानों (अनुच्छेदों) को व्यक्त करने के लिए पता लगाया जाना चाहिए।

सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि राज्य मदरसों को नियमित कर सकता है, जब तक विनियमन उचित और तर्कसंगत है। राज्य प्रशासन को संभालने के अपने अधिकारों का उल्लंघन किए बिना अल्पसंख्यक संस्थानों में शिक्षा के पहलुओं को विनियमित कर सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि मदरसा अधिनियम शैक्षणिक संस्थानों को उनके अल्पसंख्यक चरित्र से वंचित किए बिना ऐसा कर सकता है। न्यायालय ने संविधान में समवर्ती सूची की प्रविष्टि 25 का भी उल्लेख किया जो राज्यों और केंद्र दोनों को शिक्षा के विषय पर कानून बनाने की अनुमति देता है। इसमें कहा गया है कि इसको व्यापक अर्थ दिया जाना चाहिए। इसमें धार्मिक शिक्षा प्रदान करने वाले संस्थान शामिल होने चाहिए। सन्

2014 में सर्वोच्च न्यायालय में अनुच्छेद 21 ए की संवैधानिकता को चुनौती दी गई थी। न्यायालय ने कहा कि बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2006 (आरटीई अधिनियम) अल्पसंख्यक संस्थानों पर लागू नहीं होना चाहिए। यह उनके अल्पसंख्यक चरित्र को नष्ट कर सकता है। मदरसा अधिनियम मामले में उच्चतम न्यायालय ने इस निर्णय का उल्लेख किया और कहा कि उच्च न्यायालय ने शिक्षा के अधिकार का उल्लंघन करने के लिए कानून को निरस्त करके गलती की थी। न्यायालय ने यह भी कहा कि मदरसों जैसे अल्पसंख्यक संस्थानों को अनुच्छेद 30 के तहत धार्मिक शिक्षा प्रदान करने और अपना प्रशासन संभालने का अधिकार है।

सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि मदरसा अधिनियम की धारा 9 का एक हिस्सा जो बोर्ड को कामिल और फाजिल पाठ्यक्रम पूरा करने वालों को पाठ्यक्रम लिखने, परीक्षा आयोजित करने और डिग्री देने की अनुमति देता है, यूजीसी अधिनियम के विपरीत है। यूजीसी अधिनियम की धारा 22 के तहत, केवल वे विश्वविद्यालय ही डिग्री प्रदान कर सकते हैं जिन्हें केंद्र या राज्य अधिनियम के तहत स्थापित किया गया है या जिन्हें यूजीसी द्वारा विश्वविद्यालय माना गया है। इसलिए, उच्चतम न्यायालय ने धारा 9 के एक भाग को निरस्त कर दिया।

सर्वोच्च न्यायालय ने अपने ताजा फैसले में मदरसा अधिनियम की वैधता को बरकरार रखते हुए कहा कि यह राज्य के सकारात्मक दायित्व के अनुरूप है। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि मान्यता प्राप्त मदरसों में अध्ययन करने वाले छात्र योग्यता का स्तर प्राप्त करें जो उन्हें समाज में प्रभावी ढंग से भाग लेने और आजीविका कमाने की अनुमति देगा। न्यायालय ने यह भी कहा कि संविधान के अनुच्छेद 21-ए और शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 को धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों के अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन के अधिकार के साथ सुसंगत रूप से पढ़ा जाना चाहिए। राज्य सरकार की मंजूरी से मदरसा शिक्षा बोर्ड यह सुनिश्चित करने के लिए नियम बना सकता है कि धार्मिक अल्पसंख्यक संस्थान अपने अल्पसंख्यक चरित्र को नष्ट किए बिना आवश्यक मानक की धर्मनिरपेक्ष शिक्षा प्रदान करें।

इसके अलावा, मदरसा अधिनियम राज्य विधानमंडल की विधायी क्षमता के भीतर है और सूची तीन की प्रविष्टि 25 तक इसका पता लगाया जा सकता है। लेकिन न्यायालय ने यह भी माना कि मदरसा अधिनियम के प्रावधान जो उच्च शिक्षा की डिग्री को विनियमित करने का प्रयास करते हैं, जैसे कि फाजिल और कामिल असंवैधानिक हैं क्योंकि वे यूजीसी अधिनियम के साथ संघर्ष में हैं। इसे संविधान की सूची प्रथम की प्रविष्टि 66 के तहत अधिनियमित किया गया है। इस फैसले के साथ, तीन न्यायाधीशों की पीठ ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच के फैसले को भी उलट दिया, जिसने मदरसा अधिनियम को धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत, संविधान के अनुच्छेद 14, 21 और 21-ए का उल्लंघन करने और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (यूजीसी अधिनियम) की धारा 22 का उल्लंघन करने के लिए असंवैधानिक घोषित किया था।

(शेष अगले कॉलम में)

दृष्टिकोण

राजेंद्र बज

लेखक स्तंभकार हैं।

अपने आप को सामने वाले की जगह पर रखकर भी सोचिए...

इस संदर्भ में क्या ही बेहतर हो यदि विवादित मुद्दा सामने आने पर आदमी अपने आप को सामने वाले की जगह पर रखकर विचार करें। वैसे यह बात एक परिकल्पना लग सकती है, लेकिन इसका व्यावहारिक महत्व अनुमान से कहीं बहुत ज्यादा होगा। दरअसल अधिकांश विवादों की जड़ में एकतरफा सोच विचार ही वह कारण बन जाता है जब कोई बात तूल पकड़ लेती है। इसके चलते दोनों ही पक्ष मानसिक दबाव की स्थिति में आ जाते हैं। जिसका सीधे तौर पर नतीजा यह होता है कि दोनों ही पक्ष अपने-अपने क्षेत्र में अपनी-अपनी कार्यक्षमता को खोने लगते हैं। समाज में ऐसे अनगिनत लोग होंगे जिनकी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा अंतिम रूप से न्याय पाने की प्रयासों में ही गुजर गया।

सारे जमाने में तमाम तरह के जमाने भर के विवाद है। जिसके चलते परस्पर हिंसा, मनमुटाव और पारिवारिक रंजिश के अनगिनत मामले कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में विचाराधीन है। हालांकि पीड़ित पक्ष को न्याय प्रदान करने की व्यवस्था है, लेकिन वह अपर्याप्त होकर सस्ता एवं सुलभ न्याय प्रदान नहीं कर पाती। अनेक मामले ऐसे हैं जिनमें पीढ़ी-दर-पीढ़ी अंतिम न्याय की प्रतीक्षा करती रहा करती है। नागरिकों का एक वर्ग विलंबित न्याय के दौर में त्वरित न्याय हेतु अनपेक्षित कदम उठाते भी देखा गया है। खैर, अब विवादों को तो जड़ मूल से खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन विवाद कम होने की दिशा में तो कुछ सोचा जा सकता है।

इस संदर्भ में क्या ही बेहतर हो यदि विवादित मुद्दा सामने आने पर आदमी अपने आप को सामने वाले की जगह पर रखकर विचार करें। वैसे यह बात एक परिकल्पना लग सकती है, लेकिन इसका व्यावहारिक महत्व अनुमान से कहीं बहुत ज्यादा होगा। दरअसल अधिकांश विवादों की जड़ में एकतरफा सोच विचार ही वह कारण बन जाता है जब कोई बात तूल पकड़ लेती है। इसके चलते दोनों ही पक्ष मानसिक दबाव की स्थिति में आ जाते हैं। जिसका सीधे तौर पर नतीजा यह होता है कि दोनों ही पक्ष अपने-अपने क्षेत्र में अपनी-अपनी कार्यक्षमता को खोने लगते हैं। समाज में ऐसे अनगिनत लोग होंगे जिनकी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा अंतिम रूप से न्याय पाने की प्रयासों में ही गुजर गया।

ऐसी स्थिति स्वाभाविक रूप से आदमी को अस्थिर मनोवृति की ओर धकेल दिया करती है। इसका प्रभाव सामाजिक परिवेश में नकारात्मक रूप से पड़ता है। जो प्रकारांतर से समाज एवं राष्ट्र के विकास क्रम को बाधित करता है। निश्चित रूप से यदि आदमी अपने सोच विचार को प्रतिद्वंदी की भावना से देखें, तो काफी हद तक विवादों को सुलझ जाने के आसार बनने लग जाते हैं। वर्तमान दौर में तमाम तरह के दीवानी मुकदमे पारिवारिक रिश्तों की मान मर्यादा को दांव पर लगा रहे हैं। ऐसी स्थिति में परस्पर नजदीकी रिश्तों में भी आत्मीयता का भाव विलुप्ति की कगार पर दिखाई देता है। आजकल तो खून के रिश्तों में भी रिश्ता निभाने की गारंटी नहीं मानी जा

सकती।

दरअसल जब दो पक्षों में किसी बात को लेकर विवादित स्थिति बन जाती है, यह निश्चित है कि किसी एक का पक्ष ही सही होगा। या फिर उनके बीच किसी प्रकार की गलतफहमी होगी या वे परस्पर अविश्वास की भावना से भरे होंगे। ऐसी स्थिति में बीते दौर में स्थानीय सर्वमान्य प्रबुद्धजनों के समूह से विवादित स्थिति का निराकरण कराया जाता रहा था। तब न्याय सस्ता एवं सुलभ तो था ही लेकिन त्वरित निर्णय का भी कारण बना करता था। हालांकि उनके कार्यक्षेत्र का भी एक सीमित दायरा था, लेकिन जो भी था वह कारगर था। तब के जमाने में 'आंख की शर्म' पाली जाती थी। प्रतिष्ठितों की प्रतिष्ठा निर्विवाद रहा करती थी। लेकिन बदलते दौर में सब कुछ बदल गया।

इन तमाम सन्दर्भों में आम आदमी को महान धर्मग्रंथ रामायण और महाभारत के तमाम पात्रों की भूमिका पर विचार कर लेना चाहिए। इनका धार्मिक ही नहीं अपितु व्यावहारिक महत्व भी है। हर कोई इन ग्रंथो के प्रमुख पात्रों के चरित्र चित्रण से भलीभांति परिचित है। व्यावहारिक रूप से आदमी के निजी, पारिवारिक एवं सामाजिक जीवन में आने वाली तमाम विकट स्थिति के दौर में आदमी को इन ग्रंथो के प्रमुख पात्रों की भूमिका से बहुत कुछ सीख मिल सकती है। एक पल के लिए आदमी को यह सोच लेना चाहिए कि यदि वह किसी विवाद में उलझा है तो उसके अंतर्मन में कौन सा पात्र स्थापित हो गया है? ऐसे में हम स्वयं अपने आपको पहचानने की मुद्रा में आ जाएंगे। हम स्वयं सही और गलत का निर्णय ले लेंगे। फिर विवाद रह ही कहां जाएगा?

एक पल, केवल और केवल एक पल, एक पल में ही अपनी स्थिति का भान हो जाएगा। निश्चित रूप से जब हम किसी बिंदु पर आत्म स्वीकृति पा लेते हैं, फिर कहीं से कहीं तक विवादित स्थिति आती ही नहीं है।

पर्यावरण

उपेन्द्र शंकर

लेखक सामाजिक कार्यकर्ता हैं।

जलवायु मार्च : केरल को बचाने की कोशिश

केरल में पहला 'जलवायु मार्च' 2015 में आयोजित किया गया था, जब लोगों ने वझाचल से अथिराप्पिल्ली तक मार्च किया था। मार्च के महासचिव रवि ने बताया यह चालक्कुडी 'नदी बेसिन की सुरक्षा के लिए अथिराप्पिल्ली आंदोलन की पृष्ठभूमि में आयोजित किया गया था।' 'वर्ष 2016 से केरल नियमित रूप से चरम जलवायु घटनाओं का सामना कर रहा है। 2016 में, हमारे पास सूखा था, उसके बाद 2018 और 2019 में बाढ़ आई और फिर बड़े पैमाने पर भूस्खलन हुआ। हम ऐसी स्थिति में पहुँच गए हैं जहाँ तत्काल और पर्याप्त जलवायु कार्रवाई की आवश्यकता है। इसी संदर्भ में हमने डॉ. लता की सातवीं पुण्यतिथि को जलवायु मार्च के रूप में आयोजित करने के बारे में सोचा।'

जलवायु संकट से उत्पन्न गंभीर चुनौतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 16 नवंबर 2024 को केरल के वझाचल से अथिराप्पिल्ली तक, पांच किलोमीटर के क्षेत्र में, 'जलवायु मार्च 2024' का आयोजन किया गया। 'पीपुल्स क्लाइमेट एक्शन, केरल' और 'चालाकुडी रिवर प्रोटेक्शन फोरम' के संयुक्त नेतृत्व में इस जलवायु मार्च का आयोजन किया गया था।

16 नवंबर को 'रिवर रिसर्च सेंटर' के संस्थापक और प्रेरक व्यक्तित्व डॉ. लता अनंथा का स्मृति-दिवस भी है। वैज्ञानिक डॉ. लता का, जिन्होंने मुक्त प्रवाह वाली नदियों के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया, 2017 में एक साल से अधिक समय तक कैंसर से जूझने के बाद निधन हो गया। उनकी उज्ज्वल यादों को श्रद्धांजलि देते हुए, डॉ. लता की 7वीं पुण्यतिथि पर ही इस 'जलवायु मार्च' का आयोजन किया गया था।

यात्रा की सुबह करीब 10 बजे विभिन्न कॉलेजों और स्कूलों के छात्र, केरल के विभिन्न हिस्सों से पर्यावरण कार्यकर्ता, कला, सांस्कृतिक, सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता, वैज्ञानिक, शोधकर्ता, मौसम विशेषज्ञ और आम जनता वझाचल पहुंचे और लता स्मृति सभा का आयोजन किया। पर्यावरण कार्यकर्ता और 'नेशनल अलायंस ऑफ पीपुल्स मूवमेंट्स' (एनएपीएम) के राष्ट्रीय संयोजक सीआर नीलकंदन ने समारोह की अध्यक्षता की और 'जलवायु मार्च 2024' के महासचिव एसपी रवि ने स्वागत किया।

केरल में पहला 'जलवायु मार्च' 2015 में आयोजित किया गया था, जब लोगों ने वझाचल से अथिराप्पिल्ली तक मार्च किया था। मार्च के महासचिव रवि ने बताया यह चालक्कुडी 'नदी बेसिन की सुरक्षा के लिए अथिराप्पिल्ली आंदोलन की पृष्ठभूमि में आयोजित किया गया था।' 'वर्ष 2016 से केरल नियमित रूप से चरम जलवायु घटनाओं का सामना कर रहा है। 2016 में, हमारे पास सूखा था, उसके बाद 2018 और 2019 में बाढ़ आई और फिर बड़े पैमाने पर भूस्खलन हुआ। हम ऐसी स्थिति में पहुँच गए हैं जहाँ तत्काल और पर्याप्त जलवायु कार्रवाई की आवश्यकता है। इसी संदर्भ में हमने डॉ. लता की सातवीं पुण्यतिथि को जलवायु मार्च के रूप में आयोजित करने के बारे में सोचा।'

सरकार जलवायु संकट पर हर चीज को दोष देती है, लेकिन शमन के लिए कुछ नहीं करती है। रवि ने कहा, 'सभी आपदाएं अत्यधिक वर्षा या चरम जलवायु घटनाओं के कारण नहीं होती हैं। इन आपदाओं में भूमि उपयोग परिवर्तनों की प्रमुख भूमिका होती है, लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है।' वर्ष 2018 की विनाशकारी बाढ़ कई कारणों से आई थी, जिसमें पश्चिमी घाट में भूमि उपयोग में बदलाव और मध्यभूमि में धान की खेती शामिल है। बांधों ने भी इसमें भूमिका निभाई और आपदा प्रबंधन तंत्र की विफलता भी हुई। रवि ने कहा, 'इन सभी का सम्मिलित प्रभाव बड़े पैमाने पर बाढ़ था, जिसने आपदा की भयावहता को कई गुना बढ़ा दिया। इन सभी पर ध्यान देने की आवश्यकता है। पश्चिमी घाट सबसे अधिक संवेदनशील क्षेत्रों में से एक है।'

पश्चिमी घाट क्षेत्र में तापमान वृद्धि मध्यभूमि से अधिक बताई जाती है और तापमान या वर्षा पैटर्न में एक छोटा सा बदलाव भी जैव-विविधता को बडे स्तर पर प्रभावित कर सकता है। रवि ने कहा, 'केरल पश्चिमी घाट के संरक्षण में है,

इसके बिना केरल, जैसा कि हम जानते हैं, अस्तित्व में नहीं रह सकता, लेकिन दुर्भाग्य से पश्चिमी घाट के इस महत्वपूर्ण महत्व को स्वीकार नहीं किया जाता है।'

तटीय क्षेत्र में कई स्थानों पर लगातार तूफानी लहरें और ज्वारीय बाढ़ देखी जा रही है। 'उच्च जनसंख्या घनत्व वाला पूरा तटीय क्षेत्र बेहद संवेदनशील हो गया है और हम नहीं जानते कि कब कोई बड़ी आपदा आ जाएगी।' केरल में जलवायु कार्यकर्ता चाहते हैं कि उन क्षेत्रों को विशेष महत्व दिया जाए जहां अधिक कार्रवाई की आवश्यकता है। वे यह भी सुनिश्चित करना चाहते हैं कि स्थानीय स्वशासन स्तर से लेकर सभी सरकारी परियोजनाओं की जलवायु संकट के संबंध में जांच की जाए।'

शमन और लचीलापन निर्माण के लिए विशिष्ट गतिविधियों की आवश्यकता है, यह अस्पष्ट नहीं हो सकता और केवल राज्य-स्तरीय कार्य योजना रखने की बजाय, हमें इसे स्थानीय स्तर पर विभाजित करना पड़ सकता है। 'केरल स्थानीय प्रशासन संस्थान' (KILA) ग्राम पंचायतों के लिए जलवायु पर लचीली योजनाएँ विकसित कर रहा है, लेकिन पता नहीं कि इसका कितना हिस्सा जमीनी स्तर पर पहुँचा है,' रवि ने कहा।

स्थानीय निकाय, समुदाय के स्तर पर भागीदारी और युवाओं की भागीदारी इस दृष्टिकोण के लिए बुनियादी हैं। रवि के मुताबिक, 'अभी कई जगहों पर मानसून की बारिश की निगरानी हो रही है, जिसे राज्य की कार्ययोजना में शामिल किया जाना चाहिए और कार्रवाई करते समय इस पर विचार किया जाना चाहिए। युवाओं को इसमें सबसे आगे रहना होगा। इन चीजों को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए। जिस तरह से इसे पढ़ाया जा रहा है, वह ज्यादातर सतही है। हमेशा की तरह चलने वाला परिदृश्य अब संभव नहीं है।'

वर्ष 2022 में केरल ने जलवायु परिवर्तन पर राज्य कार्य योजना को संशोधित किया था, जिसमें ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से अपने कमजोर भौगोलिक क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए कार्रवाई की पहचान की गई थी, लेकिन जलवायु कार्यकर्ताओं को लगता है कि ज़मीन पर पर्याप्त काम नहीं किया जा रहा है।

जलवायु संकट पर जागरूकता पैदा करने और कार्रवाई को गति देने के लिए 'जलवायु मार्च 2024' के आयोजक कम-से-कम 10 वर्षों की अवधि के लिए पूरे राज्य में एक अभियान विकसित करने की योजना बना रहे हैं। यह कार्यक्रम 29 वें 'संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन' ('कॉप29') के साथ भी मेल खाता है, जो इन दिनों (11 से 22 नवंबर2024 तक) अज़रबैजान के बाकू में चल रहा है। (सप्रेस)

भौंरा में आधार सेवाओं का संकट, नागरिकों को उठानी पड़ रही भारी परेशानी

आधार कार्ड बनाने व अपडेट कराने परेशान हो रहे लोग

बैतूल/भौंरा। शहर का आधार केन्द्र बंद है। आधार अपडेट कराने या बनाने के लिए लोगों को शाहपुर या बैतूल जाना पडता है। यहां भी एक दिन में आधार अपडेट या आधार नहीं बनने से लोगों को मायूस लौटना पड़ रहा है। दरअसल भौरा का एकमात्र आधार केंद्र पिछले 6 माह से से बंद पड़ा है। इस वजह से ग्रामीणों को न केवल समय और पैसे की बर्बादी झेलनी पड़ रही है, बल्कि कई सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने से भी वंचित रहना पड़ रहा है। भौरा के आधार केंद्र को 6 माह पहले बंद कर दिया गया, क्योंकि इसके सुपरवाइजर को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया था। आधार केंद्र के अभाव में भौरा और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को आधार कार्ड बनवाने या उसमें सुधार कराने के लिए 10 किमी दूर शाहपुर या 50 किमी दूर बैतूल जाना पड़ता है। वहां की लंबी कतारों और सीमित संसाधनों के कारण कई बार उन्हें बार-बार आना-जाना पड़ता है। इन्हीं आधार केन्द्रों पर शहर के अलावा ग्रामीण क्षेत्र से भी लोग आकर आधार में सुधार करवाते है। जिससे आधार केन्द्रों पर अत्याधिक भीड़ हो रही है और लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालात यह है कि सुबह से ही आधार अपडेट कराने के लिए लोग केन्द्र पर लोग पहुंच जाते है। लोगों ने बताया कि भीड़ की वजह से आधार में सुधार व अन्य काम कराने के लिए पूरा दिन लग जाता है।

आधार केंद्र बंद होने से लौट रहे लोग–ग्राम झापड़ी के सुरेश यादव ने बताया कि वह अपने बच्चों का आधार कार्ड बनवाने के लिए भौरा पहुंचे, लेकिन आधार सेंटर बंद होने के कारण उन्हें शाहपुर जाना पड़ा। बच्चों के स्कूल के लिए आधार कार्ड जरूरी है। लेकिन हर बार इतनी दूरी तय करना और दिन भर कतार में खड़े रहना मुश्किल है। आज भी काम नहीं हो पाया। सोमवार को फिर आना पड़ेगा। इसी तरह ग्राम भौरा की विधा बाई, जो अपना आधार कार्ड मोबाइल नंबर से लिंक कराने के लिए शाहपुर गई थीं, ने बताया हम बुजुर्ग लोग इतनी दूर आ-जा नहीं सकते। भौरा में केंद्र होता तो हमें यह परेशानी नहीं झेलनी पड़ती।

आधार के बिना नहीं मिल रहा योजनाओं का लाभ – भौरा और आसपास के गांवों में आयुष्मान भारत योजना के तहत कार्ड बनाने का कार्य चल रहा है। लेकिन जिन लोगों के आधार कार्ड अपडेट नहीं हैं, वे इस योजना का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। बुजुर्गों और दिव्यांगजनों के लिए आधार अपडेट कराना खासा मुश्किल हो गया है। ग्राम हांडीपानी के सुखराम चौहान ने बताया, आधार कार्ड मोबाइल नंबर से लिंक नहीं है। इसे अपडेट कराने के लिए मुझे तीन बार शाहपुर जाना पड़ा। वहां लंबी कतारों और अधिक भीड़ के कारण हर बार खाली हाथ लौटना पड़ा।

लोगों ने कहा, भौंरा में शुरू किया जाये आधार सेंटर– भौरा और आसपास के गांवों के निवासियों ने प्रशासन से जल्द से जल्द आधार केंद्र को पुन- चालू करने की मांग की है। स्थानीय नागरिक अर्पित तिवारी ने कहा, आधार कार्ड आज के समय में हर सरकारी योजना का आधार है। इसके बिना न तो सरकारी लाभ मिल पा रहा है और न ही अन्य जरूरी काम हो पा रहे हैं। भौरा में आधार सेवाओं की बहाली समय की मांग है। आधार केंद्र के बंद होने के कारण हजारों लोग परेशान हैं। प्रशासन से अपेक्षा है कि वह इस समस्या को प्राथमिकता देकर जल्द समाधान निकाले। ऐसा होने पर न केवल लोगों का आर्थिक और समय का नुकसान रुकेगा, बल्कि सरकारी योजनाओं का लाभ भी आसानी से मिल सकेगा।

सुपरवाइजर को कर दिया था ब्लैकलिस्ट– भौरा और आसपास के गांवों के निवासियों को आधार सेवाओं की अनुपलब्धता के कारण गंभीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आधार केंद्र जल्द से जल्द शुरू हो, ताकि नागरिकों को अनावश्यक परेशानियों से राहत मिल सके। भौरा का आधार केंद्र पिछले छह माह से बंद है क्योंकि इसके सुपरवाइजर को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया था। यह केंद्र पहले प्रोजेक्ट सीएसी के माध्यम से संचालित हो रहा था, जो अब बंद हो चुका है। अब इस परियोजना को जिला ई-गवर्नेंस सोसायटी द्वारा हैंडओवर लिया जा रहा है और आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

इनका कहना -

पुराने आधार केंद्र की आईडी भी बंद हो चुकी है। चूंकि प्रोजेक्ट सीएसी से हटकर इसे ई-गवर्नेंस के अधीन किया गया है, इसलिए संचालन रुका हुआ है। नए केंद्र के लिए फॉर्म जमा कर दिया गया है और जैसे ही ई-गवर्नेंस से स्वीकृति प्राप्त होगी, आधार केंद्र को पुन- चालू कर दिया जाएगा।

– कमलेश रघुवंशी, प्रबंधक, सीएसी बैतूलल

इधर कांग्रेस का दावा – कांग्रेस का संघर्ष रंग लाया, अब निजी हाथों में नहीं जाएगा जिला अस्पताल

बैतूल। पीपीपी मोड पर मेडिकल कालेज बनाने और उसके लिए सरकारी जिला अस्पताल को भी प्राइवेट प्लेयर के हाथ में देने के फैसले पर कांग्रेस ने कहा कि लौट कर कम अक्ल घर पर आए। यह बात कहते हुए जिला कांग्रेस प्रवक्ता मोनू वाघ ने कहा बैतूल जिले में जिला अस्पताल को पीपीपी मोड के मेडिकल कालेज के लिए प्राइवेट सेक्टर के हाथो में दिए जाने का जिला कांग्रेस ने पुरजोर विरोध किया था। उनका कहना है कि जिला कांग्रेस अध्यक्ष हेमंत वागद्रे के नेतृत्व में जिले के कांग्रेसियों ने 8 अगस्त को बरसात में भीगते हुए कलेक्ट्रेट तक रैली निकाल और ज्ञापन देकर इस मामले को आम जनता के बीच लेकर गई थी। इसके बाद भी हर मौके पर इस मुद्दे को उठाया गया। इससे आम जनता में सरकारी अस्पताल के निजी हाथो में जाने का आंतरिक आक्रोश फैल गया। बैतूल सहित अन्य जिलों में भी विरोध शुरू हुआ। इसी का नतीजा है कि सरकार को बैक फुट पर आना पडा और सरकारी अस्पताल को प्राइवेट हाथों में देने का फैसला बदलना पडा। जिला कांग्रेस अध्यक्ष का कहना है कि सरकार यह भी बताएं कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज कब तक अपना स्वयं का अस्पताल बनाएगा और उक्त अस्पताल में आम जनता के निःशुल्क इलाज के लिए कितने बेड उपलब्ध रहेंगे। प्रदेश सरकार के साथ बैतूल के सांसद सहित सभी विधायक जनता को जवाब दे।

विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग आज से प्रारंभ

बैतूल। प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी राष्ट्रीय युवा महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है। इस संबंध में नेहरू युवा केंद्र के जिला युवा अधिकारी मोनिका चौधरी ने बताया कि इस बार का युवा महोत्सव बेहद खास और अलग होगा। इस बार की जो थीम है वह काफी नई और यूनिक है। विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग के थीम पर आधारित चार स्टेज में इस कार्यक्रम का आयोजन होगा जिसमें युवा द्वारा माय भारत पोर्टल पर जाके 25 नवंबर से 5 दिसंबर तक प्रतिभाग किया जा सकता है।15 से 29 वर्ष के युवा इस कार्यक्रम में हिस्सा ले सकते हैं। पहले चरण में विकसित भारत की थीम पर ऑनलाइन क्विज कंपटीशन का आयोजन माय भारत पोर्टल पर होगा। इसमें से चुने गए प्रतिभागी दूसरे चरण में ऑनलाइन निबंध लेखन में भाग लेंगे। तीसरे लेवल पर स्टेट चैंपियनशिप भोपाल में और चौथी और आखिरी चरण में नेशनल चैंपियनशिप नई दिल्ली में माननीय प्रधानमंत्री की मुख्य आतिथ्य में आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा यंग माइंड को अपने देश की संस्कृति, इतिहास और सभ्यता से जोडना होगा और साथ ही साथ युवाओं से संवाद कर उनके विचार को प्रमुखता के साथ राष्ट्रीय स्तर पर साझा करना होगा। विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग राष्ट्रीय युवा महोत्सव के दौरान 11 और 12 जनवरी 2025 को आयोजित होगा। इस दो दिवसीय कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत मंडपम में 3 हजार युवा नेताओं के साथ संवाद करेंगे। इन 3 हजार युवा नेताओं में से 1500 प्रतिभागियों का चयन विकसित भारत चैलेंज के माध्यम से माय भारत प्लेटफ़ॉर्म पर किया जाएगा। राष्ट्रीय युवा महोत्सव विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग का उद्देश्य युवाओं की प्रतिभा को पहचानना और उसे प्रोत्साहित करना है, जिससे उन्हें विकसित भारत के लिए अपने विचार साझा करने का एक मंच मिल सके। धनंजय सिंह ठाकुर ने बताया कि इस आयोजन का मुख्य आकर्षण यह होगा कि युवा सीधे प्रधानमंत्री के साथ संवाद कर सकेंगे और भारत के भविष्य के लिए अपने विचार प्रस्तुत करेंगे, जिससे राजनीति और सामाजिक जीवन में युवाओं की भागीदारी बढ़ेगी।

1 दिसम्बर को होगा दिवाली गोठान महोत्सव

बैतूल। सर्व आदिवासी समाज के तत्वाधान में आदिवासी सामुदायिक मंगल भवन में रविवार 24 नवंबर को बैठक आयोजित की गई। बैठक में 1 दिसंबर 2024 दिन रविवार को जिला स्तरीय दिवाली गोठान सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन करने का निर्णय लिया गया। समाज के अविनाश धुर्वे ने बताया कि जिला मुख्यालय के शिवाजी ऑडिटोरियम में 1 दिसंबर को सुबह 10 से शाम 6 बजे तक दिवाली गोठान महोत्सव में आदिवासी समाज की संस्कृति रीति रिवाज, परंपरा देखने को मिलेगी। दिवाली गोठान महोत्सव में पूरे जिले से गोंड गायकी (ठाठिया) समुदाय के जाने माने 200 से अधिक कलाकार गोठान में गायकी नृत्य की प्रस्तुति देंगे। गोंडी डंडार की लगभग दो दर्जन टीमों के द्वारा शानदार प्रस्तुति दी जाएगी। कोरकू आदिवासी समुदाय की गली नृत्य की टीमें भी महोत्सव में शिरकत करेगी। अंकित कुमरे ने बताया कि दिवाली गोठान सांस्कृतिक महोत्सव की शुरुआत पडापेन ठाना सदर से होगी एवं गोठान महोत्सव का आयोजन रानी दुर्गावती आडिटोरियम में किया जाएगा। विशाल धुर्वे ने बताया कि इस गोठान सांस्कृतिक महोत्सव में बैतूल जिले के अलावा अन्य जिलों के भी आदिवासी समाज के लोग बडी संख्या में पहुचेंगे। कार्यक्रम में सभी के लिए भोजन की व्यवस्था भी गई है। इस बैठक में आकास संगठन जिला अध्यक्ष शंकर सिंह आहके, युआवि संगठन जिलाध्यक्ष जितेंद्र सिंह इवने, अविनाश धुर्वे, अंकित कुमरे, विशाल धुर्वे, अनिल परते, रामदास उइके, उमेश परते,प्रकाश उइके, करण चढोकार सहित अन्य सामाजिक बन्धु उपस्थित थे।

स्कूल न जाने वाली बालिकाएं होती हैं ज्यादा अपराध का शिकार : एएसपी कमला जोशी

बैतूल। सीएम राइस स्कूल बैतूलबाजार में पुलिस विभाग के प्रयास एक कोशिश टीम एवं प्रत्याशा फाउंडेशन ने बालिका जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम का उद्देश्य बालिकाओं को विभिन्न प्रकार के साइबर अपराधों एवं बालिकाओ से जुड़े अपराधों से बचाव व जानकारी दी गई। कार्यक्रम में एएसपी कमला जोशी, शाहपुर एसडीओपी मयंक तिवारी बैतूल बाजार थाना प्रभारी रंजना धुर्वे, यातायात प्रभारी गजेंद्र कैन, साइबर सेल प्रभारी नवीन सोनकर उपस्थित थे। मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद नवांकुर संस्था प्रत्याशा फाउंडेशन से तूलिका पचौरी, निमिषा शुक्ला, प्रमिला धोत्रे, आशीष पचौरी एवं आशीष कोकने, प्रदीपन संस्था की ओर से रेखा गुजरे एवं दीपमाला खातरकर, मीरा एंथोनी, मध्यप्रदेश जन अभियान की ओर से संभाग समन्वयक कौशलेश तिवारी एवं जिला समन्वयक प्रिया चौधरी, महिला बाल विकास अधिकारी गौतम अधिकारी, प्राचार्य श्रीमती साधना हैंड, वन स्टाफ सेंटर से मीरा राजपूत एवं शिक्षक-शिक्षिका उपस्थित थे। इस अवसर पर जिला अभियोजन अधिकारी श्री वर्मा, वंदना शिवहरे, अमित राय द्वारा बालिकाओं को कानूनी जानकारी भी दी गई।

सभी उपस्थित अतिथियों ने बालिकाओं को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से बचने, उनका संभल कर उपयोग करने, मोबाइल फोन के कारण होने वाले विभिन्न फ्रॉड से बचने की नसीहत देते कहा कि बच्चियां अपने साथ होने वाली किसी भी प्रकार की घटना को अपने तक ना रखते हुए अपने माता-पिता, सहेलियों को अवश्य बताएं। इसके अलावा वह अपनी समस्याएं प्रेरणा दीदी, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर अथवा पुलिस को भी बता सकते हैं। कार्यक्रम में स्कूल की बालिकाओं ने जागरूकता पर सुंदर पोस्टर एवं रंगोली बनाई। जिसमें कुमारी प्रेमलता पवार को पोस्टर में विशेष स्थान, भाषण प्रतियोगिता में कुमारी तृप्ति मालवीय एवं कुमारी मिताली, रंगोली प्रतियोगिता में प्रथम द्वितीय एवं तृतीय स्थान पर रहे, जिन्हें प्रशस्ति पत्र भेंट किया गया। मंच संचालन तूलिका पचौरी द्वारा किया गया। कार्यक्रम के अंत में स्कूल प्राचार्य साधना हैंड ने सभी का आभार व्यक्त करते हुए सभी को बाल विवाह रोकने के लिए शपथ दिलाई।

नपा सारणी के वार्ड क्रमांक 33 में कलेक्टर ने शस्त्र लाइसेंस किए निलंबित

बैतूल। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार नगर पालिका उप निर्वाचन-2024 के तहत नगर पालिका परिषद सारनी के लिए आगामी 9 दिसंबर 2024 को मतदान सम्पन्न होना है। इस दौरान आचार संहिता प्रभावशील हो गई है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी ने निर्वाचन के दौरान लोक शांति एवं व्यवस्था बनाये रखने के लिए नगर पालिका परिषद सारनी के वार्ड क्रमांक 33 के अन्तर्गत शस्त्र अनुज्ञप्ति धारियों आग्नेयास्त्रों शस्त्र मतगणना अवधि 12 दिसंबर 2024 तक के लिए निलंबित करने के आदेश जारी किये हैं। यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील हो गया है। कलेक्टर श्री सूर्यवंशी ने शस्त्र अनुज्ञप्ति धारियों को स्वीकृत शस्त्र निकटतम थाने में जमा कराने के आदेश दिए हैं। यह आदेश सुरक्षा एवं निजी प्रतिष्ठानों के पक्ष में स्वीकृत शस्त्र अनुज्ञा पत्र में लागू नहीं होगा। इस आदेश से प्रभावित होने वाले लायसेंस धारकों द्वारा यदि उपरोक्त निलंबन कालावधि में शस्त्र अपने आधिपत्य में रखा जाता है, तो उनके विरूद्ध आयुध अधिनियम 1959 की धारा 25 तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 188 के तहत दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। सारनी थाने में जमा कराएं शस्त्र - जारी आदेश के अनुसार समस्त शस्त्र लायसेंस धारक अपने शस्त्र को तत्काल अपने क्षेत्र के थाने में जमा कराऐंगे। जिले के थाना प्रभारी सारनी को आदेशित किया गया है कि वे नगर पालिका परिषद सारणी के वार्ड क्र. 33 के समस्त शस्त्र लायसेंस धारकों से शस्त्र प्राप्त कर थाने में जमा करें। जमाकर्ता द्वारा शस्त्र लायसेंस धारकों को विधिवत उचित प्राप्ति रसीद दी जाए। उक्त शस्त्र सुरक्षित अभिरक्षा में रखे जाए तथा नगर पालिका उप निर्वाचन 2024 की प्रक्रिया 12 दिसंबर 2024 तक संपन्न होने के पश्चात समस्त शस्त्र संबंधित अनुज्ञप्तिधारियों को बिना किसी आदेश की प्रतीक्षा किए वापस किए जाए। जारी आदेश के अनुसार जिले के समस्त बैंकों, केन्द्र व राज्य शासन के उपक्रमों के अधिकारी, कर्मचारियों, बैंक के सशस्त्र सुरक्षा गार्डों के शस्त्र लायसेंस को छोडकर आयुध अधिनियम 1959 की धारा 17(3) ख में निहित प्रावधानों के अनुसार बैतूल जिले की नगर पालिका परिषद सारनी के वार्ड क्रमांक.33 जहां उप निर्वाचन सम्पन्न होना है के प्रपत्र-3 एवं प्रपत्र 5 में स्वीकृत समस्त शस्त्र लायसेंसों को 12 दिसंबर 2024 तक के लिए निलंबित किया जाता है।

महाराष्ट्र चुनाव में ऐतिहासिक जीत पर आमला के कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न

बैतूल/आमला। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भाजपा की ऐतिहासिक जीत पर कार्यकर्ताओ ने जमकर आतिशबाजी करते हुए एक दूसरे का मुंह मीठा कराया। स्थानीय विधायक डॉ. योगेश पंडाग्रे के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने जनपद चौक आमला पर जश्न मनाया। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भाजपा के ऐतिहासिक प्रदर्शन एवं झारखंड चुनाव समेत अन्य राज्यों में संपन्न उप चुनाव में बेहतर प्रदर्शन पर आमला विधायक डॉ. योगेश पंडाग्रे ने कहा कि महाराष्ट्र चुनाव में मातृशक्ति, युवा साथियों कृषक बंधुओं, बहन-बेटियों और जागरूक मतदाता बंधुओं ने दिखा दिया कि वो भाजपानीत महायुति के विकास के साथ है। ऐतिहासिक परिणाम भाजपा के समर्पित कार्यकर्ता के कठोर परिश्रम एवं भाजपानित महाराष्ट्र सरकार समेत संपूर्ण देश में संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं का प्रतिफल है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव परिणामो से साफ दिखता है की कांग्रेस की झूठ की दुकान और उसके सहयोगियों के भ्रष्टाचार को जनता ने सिरे से नकारा है। ये जनता की जीत है, लोकतंत्र की जीत है, विकास की जीत हैं।

स्वामी रामदेव के शिष्य आएंगे बैतूल

13, 14 और 15 दिसंबर को शिवाजी ओपन ऑडिटोरियम में होगा शिविर

बैतूल। योगऋषि स्वामी रामदेव के मार्गदर्शन में बैतूल में दिसंबर माह में विशाल योग आरोग्य शिविर लगने जा रहा है। इसमें योगपीठ हरिद्वार से स्वामी परमार्थ देव जी उपस्थित रहेंगे। इस शिविर में योग के अलावा आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से सभी बीमारियों का उपचार होगा। यह जानकारी भारत स्वाभिमान न्यास और पतंजलि योग समिति के राज्य प्रमुखव्दय करण सिंह और डॉ.पुष्पांजलि शर्मा ने दी। भोपाल से बैतूल तैयारियों का जायजा लेने आए इन लोगों ने अनुराग टेंट हाउस राजा भोज मार्ग में आज सुबह पंतजलि की जिले भर की टीम की बैठक लेकर जानकारी दी। 24 दिसंबर रविवार सुबह 11 बजे दीप प्रज्ज्वलित कर इस बैठक का शुभारंभ किया गया। इसमें भारत स्वाभिमान न्यास के राज्य प्रभारी करण सिंह, पतंजलि योग समिति की राज्य प्रभारी डा पुष्पांजलि शर्मा, पतंजलि किसान समिति के राज्य प्रभारी कमलेश गौर, भारत स्वाभिमान न्यास के सहराज्य प्रभारी आवठे, युवा भारत के राज्य प्रभारी लखन के अलावा शिविर आयोजन समिति से जुड़े सुनील द्विवेदी, बलराम जसूजा, संजय शुक्ला, दीपक पाल के अलावा भारत स्वाभिमान न्यास के जिला प्रभारी सुनील कुबड़े, विमल दुबे, हितेश पटेल, संगीता अवस्थी, विनोद परिहार आदि शामिल थे। इस बैठक में राज्य के प्रभारियों के अलावा जिले भर के समिति के सदस्य उपस्थित थे। इस बैठक में बताया गया कि आगामी माह के 13, 14 और 15 दिसंबर को तीन दिवसीय योग-आरोग्य शिविर लगेगा। इसमें सुबह 6 बजे से 8 बजे तक पतंजलि योग समिति के केंद्रीय प्रभारी स्वामी डा परमार्थ देव के सानिध्य मार्गदर्शन योग व ध्यान होगा। इसके बाद सुबह 9 बजे से 12 बजे तक फिर दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक आरोग्य शिविर लगेगा। इस आरोग्य शिविर में सभी बीमारियों का उपचार आयुर्वेद, पंचकर्म और प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से तीनों दिन किया जाएगा। इसके अलावा स्वामी जी का स्कूलों में, आठनेर में कार्यक्रम होगा। इस कार्यक्रम में प्रदेश भर से पतंजलि के योग साधक आएंगे। राज्य स्तरीय सम्मेलन भी होगा। इसके साथ ही योग गुरुओं का सम्मान होगा, वहीं योग साधकों और छात्र छात्राओं को हरिद्वार से आए प्रमाणपत्र भी दिए जाएंगे। रविवार की इस बैठक में श्रीमती तरुणा द्विवेदी, रत्नमाला कुबड़े, चंदा भूमरकर अरुणा पाटनकर, रीना इवने मानी सोलंकी, प्रीति साहू, दिनेश, नवनीत वर्मा, राजेश कोडले, बल्लू गुप्ता, संतोष राठौर, गणेश नरवरे, कृष्णराव झरबड़े राजेश पंडोले, बिमल दुबे, नायक, सुनील मेसरे, शिवपाल, सतीश पाल, लिखितकर, पंजाबराव अडलक आदि मौजूद थे।

मेडिकल कॉलेज बनेगा लेकिन पीपीपी मोड पर नहीं जाएगा जिला अस्पताल

बैतूल विधायक ने मुख्यमंत्री–स्वास्थ्य मंत्री का आभार माना

बैतूल। बैतूल विधायक हेमंत खंडेलवाल के विशेष प्रयासों से जिला मुख्यालय बैतूल में स्वीकृत हुए मेडिकल कॉलेज में जिला अस्पताल को भी पीपीपी मोड पर सौंपने का प्रावधान था। मेडिकल कॉलेज की स्थापना के दौरान जिला अस्पताल को पीपीपी मोड पर देने की बजाए उसका स्वरूप यथावत रखने के लिए बैतूल विधायक श्री खण्डेलवाल द्वारा म.प्र.के मुख्यमंत्री एवं उपमुख्यमंत्री - स्वास्थ्य मंत्री से भेंट कर मांग की गई थी। आखिरकार बैतूल विधायक के प्रयास रंग लाए। बैतूल में मेडिकल कॉलेज की स्थापना तो होगी, लेकिन बैतूल जिला अस्पताल पीपीपी मोड पर नहीं जाएगा उसका स्वरूप यथावत रहेगा। शनिवार को मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव की अध्यक्षता और डिप्टी सीएम स्वास्थ्य- चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉ.राजेन्द्र शुक्ल, बैतूल विधायक हेमंत खंडेलवाल, सीएस अनुराज जैन की

मौजूदगी में आयोजित उच्चस्तरीय बैठक में बैतूल सहित प्रदेश के 12 सरकारी जिला अस्पतालों को पीपीपी मोड पर मेडीकल कॉलेज बनाने के संबंध में यह निर्णय लिया गया कि जिला अस्पतालों को पीपीपी मोड पर न सौपंकर केवल टीचिंग और प्रैक्टिस के लिए उपलब्ध कराया जाएगा । उक्त निर्णय के लिए बैतूल विधायक हेमंत खण्डेलवाल ने मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव एवं उपमुख्यमंत्री ,स्वास्थ्य - चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉ.राजेन्द्र शुक्ल को धन्यवाद ज्ञापित कर आभार माना। उल्लेखनीय है कि मध्यप्रदेश सरकार द्वारा बैतूल सहित म.प्र के 12 सरकारी जिला अस्पतालों को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर मेडिकल कॉलेज बनाने की घोषणा करने के बाद जिला प्रशासन एवं स्वास्थ्य

बैतूल विधायक हेमंत खंडेलवाल

विभाग द्वारा कार्यवाही शुरु कर दी थी। मेडिकल कॉलेज निर्माण के लिए बैतूल सहित अन्य जिलों में भूमि भी आवंटित कर दी गई थी। पीपीपी मोड पर मेडिकल कॉलेज स्थापना के प्रोजेक्ट में जिला अस्पताल को पीपीपी मोड पर देनें का प्रावधान था। मेडिकल कॉलेज की स्थापना के दौरान बैतूल जिला अस्पताल को पीपीपी मोड से मुक्त रखने के लिए जिलेवासियों द्वारा बैतूल विधायक श्री खण्डेलवाल से लगातार मांग की जा रही थी। जिसे गंभीरता से लेकर बैतूल विधायक नें मुख्यमंत्री एवं स्वास्थ मंत्री से पत्राचार एवं व्यक्तिगत भेंट कर जिला अस्पताल के स्वरूप को यथावत रखने के संबंध में तथ्यात्मक जानकारी से अवगत कराकर पीपीपी मोड से मुक्त रखने की मॉग ही। परिणामस्वरूप मुख्यमंत्री की अध्यक्षता एवं उपमुख्यमंत्री, स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा मंत्री, बैतूल विधायक तथा मुख्य सचिव की मौजूदगी में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में निर्णय लिया गया कि मेडीकल कॉलेज की स्थापना के दौरान जिला अस्पताल को पीपीपी मोड से मुक्त रखा जाएगा। इस निर्णय के लिए बैतूल विधायक ने जिलेवासियों की ओर से मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव एवं उपमुख्यमंत्री-स्वास्थमंत्री डॉ.राजेन्द्र शुक्ल का धन्यवाद ज्ञापित किया है।

महाराष्ट्र चुनाव

डॉ. राजेन्द्र प्रसाद शर्मा

लेखक स्तंभकार हैं।

महिला मतदाता बदल रही चुनावी तस्वीर

मध्यप्रदेश से निकली लाड़ली बहना महाराष्ट्र तक आते-आते माझी लाड़की बहना योजना ने महाराष्ट्र सरकार द्वारा इसी साल लागू करने और चुनाव से पहले ही तीन किश्तें लक्षित महिलाओं के खातों में जाने से पूरा माहौल ही बदल गया। योजना शुरु करने पर विपक्ष ने विरोध किया और यहां तक कि कोर्ट में जनहित याचिकाएं लगाई गई पर कोर्ट द्वारा योजना को सही ठहराने और सीधे खाते में पैसे आने से महिलाओं में सरकार के प्रति विश्वास जगा वहीं महाअघाड़ी गठबंधन महिलाओं से जुड़ी इस योजना को समझने में ही देरी कर दी और भले ही बाद में चुनाव घोषणा पत्र या यों कहे कि चुनावी वादों में अधिक पैसा देने का वादा भी किया पर महिलाओं का विष्वास नहीं जीत पाएं। परिणाम सामने हैं जो मिल रहा है वह बढ़कर मिलेगा इस पर महिलाओं ने अधिक विश्वास जताया। सही मायने में देखा जाए तो महिला शक्ति गेम चेंजर बन कर सामने आई। कहा तो यहां तक जाने लगा है कि महिलाएं जिनके साथ है सत्ता भी उनके हाथ ही लगेगी।

महाराष्ट्र विधान सभा के चुनावों ने एक बार फिर यह सिद्ध कर दिया है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में चुनावी नतीजों को बदलने में महिलाओं की प्रमुख भूमिका हो गई है। महाराष्ट्र विधानसभा के चुनावों में महिलाओं के 6 प्रतिशत अधिक मतदान ने चुनावी परिणामों को ही पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। इसी साल की शुरुआत में हुए लोकसभा के चुनाव परिणामों से महाराष्ट्र में कांग्रेस नीत महाअघाड़ी गठबंधन अतिउत्साह में था और लगभग यह मानकर ही चल रहे थे कि महाराष्ट्र के चुनाव नतीजे उनके पक्ष में ही होंगे। अत्यधिक आत्मविश्वास के चलते चुनावी अभियान को सही दिशा व समझ नहीं बैठा पाएं और इसका परिणाम यह रहा कि भाजपा नीत गठबंधन ने विजय के सारे रेकार्ड तोड़ दिए। माने या ना माने पर इसमें कोई दो राय नहीं कि चुनावी नतीजों को बदलने में महिलाओं की प्रमुख भूमिका रही।

मध्यप्रदेश से निकली लाड़ली बहना महाराष्ट्र तक आते आते माझी लाड़की बहना योजना ने महाराष्ट्र सरकार द्वारा इसी साल लागू करने और चुनाव से पहले ही तीन किश्तें लक्षित महिलाओं के खातों में जाने से पूरा माहौल ही बदल गया। योजना शुरु करने पर विपक्ष ने विरोध किया और यहां तक कि कोर्ट में जनहित याचिकाएं लगाई गई पर कोर्ट द्वारा योजना को सही ठहराने और सीधे खाते में पैसे आने से महिलाओं में सरकार के प्रति विश्वास जगा वहीं महाअघाड़ी गठबंधन महिलाओं से जुड़ी इस योजना को समझने में ही देरी कर दी और भले ही बाद में चुनाव घोषणा पत्र या यों कहे कि चुनावी वादों में अधिक पैसा देने का वादा भी किया पर महिलाओं का विष्वास नहीं जीत पाएं। परिणाम सामने हैं जो मिल रहा है वह बढ़कर मिलेगा इस पर महिलाओं ने अधिक विश्वास जताया। सही मायने में देखा जाए तो महिला शक्ति गेम चेंजर बन कर सामने आई। कहा तो यहां तक जाने लगा है कि महिलाएं जिनके साथ है सत्ता भी उनके हाथ ही लगेगी।

विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत में चुनावों में महिलाओं की बढ़ती सक्रिय भागीदारी तारीफे काबिल है।

गत चुनावों चाहे वे लोकसभा के हों या राज्यों की विधानसभाओं के देश की महिला वोटरों ने नई सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मजे की बात यह भी है कि चुनाव में पुरुष मतदाताओं की तुलना में महिला मतदाताओं ने अधिक मुखर होकर मतदान किया है। अब तो यह माना जाने लगा है कि देश के एक दर्जन के करीब राज्यों में महिलाओं के वोट ही नई सरकार के गठन में बड़ी भूमिका निभाने लगे हैं। तस्वीर का सकारात्मक पक्ष यह भी है कि मतदान ही नहीं चुनावों में सक्रियता से हिस्सा लेने और चुनावों में उम्मीद्वारी जताने में भी महिलाएं आगे आई हैं। देश के पहले और दूसरे लोकसभा के आमचुनावों में जहां 22 महिला सांसद चुन कर आई थी वहीं गत 2024 के आमचुनाव में 74 महिला सांसद चुन कर आई। हांलाकि आधी आबादी को मुख्य धारा में लाने के लिए राजनीतिक दलों द्वारा नए नए सब्जबाग दिखाने के बावजूद टिकट वितरण के समय महिलाओं की हिस्सेदारी कम ही रह जाती है। अनुभव तो यही बताता है कि किसी भी राजनीतिक दल द्वारा आधी तो दूर की बात एक तिहाई सीटों पर भी महिलाओं को टिकट नहीं दिए जाते है। इस बार महाराष्ट्र चुनावों में 50 महिलाओं को टिकट दिए गए और 21 महिलाएं चुनाव जीत कर विधायक बनी है।

सबसे अच्छी बात यह है कि गॉव हो या शहर महिलाएं अब घर की चार दीवारी में कैद रहने वाली या पुरुष के कहे अनुसार मतदान करने वाली नहीं रही है। पुरुषों के हां में हां मिलाने वाली स्थिति से बहुत बाहर आ चुकी है आज देश की महिलाएं। संपूर्ण चुनाव प्रक्रिया में महिलाएं सक्रियता से हिस्सा लेने लगी हैं। चुनावों में उम्मीद्वारी भी जताती है तो चुनाव केंपेन के दौरान अपनी उपस्थिति भी दर्ज कराती है। दूसरी और मतदान में भी आगे आकर हिस्सा लेने लगी है। देखा जाए तो महिलाओं ने जिस दल पर अधिक भरोसा जताया या यों कहे कि जिस दल को अधिक मत दिए उसी दल की सरकार बनी। मजे की बात यह है कि अब सभी राजनीतिक दल महिला मतदाताओं को अपने पक्ष में लाने के हर संभव प्रयास में जुटे हैं। यही कारण है कि महिलाओं को लुभाने वाली योजनाएं और कार्यक्रम ना केवल घोषित किये जा रहे हैं अपितु राजनीतिक दलों के आने वाले चुनाव घोषणा पत्रों में महिला मतदाताओं को लुभाने के हर संभव प्रयास किए जाते हैं। क्योंकि एक बात साफ हो चुकी है कि आज की महिला स्वयं निर्णय लेने में सक्षम है और उसकों दबाव या अन्य तरीके से प्रभावित नहीं किया जा सकता। कम से कम चुनावों के परिणाम तो इसी और इंगित कर रहे हैं। मजे की बात यह है कि माझी लड़की बहना योजना में 2.50 लाख आय वाली 18 से 60 साल की महिलाओं को इस योजना से जोड़ा गया। इससे यह साफ हो जाता है कि यह वर्ग कमजोर आर्थिक आय वाली महिलाओं का है। यहां साफ हो जाता है कि महिलाओं का यह वर्ग वो वर्ग है जिसके बारें में यह माना जाता है कि इस वर्ग में महिलाएं पुरुषों के निर्णयों पर अधिक निर्भर होती है पर महाराष्ट्र और अन्य प्रदेशों के चुनावी नतीजों से यह साफ हो गया है कि महिलाएं पुरुषों की हां में हां ना मिलाकर स्वयं निर्णय लेने लगी है और उसीसे ताजा नतीजें रुबरु कराते हैं।

खैर यह अलग बात है, पर यह साफ हो चुका है कि देश के लोकतंत्र के इस महापर्व में महिलाएं अग्रणी भूमिका निभा रही है। अब महिला मतदाताओं को कमतर नहीं आंका जा सकता। महिला सशक्तिकरण की दिषा में भी इसे शुभ संकेत माना जा सकता है। इसे देश और लोकतंत्र दोनों के लिए ही सकारात्मक प्रयास कहा जा सकता है तो दूसरी और दुनिया के देशों के लिए भी भारत की महिलाएं एक मिसाल बन कर सामने आ रही हैं। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए कि भविष्य के चुनावों में भी राजनीतिक दलों को सत्ता का स्वाद चखना है तो निगाहें महिला मतदाताओं की और रखनी ही होगी।

9 पुलिस अधीक्षकों के तबादले, इंदौर एसीपी नंदिनी शर्मा होंगी ईओडब्ल्यू में डीएसपी

भोपाल (नप्र)। राज्य शासन ने शनिवार रात नौ पुलिस अधीक्षकों के स्थानांतरण कर दिए हैं। इनमें एसीपी इंदौर नंदिनी शर्मा को डीएसपी, ईओडब्ल्यू इंदौर बनाया गया है। इसी तरह, दिनेश कुमार प्रजापति को पुलिस मुख्यालय भोपाल से एसडीओपी, सीतामऊ मंदसौर पदस्थ किया गया है।

निकिता सिंह मंदसौर में एसडीओपी- विश्वदीप सिंह को सहायक सेनानी प्रथम वाहिनी बिसबल इंदौर से एसडीओपी सरदारपुर धार बनाया गया है। इसके अलावा, शिवेन्दु जोशी को एसीपी आसूचना इंदौर से एसीपी अन्नपूर्णा इंदौर की जिम्मेदारी सौंपी गई है। निकिता सिंह को एसडीओपी मंदसौर से डीएसपी महिला सुरक्षा नीमच नियुक्त किया गया है। किशोर पाटनवाला को डीएसपी सीआइडी पुलिस मुख्यालय भोपाल से डीएसपी रतलाम के रूप में तैनात किया गया है।

आशुतोष पटेल को इंदौर की जिम्मेदारी- आशुतोष पटेल को एसडीओपी धार से एसीपी अपराध इंदौर की जिम्मेदारी दी गई है। इंद्रजीत सिंह चावड़ा को सहायक सेनानी राजभवन सुरक्षा से डीएसपी पुलिस मुख्यालय भोपाल नियुक्त किया गया। अभिलाष कुमार भलावी को एसडीओपी रतलाम से सहायक सेनानी राजभवन सुरक्षा पदस्थ किया गया है।

पत्नी ने अपने जीजा के साथ मिलकर की अपने पति की हत्या, 2 आरोपी गिरफ्तार

देवास/मोहन वर्मा। पीपलरावाँ थानांतर्गत बालोन में एक महिला द्वारा कथित रूप से घरेलू हिंसा से तंग आकर अपने जीजा के साथ मिलकर अपने पति की हत्या करवाने का मामला सामने आया है। पुलिस अधीक्षक पुनीत गेहलोद द्वारा आज प्रेस वार्ता में दी गई जानकारी के अनुसार 21.11.2024 को सुबह चौकी प्रभारी बालोन श्री हिमांशु पाण्डे को ग्राम मुण्डला के चौकीदार से सूचना प्राप्त हुई कि दिनांक 20.11.2024 की रात्री 10.00 बजे के करीब लोकेन्द्रसिंह पिता अन्तरसिंह राजपूत उम्र 25 साल निवासी ग्राम मुण्डला दांगी का खेत पर अकेला पानी फेरने के लिये गया था। सुबह 04.00 बजे तक नही आया तो लोकेन्द्र सिंह की माँ भंवरबाई ने अपने पडोसी रिश्तेदार धनसिंह को बुलाया और बताया की लोकेन्द्रसिंह अभी तक घर पर नही आया है मोबाईल भी बन्द आ रहा है। भंवरबाई एवं धनसिंह राजपूत दोनों खेत पर गये देखा कि लाखन सिंह राजपूत के खेत में लोकेन्द्रसिंह की लाश पडी हुई थी जिसके गले में चोट के निशान थे। उक्त सूचना पर थाना प्रभारी पीपलरवां श्री कमल सिंह गेहलोत एवं चौकी प्रभारी बालोन तत्काल मय फोर्स के घटना स्थल पर पहुंचे एवं घटना स्थल का सुक्ष्मता से निरीक्षण किया गया एवं उक्त गंभीर घटना की जानकारी तत्काल वरिष्ठ अधिकारियो को दी गई। जिस पर थाना पीपलरवाँ में अज्ञात आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 416/2024 धारा 103 (1) बीएनएस का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

पीएम मोदी के करिश्माई नेतृत्व से भाजपा से जुड़ रही जनता, और मजबूत हो रहा संगठन : विष्णुदत्त शर्मा

अपार उत्साह के साथ भाजपा संगठन से जुड़ रहे कार्यकर्ता, 85 प्रतिशत बूथ समिति गठित, भाजपा को चुनावों में ऐतिहासिक विजय दिलाने में बूथ समितियों की महती भूमिका

भोपाल (नप्र)। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एवं खजुराहो सांसद श्री विष्णुदत्त शर्मा ने भोपाल व जबलपुर, प्रदेश संगठन महामंत्री श्री हितानंद जी ने गुना जिले के राघौगढ़ विधानसभा के बूथ क्रमांक 100 ग्राव आंवन के नवनिर्वाचित बूथ अध्यक्ष हीरालाल लोधा का शॉल श्रीफल एवं साफा बांधकर सम्मान कर अभिनंदन यात्रा में शामिल हुए। वहीं प्रदेश शासन के मंत्री, पार्टी पदाधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों ने प्रदेश भर में नवनिर्वाचित बूथ अध्यक्षों व बूथ समिति के सदस्यों का सम्मान किया। प्रदेश के जिलों में घोड़े, हाथी, बग्घी पर बैठाकर नवनिर्वाचित बूथ अध्यक्षों की सम्मान यात्राएं भी निकाली गई हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष व सांसद श्री विष्णुदत्त शर्मा ने जबलपुर उत्तर विधानसभा के विवेकानंद मंडल के 22 बूथों के बूथ समिति की बैठक में शामिल होकर नवनिर्वाचित अध्यक्षों व बूथ समिति के सदस्यों को सम्मानित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के करिश्माई नेतृत्व से बड़ी संख्या में देश की जनता भाजपा के साथ जुड़ रही है और भाजपा संगठन और मजबूत हो रहा है। अपार उत्साह के साथ भाजपा संगठन से कार्यकर्ता जुड़ रहे हैं। प्रदेश में 85 प्रतिशत बूथ समितियों का गठन पूरा हो चुका है। मध्यप्रदेश में पिछले विधानसभा चुनाव व इस साल हुए लोकसभा सहित समय-समय पर होने वाले अन्य चुनावों में पार्टी को ऐतिहासिक विजय दिलाने में बूथ समितियों की महती

भूमिका होती है। कार्यक्रम में प्रदेश शासन के मंत्री श्री तुलसी सिलावट, महानगर अध्यक्ष श्री प्रभात साहू, विधायक श्री अभिलाष पांडेय, पार्टी के प्रदेश कोषाध्यक्ष श्री अखिलेश जैन एवं पूर्व मंत्री श्री अंचल सोनकर सहित पार्टी पदाधिकारी उपस्थित रहे।

मोदी जी के नेतृत्व में देश प्रगति के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा–भाजपा प्रदेश अध्यक्ष व सांसद श्री विष्णुदत्त शर्मा ने कहा कि बूथ संगठन पर्व के तहत प्रदेश में बूथ समितियों का गठन किया जा रहा है। लगातार बूथ अध्यक्षों की नियुक्तियां हो रही हैं। प्रदेश में अब तक लगभग 85 प्रतिशत बूथ समितियों का गठन पूर्ण हो चुका है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में देश प्रगति के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। जनता की अपेक्षाओं और आकांक्षाओं को बल मिला है, जिसके फलस्वरूप देशभर में बड़ी संख्या में लोग भाजपा से जुड़कर संगठन को और मजबूत कर रहे हैं। बूथ समितियों के गठन के बाद मंडल और जिला कार्यसमितियों के चुनाव संपन्न होंगे।

बूथ अध्यक्ष व बूथ समिति भाजपा संगठन की सबसे अहम कड़ी– भाजपा प्रदेश अध्यक्ष व सांसद श्री विष्णुदत्त शर्मा ने भोपाल मध्य विधानसभा के बूथ क्रमांक 192 के नवनिर्वाचित बूथ अध्यक्ष श्री अभिषेक मिश्रा का स्वागत कर अभिनंदन किया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री शर्मा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी कैडरबेस ऑर्गनाईजेशन है।

यह कार्यकर्ता आधारित दल है। भाजपा बूथ जीता चुनाव जीता जैसे अभियान चलाकर प्रदेश के सभी बूथों को मजबूत करने का कार्य किया है। प्रदेश में बूथ स्तर पर पार्टी संगठन की मजबूत स्थिति से ही पिछले वर्ष विधानसभा और इस साल प्रदेश की सभी 29 लोकसभा चुनाव में मिली ऐतिहासिक विजय पार्टी को मिली है। हमारा बूथ जितना मजबूत होगा, संगठन भी उतना मजबूत होगा और चुनावों में विजय भी ऐतिहासिक होगी। इसलिए आप सभी नवनिर्वाचित बूथ अध्यक्ष व बूथ समिति के सदस्य पार्टी संगठन को और मजबूती देने के लिए कार्य करें।

भोपाल में एमडी ड्रग्स की तस्करी करने वाले 2 अरेस्ट

- **2 लाख रुपए की 19.7 ग्राम ड्रग्स जब्त; बेचने की फिराक में घूम रहे थे**

भोपाल (नप्र)। भोपाल क्राइम ब्रांच ने एमडी ड्रग्स की तस्करी करने वाले 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 2 लाख रुपए कीमत की 19.7 ग्राम एमडी ड्रग्स जब्त की गई है। एसीपी मुख्तार कुरैशी ने बताया कि, क्राइम ब्रांच को सूचना मिली थी कि एमपी नगर स्थित यश बैंक के सामने ग्राउंड पर मौजूद दो युवक मादक पदार्थ बेचने की फिराक में हैं। दोनों युवकों को हुलिया बताते हुए जानकारी दी गई कि, उनके पास बड़ी मात्रा में एमडी ड्रग्स हो सकती है। सूचना मिलते ही तत्काल पुलिस की एक टीम घटनास्थल के लिए रवाना की गई। टीम ने बताए गए हुलिए के दो युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उन्होंने अपने नाम साजिद खान उर्फ किट्टू (24) निवासी जावरा फाटक जिला रतलाम और नवेद अली (29) निवासी बोरबन स्कूल के पीछे सीआई कालोनी थाना जहांगीराबाद भोपाल बताया।

तलाशी में बरामद हुआ मादक पदार्थ– दोनों युवकों की तलाशी लेने पर उनके पास सफेद रंग की एयरटाइट पन्नी मिली, जिसके अंदर मटमैला दानेदार पदार्थ रखा था। तस्दीक करने पर यह पदार्थ एमडी ड्रग्स निकला, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया। जब्त हुए मादक पदार्थ का वजन 19.7 ग्राम और कीमत 2 लाख रुपए बताई गई है। आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है।

2300 से ज्यादा धावकों ने लगाई उत्साह की मैराथन दौड़

देवास/मोहन वर्मा । शहर में रविवार सुबह हुई मैराथन में गुलाबी ठंड के बाबजूद हजारों धावकों ने उत्साह की दौड़ लगाई। एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्री के तत्वावधान और बेअरलॉकर एडिटिवस उद्योग के सहयोग से हुई इस मैराथन दौड़ में 2300 से अधिक धावकों ने दौड़ लगाई जिसमें इंदौर उज्जैन महू से लेकर मंदसौर तक के खिलाडी शामिल रहे। दस और पांच किलोमीटर के इस मैराथन में प्रशासन,नगर निगम, उद्योग, खेल संगठन और मीडिया की सराहनीय भागीदारी रही। मैराथन में शामिल होने छोटे बच्चों से लेकर उम्रदराज महिला पुरुषों का उत्साह देखते ही बनता था। खुद जिलाधीश ऋषव गुप्ता और पंचायत सीईओ हिमांशु प्रजापति ने पांच किलोमीटर की दौड़ में भाग लेकर

प्रतिभागियों का उत्साह बढ़ाया वहीं बेअरलॉकर उद्योग के इन्डिया ऑपरेशन हेड हितेश कंवर ने भी 10 किलोमीटर के दौड़ में उत्साह से भाग लिया। कार्यक्रम में विजेताओं को पुरस्कृत करते हुए जिलाधीश ऋषव गुप्ता ने सभी प्रतिभागियों से कहा, हार जीत से ज्यादा महत्व ऐसे आयोजनों में भाग लेना होता है जो खुद में तो उत्साहपूर्ण का संचार करता ही है दूसरों को भी प्रेरित करता है।

दीपावली पर नेत्र प्रत्यारोपण से एम्स भोपाल ने लौटाई दो व्यक्तियों की आँखों की रोशनी

भोपाल। एम्स भोपाल के कार्यपालक निदेशक प्रो. (डॉ.) अजय सिंह के मार्गदर्शन में एम्स भोपाल में इस दीपावली, नेत्र प्रत्यारोपण के माध्यम से दो मरीजों को उनकी आँखों की खोई हुई रोशनी लौटाई गई। यह उपलब्धि एम्स भोपाल के नेत्र रोग विभाग की टीम की मेहनत और नेत्रदान के प्रति समाज की जागरूकता का परिणाम है। प्रो. सिंह ने इस सफलता पर खुशी जताते हुए कहा, च्च्दीपावली अंधकार पर प्रकाश की विजय का प्रतीक है, और इस पावन अवसर पर नेत्र ज्योति से बड़ा कोई उपहार नहीं हो सकता। दीपावली के अवसर पर जहाँ लोग अपने परिवारजनों के साथ समय बिताते है, वही हमारे डॉक्टरों ने अपने सपर्पण और त्याग का परिचय देते हुए इन मरीजों का नेत्र प्रत्यारोपण कर उनकी आँखों के साथ जीवन को भी रोशन किया। इन सफल सर्जरी ने यह दिखाया है कि नेत्रदान का कितना बड़ा महत्व है। मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि समाज में नेत्रदान को प्रोत्साहित करें ताकि जरूरतमंदों को रोशनी मिल सके। डॉ. प्रीति सिंह और उनकी टीम ने दीपावली के दौरान यह सफल नेत्र प्रत्यारोपण किया। पहली मरीज, 28 वर्षीय युवती, बचपन से आंख की चोट के

कारण एक आंख से देख नहीं पाती थी। दूसरे मरीज 50 वर्षीय पुरुष थे, जिनकी आंख में संक्रमण के कारण रोशनी चली गई थी। ये दोनों कई जगह इलाज के लिए गए लेकिन नेत्र प्रत्यारोपण नहीं हो सका। एम्स भोपाल में उनकी सूची बनाई गई और जैसे ही नेत्र बैंक में आंखें उपलब्ध हुई, टीम ने तेजी से सभी आवश्यक प्रबंध कर उनके प्रत्यारोपण को सफल बनाया। दोनों मरीज अब स्वस्थ हैं और उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। उन्होंने एम्स भोपाल और डॉक्टरों की टीम का दिल से धन्यवाद किया। यह सफलता न केवल एम्स भोपाल की उत्कृष्ट चिकित्सा सेवाओं को प्रदर्शित करती है, बल्कि नेत्रदान के महत्व पर एक महत्वपूर्ण संदेश भी देती है।

कौशल विकास के लिए बेसिक एवं एडवांस्ड हिस्टेरोस्कोपी कार्यशाला का आयोजन

भोपाल (नप्र)। एम्स भोपाल के कार्यपालक निदेशक प्रो. (डॉ.) अजयसिंह के मार्गदर्शन में प्रसूति और स्त्री रोग विभाग द्वारा बेसिक एवं एडवांस्ड हिस्टेरोस्कोपी पर एक कार्यशाला आयोजित की गई, जिसका उद्देश्य मिनिमली इनवेसिव सर्जरी (छोटे चीरे द्वारा सर्जरी) में कौशल को बढ़ावा देना था।इस कार्यशाला में क्षेत्र के प्रमुख विशेषज्ञों और प्रतिभागियों ने हिस्टेरोस्कोपी के सिद्धांतों, तकनीकों और व्यावहारिक अनुप्रयोगों पर गहन जानकारी प्राप्त किया। प्रो. सिंह ने इस कार्यक्रम के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा, हिस्टेरोस्कोपी आधुनिक स्त्री रोग विज्ञान में एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, और इस तरह की कार्यशालाओं के माध्यम से हम स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों को आवश्यक विशेषज्ञता प्रदान करने का प्रयास कर रहे हैं। हिस्टेरोस्कोपी,

गर्भाशय की समस्याओं का निदान और इलाज करने के लिए की जाने वाली एक चिकित्सा प्रक्रिया है, जिसमे एक पतली रोशनी वाली ट्यूब गर्भाशय में डाला जाता है। इस ट्यूब में एक कैमरा होता है, जिससे डॉक्टर गर्भाशय को करीब से देख सकते हैं। हिस्टेरोस्कोपी के ज़रिए, गर्भाशय के अंदर की जांच की जाती है और असामान्यताओं का पता लगाया जाता है। इस कार्यशाला का आयोजन विभागाध्यक्ष प्रो. (डॉ.) के. पुष्पलता की देखरेख में किया गया।कार्यशाला की शुरुआत डॉ. भारती सिंह की 'हिस्टेरोस्कोपी बेसिक्स और उपकरण' पर व्याख्यान से हुई, जिसने सफल प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक उपकरणों और तकनीकों को समझने के लिए एक मजबूत आधार प्रदान किया। कार्यशाला का एक प्रमुख आकर्षण ऑपरेटिंग थिएटर से डायग्नोस्टिक और ऑपरेटिव हिस्टेरोस्कोपी के मामलों का लाइव ट्रांसमिशन था, जिसमें डॉ. मिलिंद तेलंग, डॉ. भारती सिंह, डॉ. अरुण डोरा और डॉ. अवंतिका गुप्ता की विशेषज्ञ टीम ने रियल टाइम में मामलों का प्रबंधन किया।सहायक एनेस्थीसिया टीम में डॉ. ज़ैनब और डॉ. हरीश शामिल थे। कार्यशाला के दौरान डॉ. मिलिंद तेलंग ने 'ऑफिस हिस्टेरोस्कोपी (सी एंड ट्रीट)' पर अपना व्याख्यान दिया, जिसमें उन्होंने कार्यालय-आधारित हिस्टेरोस्कोपी की तकनीकों पर महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। इसके बाद, डॉ. अजय हल्दर ने 'हिस्टेरोस्कोपी में फ्लूड प्रबंधन और इलेक्ट्रो सर्जरी के सिद्धांत' पर मार्गदर्शन दिया। डॉ. अरुण डोरा ने हिस्टेरोस्कोपी की जटिलताओं की विस्तृत व्याख्या की और डॉ. नीतू मिश्रा ने इसकी नवीनतम प्रगति पर चर्चा की। कार्यशाला का समापन प्रश्नोत्तर सत्र से हुआ, जिसके बाद सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए। प्रतिभागियों ने स्किल लैब में हिस्टेरो ट्रेनर्स और सिमुलेटर्स का उपयोग करते हुए हैंड्स-ऑन प्रशिक्षण लिया।

गियर बदलते ही अनियंत्रित होकर पलटा ऑटो रिक्शा, सास-बहू की मौत

राजगढ़ (नप्र)। जिला मुख्यालय पर शनिवार को एक ऑटो रिक्शा अनियंत्रित होकर पलट गया। इस हादसे में ऑटो रिक्शा में सवार सास-बहू की मौत हो गई। यह परिवार खिलचीपुर में बड़े और छोटे महाराज का दर्शन कर लौट रहा था, तभी आरोग्य अस्पताल के पास यह हादसा हो गया। पुलिस ने मर्ग कायम कर हादसे की जांच शुरू कर दी हे। ब्यावरा के सुठालिया रोड रविशंकर नगर में रहने वाला साहू परिवार शनिवार सुबह बड़े व छोटे महाराज के दर्शन करने के लिए खिलचीपुर गए थे। परिवार के घनश्याम साहू (35) ने बताया कि खिलचीपुर पहुंचकर मां रमाबाई (60) पत्नी सोनूबाई (30) के साथ दर्शन किए। इसके बाद करीब 11 बजे बाद वह ब्यावरा लौटने के लिए ऑटो रिक्शा में सवार होकर निकले थे।

पन्ना टाइगर रिजर्व में दिखे चार शावक

पन्ना (नप्र)। पन्ना टाइगर रिजर्व में बढ़ती बाघों की संख्या पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। रविवार को बाघिन पी-141 और उसके चार शावक को अपनी मां के साथ अटखेलियां करते देख पर्यटक रोमांचित हुए। क्षेत्र संचालक अंजना सूचिता तिर्की ने बताया कि यह चारों शावक अपनी मां के साथ जंगल में रहने का तरीका सीख रहे हैं। शावक 6 महीने के हो चुके हैं, जो अब जंगल में विचरण करने के गुण अपनी मां से सीख रहे हैं। बाघिन पी-141 व उसके चारों शावक पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बने हुए है। जिनकी अच्छी साइटिंग हो रही है। हालांकि बाघिन पी 141 से पहले बाघिन पी 151 के चार शावकों ने करीब ढाई साल तक पर्यटकों को रोमांचित किया। चारों शावक आए दिन अपनी मां के दिखते थे। अब अपनी बनाकर पीटीआर के जंगल में घूम रहे हैं।

शादी की खुशियां मातम में बदलीं, नदी में नहाने गए दो सगे भाइयों की डूबने से मौत

देवरी कलां (सागर) (नप्र)। केसली थाना क्षेत्र में रविवार के सुबह एक हृदय विदारक घटना घटित होने से शादी की खुशियां मातम में बदल गईं। दरअसल केसली में एक मुस्लिम परिवार में बारात जाने के तैयारी चल रही थी। उसी दौरान नदी में नहाने गए दो सगे भाइयों की डूबने से मौत हो गई। यह दोनों भाई अपनी मौसी के परिवार में हो रही शादी में शामिल होने केसली आए थे। इस घटना से परिवार में मातम पसर गया। पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले में जांच शुरू कर दी है। केसली थाना प्रभारी लोकेश पटेल बताया कि इलाके में रहने वाले गुड्डू खान के परिवार में शादी है। रविवार को सुबह बारात जाने की तैयारी चल रही थी। परिवार के लोग बारात रवानगी की तैयारी में जुटे हुए थे। इसी दौरान कुछ रिश्तेदार नहाने के लिए नदी के घाट पर गए थे। सुनार नदी में नहाने के दौरान बीना निवासी अल्ताफ (19 साल) तथा तय्यब (22 साल) पिता अब्दुल सईद गहरे पानी में चले गए और डूब गए।

कर्म में विश्वास रखते हुए निरंतर जनता की सेवा करने वाले जनप्रतिनिधि सदैव याद रखे जाते हैं : मुख्यमंत्री डॉ. यादव

पूर्व सांसद स्व. फूलचंद वर्मा की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा से वर्चुअली जुड़े

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि कर्म में विश्वास रखते हुए निरंतर जनता की सेवा में लीन रहने वाले जनप्रतिनिधि सदैव याद रखे जाते हैं। निर्वाचन क्षेत्र के साथ संपूर्ण प्रदेश के विकास की चिंता करना एक समर्पित जन-प्रतिनिधि की पहचान होती है।

स्व. फूलचंद वर्मा एक ऐसे ही जनप्रतिनिधि थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने शनिवार की शाम पूर्व सांसद स्व. फूलचंद वर्मा की द्वितीय पुण्यतिथि पर इंदौर में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में मुख्यमंत्री निवास से वर्चुअल रूप से शामिल होकर श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि आज जब मध्यप्रदेश में औद्योगिक निवेश बढ़ रहा है, कृषि विकास दर बेहतर हुई है। कई बंद उद्योग फिर से प्रारंभ होने की स्थिति में आ रहे हैं, तब श्रमिकों के कल्याण से जुड़े स्व. फूलचंद वर्मा याद आते हैं।

उन्होंने भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्य के रूप में सार्वजनिक जीवन प्रारंभ किया और चार दशक से अधिक अवधि तक कार्यकर्ता, विधायक, सांसद के रूप में और इन पदों पर न रहने पर भी नागरिकों के कल्याण के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। वे संविद सरकार में उप मंत्री रहे और पांच बार सांसद रहे। सोनकच्छ विधानसभा क्षेत्र और शाजापुर, देवास संसदीय क्षेत्र के साथ ही उज्जैन संसदीय क्षेत्र से भी निर्वाचित हुए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने स्व. वर्मा का पुण्य स्मरण किया और उनके परिजन से चर्चा भी की। इस अवसर पर विधायक सुश्री ऊषा ठाकुर भी उपस्थित थीं।

परीक्षा विशेष ट्रेन

कोटा-ग्वालियर के बीच चलेंगी 2 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें, प्रदेश के 5 जिलों के छात्रों को राहत

भोपाल (नप्र)। रेल प्रशासन ने परीक्षा के दौरान अतिरिक्त यात्रीभार को ध्यान में रखते हुए गाड़ी संख्या 09801/09802 और 09803/09804 कोटा-ग्वालियर-कोटा परीक्षा विशेष ट्रेनों के संचालन का निर्णय लिया है। ये ट्रेनें मध्य प्रदेश के ग्वालियर, रुठियाई, गुना, अशोकनगर और बीना जिलों से होकर गुजरेंगी। ट्रेन संख्या 09801: कोटा-ग्वालियर (25 नवंबर) यह ट्रेन 25 नवंबर को कोटा स्टेशन से रात्रि 9:25 बजे प्रस्थान करेगी और अगले दिन, रात 12:05 बजे रुठियाइ, रात 12:30 बजे गुना, रात 1:30 बजे अशोकनगर, सुबह 3:40 बजे बीना पहुंचेगी। वहीं मार्ग के अन्य स्टेशनों पर रुकते हुए यह ट्रेन सुबह 9:25 बजे ग्वालियर पहुंचेगी। ट्रेन संख्या 09802: ग्वालियर-कोटा (26 नवंबर), यह ट्रेन 26 नवंबर को ग्वालियर स्टेशन से सुबह 10:25 बजे प्रस्थान करेगी और उसी दिनः शाम 6:00 बजे बीना, शाम 7:45 बजे अशोकनगर, रात 9:05 बजे गुना, रात 9:50 बजे रुठियाई पहुंचेगी। वहीं मार्ग के अन्य स्टेशनों पर रुकते हुए यह ट्रेन अगले दिन रात 2:00 बजे कोटा पहुंचेगी। ट्रेन

संख्या 09803: कोटा-ग्वालियर (27 नवंबर), यह ट्रेन 27 नवंबर को कोटा स्टेशन से रात्रि 9:25 बजे प्रस्थान करेगी और अगले दिनः रात 12:05 बजे रुठियाई रात 12:30 बजे गुना, रात 1:30 बजे अशोकनगर, सुबह 3:40 बजे बीना पहुंचेगी। मार्ग के अन्य स्टेशनों पर रुकते हुए यह ट्रेन सुबह 9:25 बजे ग्वालियर पहुंचेगी। ट्रेन संख्या 09804: ग्वालियर-कोटा (28 नवंबर), यह ट्रेन 28 नवंबर को ग्वालियर स्टेशन से सुबह 10:25 बजे प्रस्थान करेगी और उसी दिनः शाम 6:00 बजे बीना, शाम 7:45 बजे अशोकनगर, रात 9:05 बजे गुना, रात 9:50 बजे रुठियाई पहुंचेगी। मार्ग के अन्य स्टेशनों पर रुकते हुए यह ट्रेन अगले दिन रात 2:00 बजे कोटा पहुंचेगी।

एमपी के 21 जिलों की सड़कें व्हाइट टॉपिंग से बनेंगी

हैवी ट्रैफिक-बारिश में भी नहीं उखड़ेंगी, 109 किमी लंबी 41 सड़कें 4 माह में होगी तैयार

भोपाल (नप्र)। भोपाल में सड़क निर्माण की तकनीक पर दो दिन तक मंथन करने के बाद अब लोक निर्माण विभाग व्हाइट टॉपिंग तकनीक से सड़कें बनाएगा। इसके लिए शुरुआती दौर में प्रदेश के 21 जिलों की 41 सड़कों को चिह्नित किया गया है। इन सड़कों का काम इसी माह शुरू किया जाना है। इसके लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू कराई जा चुकी है। ऐसी सड़कों को चार माह के भीतर कम्प्लीट किया जाएगा। प्रदेश में सड़कों की क्वालिटी खराब होने और साधारण सी बारिश में सड़कें उखड़ने की शिकायतों के बाद अब राज्य सरकार व्हाइट टॉपिंग टेक्नीक अपनाने जा रही है। इस तकनीक से बनाने वाली सड़कों की कुल लंबाई 109.31 किलोमीटर है। योजना को नवंबर के अंत तक शुरू करने की तैयारी है और इसे अगले 4 महीनों में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

शहर	मार्ग
भोपाल	14
इंदौर	3
ग्वालियर	3
बुरहानपुर	2
मंदसौर	2
सागर	2

इन जिलों में बनेगी पायलट प्रोजेक्ट पर व्हाइट टॉपिंग रोड

भोपाल में वल्लभ भवन मार्ग, श्यामला हिल्स स्थित सीएम हाउस मार्ग समेत यहां कि 14 सड़कों को इसके लिए चिह्नित किया है। लोक निर्माण विभाग ने तय किया है कि प्रदेश के आगर मालवा, उमरिया, खंडवा, गुना, छतरपुर, देवास, नर्मदापुरम, नीमच, बैतूल, मुरैना, रतलाम, रायसेन, रीवा, सतना और हरदा में एक-एक मार्ग पर व्हाइट टॉपिंग तकनीक से सड़क बनाई जाएगी।

पूर्व मंत्री सक्सेना के बेटे का नकुलनाथ पर निशाना

अजय बोले- चार दिन बाज नहीं उड़े तो आसमान कबूतरों का नहीं होता

छिंदवाडा (नप्र)। छिंदवाड़ा में पूर्व कैबिनेट मंत्री दीपक सक्सेना के बेटे अजय सक्सेना ने पूर्व सांसद नकुलनाथ और कांग्रेस जिला अध्यक्ष विश्वनाथ ओकटे पर निशाना साधा। उमरहड़ में आयोजित निशुल्क स्वास्थ्य शिविर के दौरान अजय सक्सेना ने ओकटे को चुनौती देते हुए कहा कि उन्हें चुनाव लड़ने की बहुत लालसा है। अजय ने कमलनाथ से निवेदन किया कि वो ओकटे को लोकसभा चुनाव की टिकट दें। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि विवेक बंटी साहू ओकटे को दो लाख वोटों से हराएंगे। अजय सक्सेना ने ओकटे की राजनीति पर भी टिप्पणी करते हुए कहा कि ओकटे को उनके पिता दीपक सक्सेना के राजनीतिक भविष्य की चिंता है। अजय ने ये भी याद दिलाया कि पूर्व सीएम कमलनाथ से पहली मुलाकात उनके पिता ने ही कराई थी, जब वो गुरैया के उप सरपंच थे।

ये किसी का घर नहीं, लाड़ली बहनों का गढ़ है

सक्सेना ने कहा कि चार दिन बाज ना उड़े तो आसमान कबूतर का नहीं हो जाता है। अजय ने कहा कि छिंदवाड़ा अब किसी का घर नहीं रहा, ये लाड़ली बहनों का गढ़ है। उन्होंने नकुलनाथ पर भी निशाना साधते हुए कहा कि नकुलनाथ पांच कार्यकर्ताओं के मकान बता दें तो वो राजनीति छोड़ देंगे। उन्होंने आगे कहा कि नकुलनाथ किसी कांग्रेस कार्यकर्ता को नहीं पहचानते।

मंच पर सांसद भी थे मौजूद

अजय सक्सेना ने ये आरोप उस समय लगाया जब मंच पर संसद विवेक बंटी साहू भी मौजूद थे। इस दौरान वो नकुलनाथ और विश्वनाथ ओकटे पर जमकर हमलावर हुए।

विश्वनाथ ओकटे ने दो दिन पहले ली थी चुटकी

दरअसल कांग्रेस जिला अध्यक्ष विश्वनाथ ओकटे ने 2 दिन पहले दीपक सक्सेना पर चुटकी ली थी। उन्होंने प्रभारी मंत्री की आगमन के दौरान लगे होर्डिंग में उन्हें पूर्व केंद्रीय मंत्री लिखा गया था, जिसके बाद विश्वनाथ ओकटे ने इसे अपमान जनक बताया था। इसी के चलते आज अजय सक्सेना ने ओकटे और नकुल नाथ पर तंज कसा।

कैलाश मकवाना बने एमपी के नए डीजीपी

मुख्यमंत्री के विदेश जाते ही आधी रात को आदेश, 1 दिसंबर को लेंगे चार्ज

भोपाल (नप्र)। 1988 बैच के आईपीएस ऑफिसर कैलाश मकवाना मध्यप्रदेश के नए डीजीपी (पुलिस महानिदेशक) होंगे। सीएम डॉ. मोहन यादव के विदेश यात्रा पर जाने के बाद शनिवार देर रात गृह विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए है। कैलाश मकवाना वर्तमान में मप्र पुलिस हाउसिंग कार्पोरेशन के चेयरमैन हैं। अब वे एमपी के 32वें डीजीपी होंगे। आदेश के मुताबिक मकवाना 1 दिसंबर 2024 को प्रदेश के नए पुलिस मुखिया के रूप में पदभार ग्रहण करेंगे। वे वर्तमान डीजीपी सुधीर सक्सेना की जगह लेंगे। मकवाना दिसंबर 2025 में रिटायर होंगे। बता दें कि वर्तमान डीजीपी सुधीर सक्सेना 30 नवंबर 2024 को रिटायर हो रहे हैं। सुधीर सक्सेना को 4 मार्च 2020 को डीजीपी नियुक्त किया गया था। कैलाश मकवाना का साढ़े

तीन साल के अंदर 7 बार तबादला हुआ था। कमलनाथ सरकार के दौरान ही वे तीन बार इधर से उधर किए गए थे।

सीएम के लौटने के बाद संभाल सकते हैं पदभार-

सीएम डॉ. मोहन यादव 24 नवंबर से 30 नवंबर तक यूके और जर्मनी की यात्रा पर रहेंगे। संभावना जताई जा रही है कि सीएम के विदेश दौरे से लौटने के बाद ही कैलाश मकवाना विधिवत पदभार ग्रहण करें।

मकवाना की गिनती तेज तर्रार अफसरों में- कैलाश मकवाना इस समय मप्र पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन के चेयरमैन है। शिवराज सरकार के कार्यकाल में मकवाना लोकायुक्त के डीजी थे। हालांकि वे छह महीने ही इस पद पर रहे। दरअसल, मकवाना ने लोकायुक्त में डीजी बनते ही भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई में तेजी ला दी थी। उन्होंने ठंडे बस्ते में पड़ीं कई लंबित जांचों की फाइल खोली और जांच शुरू की। उन्होंने अपने एसीआर (गोपनीय चरित्रावली) सुधरवाने के लिए मप्र शासन से 9 महीने पहले अपील की थी। उन्होंने रिप्रेजेंटेशन भेजते हुए सरकार से कहा था कि लोकायुक्त संगठन में डीजी रहने के 6 महीने के दौरान उनकी एसीआर खराब कर दी गई। दुर्भावनापूर्वक खराब की गई एसीआर पर शासन को उचित निर्णय लेना चाहिए। डीजीपी की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू होने के कुछ महीने पहले ही वरिष्ठ सचिवों की कमेटी ने इसे दुरुस्त कर दिया था।

जेसीबी से सब्जी, मिक्सर से मालपुआ बनाए

भिंड के दंदरौआधाम में भंडारे में पहुंचे डेढ़ लाख श्रद्धालु, हुआ समापन

भिंड (नप्र)। भिंड के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल दंदरौआ धाम में चल रहे आठ दिवसीय सिय-पिय मिलन उत्सव का आज (रविवार) समापन हो गया। इस अवसर पर आयोजित विशाल भंडारे में लगभग डेढ़ से दो लाख श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावना है। श्रद्धालुओं के लिए महाप्रसादी का वितरण सुबह 10 बजे से शुरू हो गया। इस आयोजन में 400 लोगों की टीम दिन-रात जुटी हुई है। इस भव्य आयोजन के लिए सौ क्विंटल आलू से सब्जी और 100 क्विंटल दूध से खीर तैयार की जा रही थी। सब्जी और खीर तैयार करने के लिए बड़ी चम्मचों के स्थान पर जेसीबी मशीन और मिक्सर मशीन का उपयोग किया जा रहा है। महाप्रसादी तैयार करने में हलवाइयों और उनकी टीम ने विशेष योगदान दिया है, जिसमें 100 महिला हलवाई भी शामिल थे। भंडारे सामग्री के बारे में मंदिर प्रवक्ता जलज त्रिपाठी ने बताया कि महाप्रसादी के लिए उपयोग की जा रही सामग्री का विशाल स्तर पर प्रबंध किया गया था। खीर- 100 क्विंटल दूध और 100 क्विंटल शक्कर मालपुआ- 80 क्विंटल आटा और 20 क्विंटल गुड़ पूड़ी- 60 क्विंटल आटा, बूंदी- 40 क्विंटल बेसन और 100 क्विंटल शक्कर, देशी घी- 450 टीन प्रतिदिन, 30 भट्टियों पर तैयार हो रहा भंडारा, श्रद्धालुओं के लिए भोजन तैयार करने में 30 भट्टियां लगातार काम कर रही हैं।

मंदिर की जमीन कैसे बिकी 60 दिन में बताएं कलेक्टर

नरसिंहपुर के 'राम-जानकी मंदिर' ट्रस्ट मामले का निराकरण कर सौंपना होगी रिपोर्ट

जबलपुर (नप्र)। नरसिंहपुर जिले के राम जानकी ट्रस्ट मंदिर कंदेली की जमीन को बेचने के मामले में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने नरसिंहपुर कलेक्टर को 60 दिन में निराकरण के निर्देश दिए हैं। ह्यजस्टिस एमएस भट्टी की एकल पीठ ने कलेक्टर से यह भी कहा है कि वह रिपोर्ट कोर्ट को सौंपे। जबलपुर निवासी यदुवंश कुमार त्रिवेदी की ओर से अधिवक्ता अजय रायजादा ने हाई कोर्ट को बताया कि याचिकाकर्ता के पूर्वजों ने ट्रस्ट बनाकर राम जानकी मंदिर का प्रबंधन और व्यवस्थापन का कार्य शुरू किया था। याचिकाकर्ता पांच भाई-बहन हैं, जिनमें से यदुवंश कुमार जबलपुर में रहते हैं। वर्ष 2009 में व्यवस्था पत्र बनवाकर छोटे भाई सुरेंद्र कुमार त्रिवेदी को देखने का दायित्व सौंप दिया था। याचिकाकर्ता ने बताया कि सुरेंद्र त्रिवेदी ने बिना अधिकार नर्मदा डेवलपर से सांठ-गांठ कर मंदिर की संपत्ति बेच दी और कलेक्टर की अनुमति से वहां निर्माण भी शुरू कर दिया। मंदिर की संपत्ति में सभी भाई-बहन का बराबर से अधिकार हैं। याचिकाकर्ता ने इस मामले में कलेक्टर से संपत्ति का दुरुपयोग रोकने मांग की थी लेकिन जब सुनवाई नहीं हुई तो याचिका दायर की गई।

युवा शक्ति मिशन से सशक्त होगा युवा नेतृत्व, लिखेगा मध्यप्रदेश के स्वर्णिम विकास की इबारत : मुख्यमंत्री डॉ. यादव

भोपाल(नप्र)। मुख्यमंत्री के रूप में डॉ. मोहन यादव के कार्यकाल का स्वर्णिम एक वर्ष 13 दिसंबर 2024 को पूरा हो जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव के सशक्त एवं विजनरी नेतृत्व में सरकार का फोकस पूरी तरह प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के मंत्र ज्ञान पर ध्यान (ग़रीब, युवा, अन्नदाता और नारी) के सशक्तिकरण पर रहा है। आने वाला नव वर्ष 2025 पर प्रदेश सरकार युवाओं के लिए सशक्तिकरण की सौगात लेकर आ रही है। प्रदेश के युवाओं में नेतृत्व क्षमता विकसित करने और उनके कौशल उन्नयन के लिये 'युवा शक्ति मिशन' का शुभारंभ नववर्ष 1 जनवरी, 2025 से किया जायेगा। इस मिशन का उद्देश्य मध्यप्रदेश के विकास में युवाओं की व्यापक क्षमताओं का उपयोग करना है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का मानना है कि सशक्त युवा नेतृत्व से ही मध्यप्रदेश के विकास का स्वर्णिम अध्याय रचा जा सकेगा।

मिशन से मिटेगी शिक्षा, कौशल और रोजगार के बीच की खाई

युवा शक्ति मिशन की परिकल्पना 'युवाओं' में शिक्षा, कौशल विकास, और सामुदायिक सेवा जैसे प्रमुख नेतृत्व गुणों को विकसित कर उन्हें सक्षम बनाना है, जिससे वे प्रदेश के सामाजिक-आर्थिक विकास में सक्रिय भूमिका निभा सकें। 'युवा शक्ति मिशन' के केंद्र में युवा है और वह राष्ट्र की प्रगति के केंद्र में भी वही है। इसलिए युवाओं को नेतृत्व सक्षम बनाने के लिये आवश्यक संसाधन और अवसर प्रदान करना ही इस मिशन का मुख्य उद्देश्य है। साथ ही प्रदेश के युवाओं को सुशिक्षित करना ही नहीं, बल्कि व्यावसायिक रूप से कुशल बनाना है। इस मिशन में युवाओं में व्यावसायिक कौशल को आधुनिक तकनीक का प्रभावी उपयोग करते हुए इस तरह उन्नत बनाया जाएगा जिससे वे न सिर्फ अच्छे वेतन वाले रोज़गार प्राप्त कर सकें, अपितु सफल उद्यमी बन राज्य की अर्थव्यवस्था के विकास में भी अपना योगदान दे सकें। मिशन के अंतर्गत सरकार ने उद्योगों और व्यावसायिक संस्थानों के साथ सहयोग करते हुए मध्यप्रदेश के युवाओं के लिए रोज़गार के विभिन्न रास्ते बनाए हैं। साथ ही युवाओं में उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए कौशल प्रशिक्षण, वित्तीय सहायता और मार्गदर्शन देकर उन्हें स्व-रोज़गार के लिए भी प्रोत्साहित किया जाएगा। 'युवा शक्ति मिशन' के परिणाम स्वरूप प्रदेश के युवा नौकरी की तलाश में जुटी भीड़ में शामिल होने के स्थान पर नौकरी देने वाले उद्यमी बनेंगे।

मिशन से युवा शक्ति में विकसित होगी सक्षम नेतृत्व क्षमता

मुख्यमंत्री डॉ.यादव के रणनीतिक नेतृत्व में 'युवा शक्ति मिशन' प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के युवा सशक्तिकरण के विजन को कार्यान्वित करने में जुटा हुआ है। मिशन के क्रियान्वयन का प्रमुख पहलू युवाओं में नेतृत्व-विकास है। इसके लिए युवाओं को शासन और सामुदायिक सेवा में शामिल करके उनमें सक्षम तथा कुशल नेतृत्व के गुण विकसित किये जाएंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव का मानना है कि स्थानीय विकास परियोजनाओं में युवाओं की भागीदारी उनके कौशल को निखारती है, साथ ही उन्हें जिम्मेदार नागरिक भी बनाती है।

तकनीक के प्रभावी उपयोग से होगा युवा सशक्तिकरण

'युवा शक्ति मिशन' के सफल क्रियान्वयन में आधुनिक तकनीक की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। कौशल विकास के पाठ्यक्रम युवाओं को सहजता से उपलब्ध हो सकें और वह उन्हें आसानी से समझ सकें, इसके लिए सरकार ने ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म लॉन्च किए हैं। इसका लाभ यह भी है कि ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के युवाओं को इसकी सुविधाएं समान रूप से सुलभ होंगी। मिशन की सफलता के लिए सरकार ने सोशल-मीडिया के माध्यमों का भी प्रभावी उपयोग करने की रणनीत बनाई है, जिससे युवाओं को मिशन से संबंधित जानकारी आसानी से उपलब्ध कराई जा सके। इससे युवाओं में मिशन के प्रति जागरूकता बढ़ेगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव के विजन से विकसित युवा मिशन प्रधानमंत्री मोदी के 'GYAN पर ध्यान' के मंत्र में शामिल युवा शक्ति के सशक्तिकरण का प्रभावी तंत्र बन कर उभरेगा।